BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

Admission Open

For The Academic Session 2026-27
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS
APPLY NOW

Vision -
To prepare the children
empowered
with Indian ethical
and spiritual values
to face the global challenges.

Mission-
To produce
enriched and enlightened
human resource
for the country.

Pillars -
SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal-
ब्रह्म तत् लक्ष्यम्

Streams:
Science,
Commerce &
Humanities

Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683
www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao,
Haldwani (Nainital), Uttarakhand

blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्मुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। (मुण्डक उपनिषद)

पोस्टल रजि.नं.यू-नैनीताल-356-2021-2023

मार्च 2026

उत्तरांचल दीप पत्रिका

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

रेलवे की भूमि से हटेगा अतिक्रमण

₹:40

खामेनेई का खात्मा

28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत उसके 40 टॉप कमांडर मारे जा गए है, साथ ही परिवार के कई लोगों की भी मौत हुई है, इनमें एक जहरा मोहम्मदी सिर्फ 14 महीने की थी वह अयातुल्ला अली खामेनेई की ग्रैंड डॉटर (नातिन) थी।

ई-मेल: uttranchaldeepatrika@gmail.com
Web: uttaranchaldeep.com

मासिक
उत्तरांचल दीप पत्रिका
वर्ष:8, अंक 11, मार्च 2026

संस्थापक संपादक
स्व.वेदप्रकाश गुप्ता
प्रधान संपादक
साकेत अग्रवाल
संपादक
श्रीमती आदेश अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी संपादक
केके चौहान
मुख्य उप संपादक
उदयभान सिंह
मार्केटिंग हेड
तारु तिवारी
प्रबंधक
दीपक तिवारी
वरिष्ठ संवाददाता
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो
दिल्ली : शालिनी चौहान
लखनऊ : पारस अमरोही
रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित
नैनीताल : अफजल फौजी
अल्मोड़ा : कमल कपूर
पिथौरागढ़ : ललित जोशी
बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट
चंपावत : मनोज राय
बरेली : अनुज सक्सेना
मुरादाबाद : आर्शेद्र कुमार अग्रवाल
डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल
किच्छा : राजकुमार राज
रामनगर : एचसी भट्ट
थत्यूड़ : मुकेश रावत
रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता
बाजपुर : इंद्रजीत सिंह
ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय
हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।
आएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440
पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीतील-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com
uttranchaldeepatrika@gmail.com
+91 8881788066 @uttranchaldeep

अंदर

'राइट टू रिकॉल' सिस्टम विश्व के कई देशों में है जिसमें जनप्रतिनिधियों का काम संतोषजनक न होने पर मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं, 'राइट टू रिकॉल' वोटर्स के लिए एक इंश्योरेंस सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसमें उन्हें यह सुरक्षा मिलेगी कि यदि उनके प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद वादा खिलाफी करते हैं तो वोटर्स बहुमत से उनका मैंडेट रद्द कर सकते हैं।

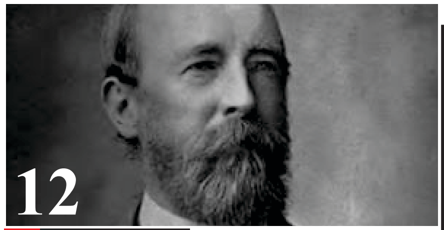

सियासत
अंग्रेजों की मुखबिर रही कांग्रेस?
महान क्रांतिकारी स्व. लाला लाजपतराय ने यंग इंडिया में छपे अपने एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी...

उत्तराखंड
धरोहरें पर संकट
पुरातत्व विभाग के संरक्षण वाले अल्मोड़ा जिले में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर के शिखर का हिस्सा टूट गया है ...

उत्तराखंड
खतरे में देवदार
हिमालय की वादियों में पाए जाने वाला देवदार का विशाल वृक्ष धार्मिक आस्था से जुड़ा है ...

विवाद

अविमुक्तेश्वरानंद व योगी में ठनी
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जगदगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष पांडेय ने जब से बटुकों के यौन शोषण का ...

साकेत अग्रवाल

लोकतंत्र का बदला परिदृश्य

भारत के लोकतंत्र में एक बुनियादी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये बात कई बदलावों से जाहिर होती है, जिसमें चुनावी मुकाबले के मिजाज में आया संस्थागत बदलाव, मध्यम वर्ग की तादाद में कई गुना का इजाफा, सोशल मीडिया का बढ़ता दायरा और समाज के पुराने ढर्रों के पतन जैसी बातें शामिल हैं। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक और भौगोलिक विस्तार ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल डाला है। जिसका नतीजा ये आया कि कांग्रेस और हाशिए पर चली गई। वाम मोर्चा तो लगभग खत्म सा हो गया है और क्षेत्रीय दलों की ताकत लगातार कम होती जा रही है। जबकि भाजपा ने चारों दिशाओं में अपना व्यापक और मजबूत विस्तार किया है। इससे मतदाताओं के उन समूहों में खासा हेर-फेर देखा जा रहा है, जिनका इस्तेमाल पहले सामाजिक दरारें बढ़ाकर वोट बैंक के रूप में किया जाता था। इसी तरह, पिछले एक दशक में राज्य स्तर पर विपक्ष की चुनावी राजनीतिक कमजोर हुई है। यह बदलाव अभी भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सहित बाकी क्षेत्रीय दलों को शायद नजर नहीं आ रहा। 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, पुंडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव होने हैं जबकि 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के साथ गोवा में चुनाव होने हैं। भाजपा का प्रयास है कि 2026 के चुनावों में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की बिदाई की जाए और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में हैट्रिक लगाई जाए। असम में वापसी और केरलम के साथ तमिलनाडु में प्रदर्शन बेहतर किया जाए। इसके लिए भाजपा ने आरएसएस के साथ मिलकर चुनावी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा संगठनात्मक स्तर पर व्यापक और आक्रामक रणनीति अपनाना चाहती है। भाजपा ने पहली बार मंडल स्तर तक बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है। इसके तहत हर प्रदेश के मंडलों में कार्यकर्ताओं को 7 प्रमुख विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान' के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। मंडल स्तर के प्रशिक्षण में बूथ प्रबंधन, संगठन की कार्य पद्धति, कार्य विस्तार, वैचारिक अधिष्ठान, संवाद कौशल और चुनावी रणनीति जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। विशेष बात यह है कि इस प्रशिक्षण में एक रात्रि प्रवास भी रखा गया है, ताकि कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय और टीम भावना विकसित हो सके।

भाजपा की रणनीति सिर्फ मंडल स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि जिला स्तर पर 10 से अधिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें दो रात्रि प्रवास शामिल होगा। वहीं प्रदेश स्तर पर इससे भी विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे, जिनमें तीन रात्रि प्रवास का प्रावधान किया गया है। पार्टी का उद्देश्य स्पष्ट है कि हर बूथ पर संगठन को मजबूत किया जाए और प्रत्येक मतदाता तक सीधा संपर्क स्थापित हो। भाजपा ने उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी योजना बनाई है जो अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए हैं। ऐसे सभी नेताओं के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। जिनमें उन्हें संगठन की विचारधारा, कार्यसंस्कृति और चुनावी रणनीति से परिचित कराया जाएगा। पार्टी का मानना है कि यदि नए कार्यकर्ता संगठनात्मक ढांचे को अच्छी तरह समझेंगे, तो वे चुनाव में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। लेकिन इसके विपरीत पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों में अभी भाजपा, विरोधियों में सन्नाटा है। कांग्रेस का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये तो ऐसा दल बन गया है जिसे न हार की चिंता होती है और न ही जीत की खास खुशी। तुक्का लग गया तो जीत गए वरना हारने की तो आदत हो गई है। जिन्हें परिवार से विरासत में राजनीति मिली है वो नेता जमीन पर मेहनत नहीं कर पाते। ऐसे नेता सोशल मीडिया और मीडिया में बयान देकर ही चुनाव जीतने का दावा करते हैं। पहले यूजीसी को लेकर विपक्षी दलों ने सवर्ण समाज को भड़काने की कोशिश की, अब अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर ब्राह्मण समाज को भड़काने और अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जी जान से सनातन-सनातन खेल रहे हैं। भाजपा को सनातन विरोधी, सवर्ण विरोधी और ब्राह्मण विरोधी साबित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो असल काम चुनाव जीतने के लिए किया जाना चाहिए उससे विरोधी दल अभी तो दूरी ही बनाए हुए हैं। जबकि भाजपा पहले से ही ग्राउंड पर काम कर रही है। भाजपा एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे राज्य के चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। जबकि जिन्हें विरासत में राजनीति मिली है वो चुनाव होते ही छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं और फिर चुनाव से चंद महीने पहले सड़क पर नजर आते हैं। राहुल गांधी तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल तथा इंडिया गठबंधन के साथी भी मानते हैं कि राहुल गांधी नाम राजनीति मे लीडरशिप का नहीं, बल्कि नासमझी, कन्फ्यूजन और गैरजिम्मेदारी का निशान बन गया है। देश को दिशा देने वाला लीडर बनने के लिए जरूरी तीन चीजे, साफ सोच, सोच का अनुशासन और देश की समझ की कमी राहुल की राजनीति में साफ झलकती है। लीडरशिप का मतलब इमोशनल बयान देना नहीं, बल्कि शब्दों के नतीजों को पहचानना है। हालांकि राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिनसे भारत की ही नहीं बल्कि कांग्रेस की भी इमेज खराब होती है। चाहे देश में हो या विदेश में। यह गलती एक-दो बार हो सकती है, लेकिन अगर यह लगातार हो, तो यह नासमझी नहीं, बल्कि नासमझी की लत है। वो एक तरफ मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं लेकिन दूसरी ओर समाज को जाति, वर्ग, धर्म और इलाके में बांटते हैं। अगर एकता की बात करने वाला नेता असल में बांटने की राजनीति कर रहा है, तो इसे पाखंड ही कहा जाना चाहिए। यही देश के लोकतंत्र में बुनियादी परिवर्तन देखा जा रहा है।

न्यायपालिका के खिलाफ साजिश

उत्तरांचल दीप डेस्क

देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा विवाद उस समय खड़ा हो गया जब आठवीं कक्षा की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों के रूप में भ्रष्टाचार, लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या और न्यायाधीशों की कमी का उल्लेख किया गया। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताते हुए स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, 'मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।' उन्होंने कहा 'संस्था के प्रमुख के रूप में मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और संज्ञान लिया है। हालांकि एक अंग्रेजी अखबार में एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से संबंधित चेप्टर पर स्टोरी छपी तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने इस विषय को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाया। उनका कहना था कि जब देश की जनता का इस संस्था पर सबसे अधिक भरोसा है, तब स्कूली बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाना आपत्तिजनक है। उनका यह भी तर्क था कि पाठ्यपुस्तक में राजनीति, नौकरशाही या कारोबार में भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं है। केवल न्यायपालिका को निशाना बनाया गया है। किताब में विवादित अध्याय 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' शीर्षक से चेप्टर है। पहले के संस्करणों में जहां न्यायालयों की संरचना, कार्यप्रणाली और न्याय तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित था, वहीं नए संस्करण में व्यवस्था की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' शीर्षक खंड में कहा गया है कि विभिन्न स्तरों पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ सकता है और गरीब तथा वंचित वर्गों के लिए इससे न्याय तक पहुंच और कठिन हो सकती है। पुस्तक में यह भी उल्लेख है कि राज्य और केंद्र स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाने तथा तकनीक के उपयोग से सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। पुस्तक में लंबित मुकदमों के आंकड़े भी दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में लगभग 81 हजार मामले लंबित हैं, उच्च न्यायालयों में लगभग 62.40 लाख और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में करीब 4.70 करोड़ मामले लंबित हैं। ये आंकड़े न्याय प्रणाली पर बढ़ते बोझ को दर्शाते हैं। पुस्तक में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के जरिए प्राप्त शिकायतों का भी उल्लेख है जिसमें बताया गया है कि 2017 से 2021 के बीच 1600 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। नई पुस्तक के 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' खंड में कहा गया है कि न्यायाधीश एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो न केवल अदालत में उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है बल्कि अदालत के बाहर उनके आचरण को भी नियंत्रित करती है। इस अध्याय में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के कथन का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाएं जन विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, किंतु त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई से इस विश्वास को पुनः स्थापित किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है, न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती।

किताब में 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' शीर्षक से अध्याय है, पहले के संस्करणों में जहां न्यायालयों की संरचना, कार्यप्रणाली और न्याय तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित था, वहीं नए संस्करण में व्यवस्था की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' शीर्षक खंड में कहा गया है कि विभिन्न स्तरों पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि उसे देश भर से फोन आ रहे हैं और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के चयनात्मक उल्लेख को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। पीठ ने संकेत दिया कि इस विषय पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। देखा जाए तो यह विवाद कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। सवाल उठता है कि क्या छात्रों को लोकतांत्रिक संस्थाओं की चुनौतियों से अवगत कराना पारदर्शिता का हिस्सा है या इससे संस्थाओं की छवि प्रभावित होती है? साथ ही इससे न्यायपालिका की स्वायत्तता और आलोचना की सीमा पर भी प्रश्न खड़ा हुआ है। वैसे यह घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र में संस्थाओं की मजबूती केवल उनको आलोचना से बचाने में नहीं, बल्कि चुनौतियों को स्वीकार कर सुधार की दिशा में आगे बढ़ने में निहित है। आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई और सरकार की प्रतिक्रिया इस बहस को नई दिशा दे सकती है। हालांकि इस तरह की बातों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करना उचित नहीं कहा जा सकता। बच्चों को प्रेरणादायक विषय पढ़ाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद सरकार ने पलटी मारी और किताब के संशोधित अध्याय हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार के उल्लेख को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार का कहना है कि यह हिस्सा पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के जुलाई 2025 के बयान पर आधारित था, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में कुछ मामलों के कारण जनता के भरोसे पर असर पड़ने की बात कही थी। सरकार का कहना है कि इस तरह का संदर्भ पाठ्यपुस्तक में देना उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

सुर्खियां

सर संघचाल

सामाजिक शक्ति है संघ

क मोहन भागवत ने देहरादून के एक कार्यक्रम में कहा कि संघ को बाहर से देखकर उसकी वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता। पथ संचलन देखकर कुछ लोग उसे अर्धसैनिक संगठन समझ लेते हैं, राष्ट्रप्रेम के गीत सुनकर संगीत मंडली मान लेते हैं, सेवा कार्य देखकर सेवा क्षेत्र का संगठन समझ लेते हैं, किंतु संघ इन सीमाओं से परे एक व्यापक सामाजिक शक्ति है। जैसे चीनी की मिठास को जानने के लिए उसे चखना पड़ता है, वैसे ही संघ को समझने के लिए संघ के कार्य में आना आवश्यक है। संघ की किसी संगठन से प्रतिस्पर्धा नहीं है। राष्ट्र सशक्त होगा तो राष्ट्रवासी भी सशक्त होंगे। यदि राष्ट्र दुर्बल होगा तो व्यक्ति अपने ही देश में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है, क्योंकि सशक्त व्यक्ति से ही सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। संघ संस्थापक डॉ केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन का उल्लेख करते हुए भागवत ने कहा कि वे जन्मजात देशभक्त और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बाल्यकाल में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिवस पर विद्यालय में वितरित मिठाई लेने से उन्होंने यह कहकर इंकार कर दिया था कि वे अपने देश पर शासन करने वाले के उत्सव में भाग नहीं लेंगे। वे अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य रहे तथा वंदेमातरम गान के कारण अंग्रेजों द्वारा दायर देशद्रोह का मुकदमा भी झेला। उनका संकल्प था कि भारत बार-बार पराधीन न हो, इसी उद्देश्य से संघ की स्थापना की गई। भागवत ने कहा कि लम्बी ऐतिहासिक यात्रा के बाद आज विश्व भारत को पुनः नेतृत्वकारी भूमिका में देखने की आशा कर रहा है। उन्होंने आमजन का संघ की गतिविधियों से जुड़कर समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव का मूल कारण व्यवस्था नहीं, बल्कि मन है। अंधकार को पीटने से नहीं, प्रकाश जलाने से समाप्त किया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन से ही भेदभाव मिटेगा। संघ में कई स्वयंसेवक दशकों तक कार्य करते हैं, पर पहचान की अपेक्षा नहीं रखते क्योंकि उनके लिए कार्य ही प्रधान है। तकनीक साधन है, साध्य नहीं। उसका उपयोग संयम और अनुशासन से होना चाहिए। परिवार में आत्मीयता और समय देना आवश्यक है, तकनीक के लिए मनुष्य की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। उनका कहना है कि जो जोड़ने का कार्य करे वही हिंदू है। मातृभूमि के प्रति भक्ति अनिवार्य है। विश्व सत्य से अधिक शक्ति को समझता है, इसलिए शक्ति अर्जित करना आवश्यक है, किंतु उसका उपयोग मर्यादित होना चाहिए। भागवत ने कहा कि महिलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। देश संचालन में उनकी भागीदारी 33 प्रतिशत ही नहीं, 50 प्रतिशत तक होनी चाहिए। उत्तराखंड की नदियों और पर्यावरण संरक्षण पर उन्होंने समन्वित नीति और स्थानीय सहभागिता पर बल दिया। शिक्षा में पाठ्यक्रम से अधिक शिक्षकों के संस्कारों को महत्वपूर्ण बताया। आरक्षण, वर्गीकरण और समान नागरिक संहिता जैसे विषयों पर उन्होंने कहा कि समाज को प्रमाणिकता और सद्भाव से कार्य करना चाहिए। विभाजन की मानसिकता से बाहर आना होगा। संघ हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता, बल्कि व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज उत्थान का कार्य करता है। ●

शराब घोटाले से केजरीवाल बरी

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों पर मुकदमा चलाने से इंकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने माना कि सीबीआई की चार्जशीट में अभियोग चलाने के लिए पर्याप्त सबूतों का अभाव है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई को बिना किसी सबूत के उन्हें फंसाने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में अंदरूनी बातें थीं जो कथित साजिश की थ्योरी की जड़ पर चोट करती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया। यह बात कानून के नियमों के खिलाफ है, खासकर जब यह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो जो किसी संवैधानिक पद पर हो। जज ने कहा कि बिना किसी बुनियादी सबूत या बयान के केजरीवाल को कथित साजिश में शामिल करने का आरोप सही नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की हजारों पन्नों की चार्जशीट में ऐसी बातें थीं जो किसी भी गवाह के बयान को सपोर्ट नहीं करतीं। जज ने यह भी कहा कि चार्जशीट में गुमराह करने वाली बातें थीं। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए जज ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो उन्हें पहले आरोपी के तौर पर क्यों फंसाया गया। सिसोदिया पर शराब पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने का आरोप था, कोर्ट ने कहा कि उनकी संलिप्तता दिखाने वाला कोई सबूत नहीं है और न ही कोई रिकवरी हुई थी? सुनवाई के दौरान, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा, कभी-कभी जब आप बहुत सारी फाइलें पढ़ते हैं, तो फाइल आपसे बात करने लगती है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा, कि मैं पहले दिन से ही कबूलनामा मांग रहा हूं, लेकिन चार्जशीट के साथ यह नहीं दिया गया। इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में दी गई थी। स्पेशल जज ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मुझे अभी तक कबूलनामे की कॉपी भी नहीं दी गई है। मैं सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं। ●

पीएचडी स्टूडेंट्स का एडमिशन रद्द

मुंबई यूनिवर्सिटी ने फरवरी में 644 पीएचडी स्टूडेंट्स का एडमिशन रद्द कर दिया है। ये सभी स्टूडेंट्स तय समय सीमा में अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाए थे। इनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे थे, जो 10-10 साल से पीएचडी पूरी नहीं कर पा रहे थे। संस्थान का कहना है कि यह एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। बल्कि 6 महीने की चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद यूजीसी नियम के तहत यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन रद्द किए गए हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी ने सितंबर 2025 में लंबे समय से पीएचडी पूरी नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स का डेटा निकालना शुरू किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के तहत फरवरी 2026 तक अधिकतम समय सीमा में पीएचडी पूरी नहीं करने पर 644 एडमिशन रद्द कर दिए। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि व्यक्तिगत मामलों की समीक्षा के बाद और नियमों का उल्लंघन पाने जाने पर यह प्रक्रिया शुरू हुई। इतनी बड़ी संख्या में पीएचडी रजिस्ट्रेशन रद्द होने का यह पहला मामला है। अधिकारियों का कहना है कि इससे नए स्कॉलर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सीटें ब्लॉक हो रही थीं और पर्यवेक्षकों को नए स्टूडेंट्स को एडमिशन देने में दिक्कत हो रही थी, जिससे डॉक्टरेट एडमिशन में भी अड़चन आ गई। यूजीसी नियम के अनुसार, एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स को कम से कम 3 साल और अधिकतम 6 साल में पीएचडी पूरी करनी चाहिए। इसमें कोर्स वर्क भी शामिल होता है। हालांकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अध्यादेश के अनुसार दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त 2 साल मिल सकते हैं। बशर्ते पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश की अवधि से 8 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला और दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) को 2 साल की और छूट मिल सकती है। इन मामलों में पीएचडी पूरी करने का अधिकतम समय 10 साल तक हो सकता है। पीएचडी पूरी करने के लिए 10 साल से अधिक समय नहीं दिया जा सकता है। हालांकि महिला पीएचडी स्कॉलर्स को कोर्स पूरा करने की अवधि में 240 दिनों तक के लिए मैटरनिटी लीव या बच्चे की देखभाल की छुट्टी मिल सकती है। ●

हवाई यात्रियों को बड़ी राहत

डीजीसीए से हवाई यात्रियों को एक बड़ी राहत मिली है। डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने नए रिफंड नियम जारी किए हैं, जिनके अनुसार टिकट कैंसल या बदलने पर 48 घंटे तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। डीजीसीए के मुताबिक, टिकट बुक करने के 48 घंटों के अंदर यात्री टिकट कैंसल या टिकट में बदलाव करा सकते हैं और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा टिकट बुकिंग करते समय नाम में हुई गलती को सुधारने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह गलती 24 घंटों के अंदर बता दी जाती है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदा गया है, तो नाम सुधारने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से टिकट खरीदने पर, रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी, क्योंकि एजेंट उनके अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एयरलाइंस यह पक्का करेंगी कि रिफंड प्रोसेस 14 वर्किंग डेज के अंदर पूरा हो जाए। इसके अलावा पैसेंजर को होने वाली मेडिकल इमरजेंसी की वजह से टिकट कैंसल करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। संशोधित नियमों में मेडिकल इमरजेंसी के कारण रद्द होने के संबंध में भी स्पष्टता दी गई है। अगर यात्रा अवधि के दौरान यात्री या उसी पीएनआर में लिस्टेड फैमिली के किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो एयरलाइन या तो पूरा पैसा वापसी की पेशकश कर सकती है या भविष्य की यात्रा के लिए क्रेडिट जारी कर सकती है। अन्य मेडिकल मामलों में एयरलाइन द्वारा नियुक्त या डीजीसीए द्वारा सूचीबद्ध एयरोस्पेस मेडिसिन विशेषज्ञ द्वारा फिटनेस मूल्यांकन के बाद धनवापसी की प्रक्रिया की जाएगी। रिफंड में देरी से संबंधित बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर ये बदलाव किए गए हैं। दिसंबर 2025 में इंडिगो से जुड़ी उड़ान व्यवधानों के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को लंबित रिफंड दावों को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश दिया है। डीजीसीए के आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2025 में ही अनुसूचित एयरलाइनों को यात्रियों से संबंधित 29,212 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 7.5 प्रतिशत शिकायतें रिफंड से संबंधित थीं। ●

खामेनेई का खात्मा

28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत उसके 40 टॉप कमांडर मारे जा गए है, साथ ही परिवार के कई लोगों की भी मौत हुई है, इनमें एक जहरा मोहम्मदी सिर्फ 14 महीने की थी वह अयातुल्ला अली खामेनेई की ग्रैंड डॉटर (नातिन) थी।

केके चौहान

दुनिया के किसी भी कोने में यदि युद्ध की आग सुलगती है तो वह यह नहीं देखती कि सामने कौन है? जंग न चेहरे पहचानती है और न ही रिश्तों की सीमा। युद्ध की सबसे डरावनी तस्वीर तब सामने आती है, जब बेगुनाह और मासूम उसकी भेंट चढ़ते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत उसके 40 टॉप कमांडर मारे जा चुके है। परिवार के कई लोगों की भी मौत हुई है। इनमें एक जहरा मोहम्मदी सिर्फ 14 महीने की थी। जहरा मोहम्मदी अयातुल्ला अली खामेनेई की ग्रैंड डॉटर (नातिन) थी। अमेरिका-इजरायल के हमले में जहरा के साथ उसके माता-पिता की मौत की भी खबर है। तेहरान में एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 80 से ज्यादा मासूम छात्र मारे गए। इस युद्ध में सभी तरफ के नागरिक और सैन्यबल की मौत हो रही है। ये हजारों का आकंड़ा कहां जाकर रुकेगा, कहा नहीं जा सकता। ये सारी तबाही परमाणु हथियार बनाने की सनक में हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई परमाणु शक्ति बनना चाहते थे, लेकिन इजराइल और अमेरिका किसी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहते हैं। इजराइल मानता है कि ईरान यदि परमाणु शक्ति बना तो वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अयातुल्ला अली खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता बने, जिन्हें क्रूर और दमनकारी शासक, राजनीतिक विरोधियों के दमन, मानवाधिकार हनन और सैन्य शक्ति के केंद्रीकरण के कारण एक दमनकारी तानाशाह माना जाता था। उन्होंने 1999, 2009, 2019 और 2022-23 के विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया था। फरवरी 2026 तक सत्ता में रहकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) की मदद से ईरान पर शासन किया। अयातुल्ला अली खामेनेई ने अयातुल्ला खुमैनी के बाद 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभाला और ईरान के धार्मिक और राजनीतिक मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण रखा। उन्होंने उदारवादियों, कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और राजतंत्रवादियों पर कड़ी कार्रवाई की और विरोधियों को 'ईशनिंदा' के आरोप में सलाखों के पीछे डाल दिया या फिर फांसी दे दी। फांसी भी सरेआम दी ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत न कर सके। उनके कार्यकाल के दौरान,

विनाशक युद्ध में तबाही परमाणु हथियार बनाने की सनक में हो रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई परमाणु शक्ति बनना चाहते थे, लेकिन इजराइल और अमेरिका किसी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहते हैं, इजराइल मानता है कि ईरान यदि परमाणु शक्ति बना तो वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा।

विशेषकर 2009 (ग्रीन मूवमेंट) और 2022-23 (महसा अमिनी विरोध) में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए जिन्हें क्रूर शासक खामेनेई ने बेरहमी से कुचल दिया। इसी साल जनवरी में खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों का निर्दयतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। सुरक्षाबलों के साथ झड़पों में 2,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया। जबकि 10,000 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए थे। हिंसक प्रदर्शनों के बीच 26 साल के युवा प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुना दी गई थी। हालांकि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद उसे फांसी नहीं दी गई। खामेनेई अपने खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने के लिए जाने जाते रहे हैं। उन्होंने आईआरजीसी की ताकत अपने फायदे के लिए बढ़ाई, जिससे ईरान में सेना का वर्चस्व रहे। उन्हें व्यापक रूप से एक ऐसे शासक के रूप में देखा जाता रहा था जिसने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मानवाधिकारों को कुचला और ईरान को एक कट्टरपंथी दिशा में धकेल दिया।

आतंकी संगठनों का फाइनेंसर है ईरान?

अयातुल्ला अली खामेनेई ने लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और यमन के हूती जैसे आतंकी संगठनों का नेटवर्क विकसित किया, जिसे 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' कहा जाता है। अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के कुद्स फोर्स का इस्तेमाल किया, जो सीधे उनके अधीन थी, ताकि विदेशों में आतंकवादी अभियानों को अंजाम दिया जा सके और अस्थिरता फैलाई जा सके। खामेनेई द्वारा समर्थित इन आतंकी संगठनों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले किए, जिसमें 1983 के बेरूत बम विस्फोट और 1994 में अर्जेंटीना में एएमआईए सेंटर पर हमला शामिल है। सीरिया में बशर अल-असद शासन और विभिन्न मिलिशिया का समर्थन किया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। अक्टूबर 2023 के नरसंहार से पहले और उसके दौरान खामेनेई ने हमास का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि उसे इजराइल से लड़ने के लिए धन, हथियारों के साथ ट्रेनिंग भी दिलाई। हालांकि खामेनेई ने इन सभी आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने दावा किया था कि ईरान खुद आतंकवाद का मुकाबला करता है और अमेरिका ही वास्तविक आतंकवादी देश है जो क्षेत्र में आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों का समर्थक है। उन्होंने खुद को 'आतंकवाद के खिलाफ' और मिडिल ईस्ट में 'अन्याय का विरोध' करने वाला बताया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय उन्हें 'एम्पायर ऑफ फियर' का सूत्रधार मानता था। 'एम्पायर ऑफ फियर' बीबीसी पत्रकार एंड्रयू होस्केन द्वारा लिखित एक गैर-काल्पनिक पुस्तक है, जो इस्लामिक स्टेट (आईएस) के उदय, उसकी क्रूर विचारधारा और विनाशकारी तरीकों का विश्लेषण करती है।

ईरान ने अपने टॉप कमांडर को मार दिया?

युद्ध के दौरान क्या ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्पेशल फोर्स के टॉप कमांडर इस्माइल कानी को मार दिया? कानी पर इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप है। अरब मीडिया के हवाले से आ रही रिपोर्ट के अनुसार कानी ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को धोखा दिया था। इस्माइल कानी ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के चीफ थे, जो विदेशों में ईरान की प्रॉक्सी को तैयार करने के लिए कुख्यात थे। अरब मीडिया में यह खबर भी आई कि कानी को जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था और संभवतः उन्हें फांसी दे दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कानी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिल गया था। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की है। कानी पर शक की सुई तब घूमी जब वो सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या करने वाले हमले में चमत्कारिक ढंग से बच गया। यूएई के 'द नेशनल' ने अपनी रिपोर्ट में बिना कंफर्म सोर्स के हवाले से बताया कि इस्माइल कानी को मोसाद से जुड़े होने के शक में मारा गया है। ऐसी रिपोर्टस कुद्स फोर्स के कमांडर के बारे में वर्षों से चल रही अफवाहों के बाद आई हैं। कानी ने अपने आसपास के शीर्ष नेताओं की हत्या करने वाले लगभग नौ संदिग्ध हत्या के प्रयासों में बार-बार बच निकलने और भागने के कारण 'नौ जिंदगियों वाला आदमी' के रूप में ख्याति पा रखी है। कहा जाता है कि इससे पहले 2024 और 2025 में भी उनकी मौत की अफवाहें तेजी से फैली थीं, लेकिन वह बाद में जिंदा सामने आ गए थे। फिलहाल तेहरान ने मीडिया रिपोर्ट में किए जा रहे दावों का खंडन किया है।

खामेनेई ने 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभाला और ईरान के धार्मिक और राजनीतिक मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण रखा, उन्होंने उदारवादियों, कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और राजतंत्रवादियों पर कड़ी कार्रवाई की, विरोधियों को 'ईशनिंदा' के आरोप में फांसी तक दे दी, फांसी भी सरेआम दी ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत न कर सके।

क्या अमेरिका फंस गया?

अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर और सिया धर्मगुरु अयातुल्ला अली खामेनेई मारे जा चुके है। ईरान के बहुत से सैन्य ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त करने का अमेरिका और ईजराइल दावा कर रहा है। यह पहली बार है, जब किसी जंग में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खामेनेई के खात्मे से बोखलाए ईरान ने मिडिल ईस्ट के 11 देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर तबाही मचा रखी है। मिडिल ईस्ट का कोई ऐसा कोना नहीं बच रहा जहां ईरान धमाके नहीं कर रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस को चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरुशलम में सीधे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। इजराइल पर हमले के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे मुस्लिम देशों पर ईरान घातक हथियारों से हमले कर रहा है। इससे भारत के कट्टरपंथियों की आंख खुल जानी चाहिए। क्योंकि ईरान मुस्लिम देश है और खाड़ी के सभी मुस्लिम देशों पर अटैक कर रहा है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर और सिया धर्म गुरु खामेनेई की हत्या करने वाला इजराइल और अमेरिका दोनों गैर मुस्लिम देश है। इजराइल यहुदियों का देश है और अमेरिका ईसाइ देश कहा जाता है। फिर भी इन देशों के हमले के बाद ईरान ने पड़ोसी मुस्लिम देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, इराक, कतर, कुवैत, जॉर्डन, यमन, लेबनान और सीरिया पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इसकी वजह है-इन देशों में अमेरिकी सैन्य बेस का होना है। ईरान का दावा है कि वो अपने हमलों में इन देशों को टारगेट नहीं कर रहा बल्कि अमेरिकी सैन्य बेस और अमेरिका से जुड़े ठिकानों को टारगेट कर रहा है। क्योंकि ईरान को पता है कि उस पर हमले के लिए इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि शुरू में मुस्लिम देशों ने ईरान पर अमेरिकी और इजराइल के हमले की आलोचना की थी, लेकिन अब जब ईरान उन्हीं की जमीन पर मिसाइलें दाग रहा है तब वो ईरान की निंदा कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने अमेरिका-इजरायल के खिलाफ अपनी कार्रवाई को क्रशिंग रिस्पॉन्स, ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 ऑपरेशन बताया है। ईरान अब तक बहरीन की राजधानी मनामा के पास अमेरिका के हेडक्वाटर्स के साथ एयरपोर्ट और रिहायशी इलाकों में मिसाइल से हमला कर चुका है। अली अल-सेलेम एयरबेस और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमले किए हैं जिसमें कई लोग घायल हुए और फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। अल उदैद एयरबेस (मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस) जिस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया, दोहा में विस्फोट के बाद उड़ानें रद्द कर दी गई। संयुक्त अरब अमीरात अल धफ्रा एयरबेस, अबू धाबी और दुबई (पाम जुमेराह, फेयरमोंट होटल) में मिसाइल हमला हो चुका है। मुवफ्फक सल्ती एयरबेस पर मिसाइल हमले को इंटरसेप्ट कर लिया गया लेकिन इससे रिहाइसी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ऐसा नहीं है कि ईरान ही हमले कर रहा है बल्कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान और तेहरान में तबाही मचाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका इजरायल के साथ ईरान के युद्ध को लेकर मुस्लिम दुनिया क्या दो फाड़ हो गई है जहां एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ बाकी के एक दर्जन मुस्लिम देश हैं? क्या ये लड़ाई लंबी चलेगी या तीसरे विश्व युद्ध में बदलेगी? क्या यूक्रेन और रूस की तरह अमेरिका ईरान के साथ जंग छेड़कर फंस गया है? क्योंकि रूस ने जहां यूक्रेन को हल्के में लिया था वहीं अमेरिका ने भी ईरान की ताकत पहचानने में कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। क्योंकि ईरान लगातार युद्ध का दायरा बढ़ाता जा रहा है।

जरूरत

लोकतंत्र की मांग राइट टू रिकॉल

'राइट टू रिकॉल' सिस्टम विश्व के कई देशों में है जिसमें जनप्रतिनिधियों का काम संतोषजनक न होने पर मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं, 'राइट टू रिकॉल' वोटर्स के लिए एक इंश्योरेंस सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसमें उन्हें यह सुरक्षा मिलेगी कि यदि उनके प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद वादा खिलाफी करते हैं तो वोटर्स बहुमत से उनका मैंडेट रद्द कर सकते हैं।

डॉ. अजीत कुमार दीक्षित
समाजशास्त्री

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजनेताओं का स्वर्ग कहा जाता है जहां यदि एक बार कोई नेता चुनाव जीत गया तो वह अगले 5 वर्षों तक जीवनानंद प्राप्त करता रहता है। वह अपने क्षेत्र में विकास का काम करें या न करें, जनता के प्रति समर्पित रहें या न रहें 5 वर्ष तक तो उनकी कुर्सी पक्की हो जाती है। आम जनता ने यदि एक दिन वोट डालते समय कोई भूल कर दी तो उसे अगले 5 वर्षों तक भुगतना अथवा झेलना पड़ता है। उनके पास अपने उस कथित जनप्रतिनिधि को झेलने के अलावा और कोई विकल्प भी शेष नहीं बचता है। भारतीय नेताओं ने राजनीति को फिक्स डिपाजिट की तरह बना दिया है जिसमें वह एक बार निवेश करते हैं और 5 वर्षों तक सत्ता और लाभ का रिटर्न प्राप्त करते रहते हैं। राजनीतिक सड़न की इस बीमारी को सुधारने की दवा 'राइट टू रिकॉल' (आरटीआर) है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मतदाताओं को अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होता है। यानी जिसे अर्श पर पहुंचाया उसे फर्श पर लाने का अधिकार होगा। यदि कोई चुना हुआ सांसद या विधायक अथवा अन्य प्रतिनिधि अपने काम से वोटर्स को संतुष्ट नहीं कर पाता है, क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली निधि का उपयोग नहीं करता है अथवा मतदाताओं की उपेक्षा करता है तो उस क्षेत्र की जनता को उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव देश के नागरिकों का अधिकार है और जब अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर जनता का विश्वास समाप्त हो जाता है, तो जनता को उन्हें हटाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो राजनीति के निरंतर अपराधीकरण के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर एक पेनाप्टिकन के रूप में कार्य करेगा।

वोटर्स के लिए इंश्योरेंस सिस्टम

'राइट टू रिकॉल' की व्यवस्था विश्व के कई देशों में लागू है जिसमें अगर जनप्रतिनिधियों का काम संतोषजनक नहीं होता है तो वहां के मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को वापस बुला सकते हैं, यानी पद से हटा सकते हैं। 'राइट टू रिकॉल' मतदाताओं के लिए एक इंश्योरेंस सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें उन्हें यह सुरक्षा मिलेती है कि यदि उनके प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपने इलाके को नजर अंदाज करते हैं या वादा खिलाफी करते हैं तो मतदाता अपने बहुमत से उनका मैंडेट रद्द कर सकते हैं और नए जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव करा सकते हैं। इस व्यवस्था से न केवल नेताओं में अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतने का डर रहेगा अपितु वह अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह भी बने रहेंगे। एक तरह से कोई भी जनप्रतिनिधि वही वादे करेगा जो वह पूरा कर सके। अभी तक राजनेता चुनाव में ऐसे वादे करते हैं जिन्हें पूरा करना संभव ही नहीं होता। 'राइट टू रिकॉल' व्यवस्था लागू होने से कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर पाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत संवैधानिक अधिकारियों को उनको चुनने वालों (वोटर्स) द्वारा हटाने का प्रावधान है तो आम लोगों को भी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को 'राइट टू रिकॉल' के जरिये हटाने का अधिकार होना चाहिए। किसी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध 'राइट टू रिकॉल' तभी लाया जाना चाहिए जब किसी प्रतिनिधि के चुनाव क्षेत्र के कुल वोटरों में से 50 प्रतिशत से अधिक वाटर्स 'राइट टू रिकॉल' के पक्ष में मतदान करें। भारतीय मतदाताओं को नोटा के रूप में एक अच्छा विकल्प मिला था किंतु नोटा का मत प्रतिशत उस चुनाव को रद्द करने की ताकत नहीं रखता है इसलिए वह नैतिक चुनावी हथियार से अधिक कुछ भी साबित नहीं हुआ। 'राइट टू रिकॉरल' व्यवस्था राजनेताओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही तो तय करेगी ही साथ ही मतदाताओं को अपना भाग्य स्वयं लिखने एवं स्वयं बदलने की क्षमता भी प्रदान करेगा।

'राइट टू रिकॉल' सिस्टम कहां लागू है

'राइट टू रिकॉल' व्यवस्था विश्व के कई देशों में लागू है जिनमें अमेरिका में कुछ राज्यों और स्थानीय (स्टेट व लोकल) स्तर पर। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में प्रांतीय स्तर पर, स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटन (प्रांतों) में, फिलीपींस में स्थानीय स्तर पर, ताइवान में विधायक, मेयर कुछ शर्तों पर राष्ट्रपति पर, जापान में स्थानीय और विधायिका स्तर पर, साउथ कोरिया में स्थानीय स्तर पर, अर्जेंटीना में कुछ राज्यों और नगर पालिकाओं में, लातविया में संसदीय व्यवस्था में, स्लोवाकिया में राष्ट्रपति के लिए रेफरेंडम रिकॉल, रोमानिया में राष्ट्रपति के लिए रेफरेंडम रिकॉल, पोलैंड में स्थानीय स्तर पर, सर्बिया में स्थानीय स्तर पर, यूक्रेन में स्थानीय स्तर पर, वेनेजुएला में राष्ट्रपति समेत सभी स्तर पर, बोलीविया में राष्ट्रपति भी 'राइट टू रिकॉल' सिस्टम में शामिल हैं। इक्वाडोर में राष्ट्रपति और स्थानीय स्तर पर, पेरू में स्थानीय स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर, कोलंबिया में मेयर और गवर्नर के लिए, पनामा में विधायक स्तर पर, मेक्सिको में राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर, रूस में स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर, नेपाल में स्थानीय निकाय स्तर पर 'राइट टू रिकॉल' सिस्टम लागू है। दुनिया के जिन देशों में 'राइट टू रिकॉल' सिस्टम है, वहां यह एक जैसा लागू नहीं होता है। कुछ देशों में यह सिस्टम राष्ट्रपति पर भी लागू होता है, जबकि कुछ में यह सांसदों को हटाने की भी इजाजत देता है। हालांकि ज्यादातर देशों में यह सिस्टम लोकल बॉडी और पंचायतों तक ही सीमित है, जिसमें भारत के कुछ राज्य भी शामिल हैं। भारत के जिन राज्यों में 'राइट टू रिकॉल' सिस्टम स्थानीय स्तर पर लागू है वहां आम जनता में इसके प्रति जागरूकता का अभाव है।

सांसद राघव चड्ढा का सुझाव है कि इस अधिकार के दुरुपयोग न हो इसलिए सुरक्षा उपाय भी जरूरी हैं, यानी पहले 35 से 40 प्रतिशत मतदाताओं के हस्ताक्षर से स्पीकर के सामने याचिका दायर हो, प्रतिनिधि को कम से कम 18 महीने काम करने का मौका मिले, इसके बाद अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता हटाने के पक्ष में वोट दें, तभी उसे हटाया जाए।

राघव चड्ढा ने उठाया 'राइट टू रिकॉल' का मुद्दा

अभी हाल ही में (फरवरी 2026) में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सदन में 'राइट टू रिकॉल' (आरटीआर) का मुद्दा उठाया। जिसने फिर से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने संसद में कहा कि जनता को जैसे नेता को हायर करने की पावर मिलती है, ठीक उसी तरह उन्हें फायर करने यानी पद से हटाने की ताकत भी मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा की इस मांग को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। क्योंकि राघव चड्ढा ने संसद में बोलते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में एक बड़ी खामी है। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे होता है और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे होती है। इसलिए वोटर्स को अपनी गलती सुधारने का अधिकार मिलना चाहिए। राघव चड्ढा ने कहा कि अगर कोई सांसद या विधायक अपने काम से जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो मतदाताओं को उसे हटाने का अधिकार मिलना ही चाहिए। राघव चड्ढा ने सुझाव दिया कि इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी जरूरी हैं। जैसे-पहले 35 से 40 प्रतिशत मतदाताओं के हस्ताक्षर से लोकसभा, विधानसभा स्पीकर के सामने याचिका

- **भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत संवैधानिक अधिकारियों को उनको चुनने वालों (वोटर्स) द्वारा हटाने का प्रावधान है तो आम लोगों को भी अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को 'राइट टू रिकॉल' के जरिये हटाने का अधिकार होना चाहिए।**
- **सांसद राघव चड्ढा ने संसद में कहा कि जनता को जैसे नेता को हायर करने की पावर मिलती है, ठीक उसी तरह उन्हें फायर करने यानी पद से हटाने की ताकत भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में एक बड़ी खामी है, चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे होता है और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे होती है, इसलिए वोटर्स को अपनी गलती सुधारने का अधिकार मिलना चाहिए।**

दायर हो। प्रतिनिधि को कम से कम 18 महीने काम करने का मौका मिले। इसके बाद अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता हटाने के पक्ष में वोट दें, तभी उसे पद से हटाया जाए।

पुरानी है 'राइट टू रिकॉल' की मांग

भारत में पहले भी इसके लिए प्रयास हुए हैं जिसमें मतदाताओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार से संबंधित संविधान (संशोधन) विधेयक 1974 में सीके चंद्रप्पन द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन विधेयक पारित नहीं हो पाया था। इससे पहले स्वतंत्रता सेनानी व विचारक एमएन रॉय ने 1944 में शासन के विकेंद्रीकृत और हस्तांतरित स्वरूप में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य प्रतिनिधियों का चुनाव करना और उन्हें पद से हटाना था। 1974 में ही जयप्रकाश नारायण ने 'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन के दौरान इसे लागू करने की वकालत की थी। 2006 से 2019 के बीच राहुल चिमनभाई मेहता ने 'राइट टू रिकॉल पार्टी' के जरिए इस मुद्दे को लगातार उठाया था। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी अतीत में विधायक की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 'राइट टू रिकॉल' सिस्टम लागू करने की मांग की थी। मार्च, 2017 में भाजपा सांसद के तौर पर वरुण गांधी के संसद में 'राइट टू रिकॉल' निजी विधेयक के रूप में लाने की चर्चा हुई थी। प्रस्तावित निजी विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया था कि किसी क्षेत्र के 75 प्रतिशत मतदाता अगर अपने सांसद और विधायक के काम से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें निर्वाचन के दो साल बाद वापस बुलाया जा सकता है। वरुण गांधी ने कहा कि तर्क और न्याय के तहत अगर लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है तो उन्हें यह भी अधिकार होना चाहिए कि वे कर्तव्य का निर्वाह नहीं करने या गलत कार्यों में लिप्त होने वाले अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकें। 'राइट टू रिकॉल' एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें किसी क्षेत्र के मतदाता एक तय प्रक्रिया के तहत हस्ताक्षर अभियान शुरू करते हैं। अगर तय संख्या में लोग लिखित रूप से मांग करते हैं, तो उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ दोबारा मतदान कराया जा सकता है। मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्थानीय निकायों में 'राइट टू रिकॉल' सिस्टम मौजूद है। छत्तीसगढ़ में खराब प्रदर्शन के कारण निर्वाचित अधिकारियों को वापस बुलाने के लिए चुनाव कराने का प्रावधान है, वहीं बिहार में मतदाताओं की मांग पर निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रावधान है। हालांकि बड़े राजनेता अपनी नेतागिरी को अपनी विरासत समझते हैं तथा राजनीतिक कुर्सी को पाना और उसे बनाए रखना अपना मौलिक अधिकार समझते हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की दशा एवं दिशा बदलने के लिए 'राइट टू रिकॉल' व्यवस्था की आवश्यकता है। राजनीति में फैले भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार समय की मांग भी है।

सियासत

अंग्रेजों की मुखबिर रही कांग्रेस?

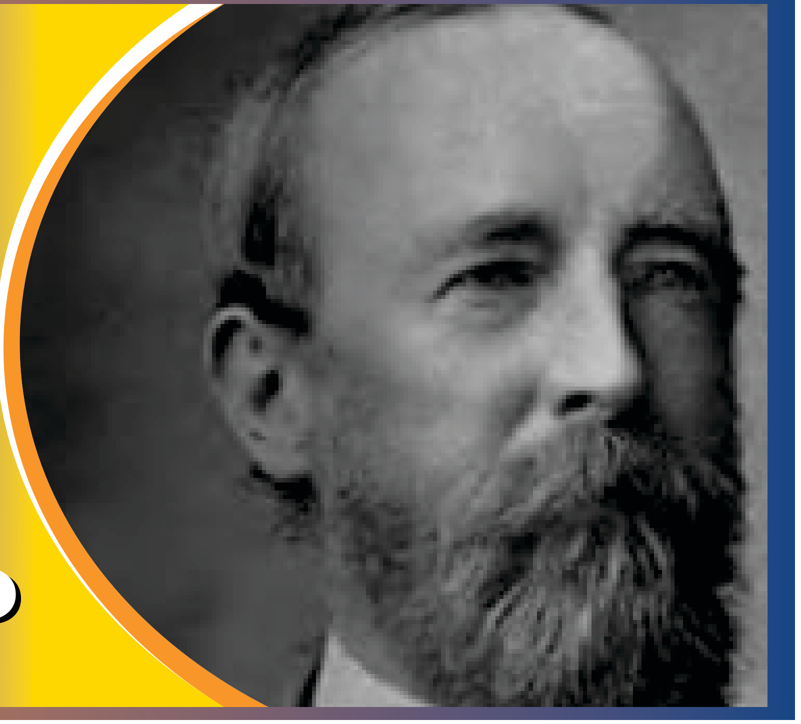

महान क्रांतिकारी स्व. लाला लाजपतराय ने यंग इंडिया में छपे अपने एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा, कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करने से कही ज्यादा उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आने वाले खतरों से उसे बचाना था।

कृष्ण कुमार चौहान

28 दिसंबर, 1885 स्थान बम्बई यानी आज का मुंबई। ये वो तारीख है जब मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस पार्टी का पहली बार गठन हुआ था। इसके संस्थापक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसके पहले अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस के गठन का मकसद ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के शिक्षित और जागरूक लोगों को संगठित राजनीतिक मंच पर लाने का बताया गया था, लेकिन यह सच नहीं था। सच ये है कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता व सैनिकों में बढ़ते असंतोष को दबाने और जनविरोध को शांत करने के लिए किया गया था। उस समय के मौजूदा वाइसराय लॉर्ड डफरिन ने यह काम सेवानिवृत्त अधिकारी स्कॉटलैंड निवासी एलन ओक्टोवियन ह्यूम को सौंपा था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के लिए एक 'सुरक्षाकवच' के रूप मे काम करना था। पंजाब केसरी के संपादक व महान क्रांतिकारी स्व. लाला लाजपतराय ने यंग इंडिया में छपे अपने एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा, कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करने से कही ज्यादा उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आने वाले खतरों से उसे बचाना था। यही नहीं उदारवादी सीएफ एड्रूज और गिरजा मुखर्जी ने भी 1938 में प्रकाशित 'भारत में कांग्रेस का उदय और विकास' में कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य के 'सुरक्षा कवच' के रूप में स्थापित करने की बात पूरी तरह स्वीकार की थी। 1939ई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक एमएस गोलवलकर ने अपने परचे 'वी' (हम) में कहा था कि हिंदू राष्ट्रीय चेतना को उन लोगों ने तबाह किया जो 'राष्ट्रवादी होने का दावा करते है। गोलवलकर के अनुसार, उस समय 'उबल रहे राष्ट्रवाद' के खिलाफ 'सुरक्षा कवच' के तौर पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यानी एलन ओक्टोवियन ह्यूम और दूसरे अंग्रेज उदारवादियों ने कांग्रेस का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार के मुखबिर के तौर पर किया। इसलिए कांग्रेस की स्थापना के शुरू के दिनों में पार्टी का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ना नहीं था।

कांग्रेस की स्थापना के बाद पार्टी का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ना नहीं था, कांग्रेस में देश के प्रबुद्ध लोगों इसलिए शामिल किया गया ताकि देश के क्रांतिकारियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके और उनके आंदोलन को कुचला जा सके, यानी कांग्रेस का गठन मुखबिरों के संगठन के रूप में किया गया था।

कांग्रेस में देश के प्रबुद्ध लोगों इसलिए शामिल किया गया ताकि देश के क्रांतिकारियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके और उनके आंदोलन को कुचला जा सके। अर्थात कांग्रेस का गठन एक तरह से मुखबिरों की सेना तैयार करने के लिए किया गया था। इसलिए किसी कांग्रेसी पर ब्रिटिश सरकार ने कभी भी अत्याचार नहीं किया, न ही किसी कांग्रेसी को फांसी या काले पानी की सजा दी, बल्कि उन्हें बंदी बनाने की जरूरत भी हुई तो उन्हें सभी सभी सुविधाओं वाले बंगलों में रखा गया।

कांग्रेस दो गुटों में बंटी

ब्रिटिश सरकार के लगातार विरोध के कारण कांग्रेस ने भारत की आजादी के आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया, ताकि उभरने वाले नए राजनीतिक सिस्टम में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बन सके। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ और इससे ही कांग्रेस को नई पहचान मिली। कांग्रेस ने बंटवारे का खुलकर विरोध किया और अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू ही किए थे कि अंग्रेजों ने कांग्रेस में ही फूट डाल दी थी। यानी कांग्रेस में दो धड़े बन गए, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल चाहता था कि आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रखा जाए, जबकि नरम दल खुलकर अंग्रेजों की बगावत करने के खिलाफ था। जब कांग्रेस का गठन हुआ था तब मोहनदास करमचंद गांधी का इससे कोई नाता नहीं था। गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। 1919 में असहयोग आंदोलन से गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद तो कांग्रेस के मायने ही बदल गए और पार्टी का मतलब ही महात्मा गांधी हो गया। गांधी के आंदोलन दुनिया में अपनी तरह के पहले ऐसे आंदोलन थे, जिसमें किसी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ी गई। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों का हिस्सा रही, जिनमें सविनय अविज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आजादी से पहले कांग्रेस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे और 7 करोड़ से ज्यादा समर्थक। उस समय किसी ने सोचा नहीं होगा कि 140 साल बाद 2026 में कांग्रेस की इतनी दुर्दशा होगी कि वो सिर्फ 3 राज्यों में ही अपनी सरकार चला पाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में नई-नई क्षेत्रीय पार्टियों से भी बुरा प्रदर्शन करेगी। यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर सिमट जाएगी। लोकसभा में 44 सीटों पर आ जाएगी। केंद्र में 400 से ज्यादा सीट लाने वाली कांग्रेस का ऐसा पतन होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्यों देश की सबसे पुरानी पार्टी की ऐसी दशा और दुर्दशा हो रही है?

कांग्रेस के पतन की शुरुआत

2014 को कांग्रेस के पतन का साल माना जाता है, लेकिन असल में इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। कांग्रेस के पतन की कहानी तीन चरणों में समझी जा सकती है। कांग्रेस को पहला झटका 1977 के आम चुनाव में लगा था। जब इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल (1975-77) के बाद 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा था। यह पहली बार था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। इस हार ने यह संकेत दे दिया था कि कांग्रेस अपराजेय नहीं है। असली पतन की नींव 1989 से 1996 में रखी गई। यानी कांग्रेस के पतन की असली शुरुआत 1989 से मानी जा सकती है। राजीव गांधी के कार्यकाल में बोफोर्स घोटाला और शाह बानो मामले में उलझी कांग्रेस 1989 के चुनाव में हार गई थी। इसके बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या ने पार्टी को गहरा झटका दिया। 1996 के चुनाव में कांग्रेस को महज 140 सीटें मिलीं यह उस समय तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इस दौर में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ और कांग्रेस का एकाधिकार टूटने लगा। 1999 से 2004 तक कांग्रेस विपक्ष में रही। 2004 में यूपीए सरकार बनी, लेकिन यह कांग्रेस की अकेली सरकार नहीं थी। बल्कि पार्टी गठबंधन पर निर्भर हो गई थी। 2009 में दोबारा यूपीए सत्ता में आई, लेकिन 2010 के बाद घोटालों की बाढ़ आ गई। 2जी, कोलगेट, कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों ने कांग्रेस की छवि पूरी तरह तबाह कर दी। 2013 आते-आते सरकार पूरी तरह लंगड़ी हो गई और अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने कांग्रेस की जड़ें हिला दीं। 2014 का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए सुनामी की तरह था। मोदी की लहर में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद से पार्टी लगातार नीचे ही गिरती रही। 2019 में सिर्फ 52 सीटें मिलीं। राज्यों के चुनावों में भी कांग्रेस शर्मनाक हार का सामना करती आ रही है और ये सिलसिला अभी जारी है। सच यह है कि कांग्रेस का पतन एक रात में नहीं हुआ। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जो 1989 से शुरू हुई, 2004-2014 के घोटालों से गहरी हुई और 2014 के बाद कांग्रेस पूरी तरह गर्त में चली गई।

कांग्रेस की गलतियां

कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या नेतृत्व की कमी है। राहुल गांधी को युवा नेता के तौर पर लॉन्च किया गया, लेकिन वे जनता से जुड़ने में नाकाम रहे। राहुल की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। 2014 में आलू से सोना बनाने वाला बयान हो या चुनाव प्रचार के दौरान छुट्टियां मनाना, ऐसे कई मौके आए जब राहुल की छवि एक लापरवाह नेता की बनी। वो न तो पार्टी संगठन को मजबूत कर पाए और न ही चुनावी रणनीति में कोई नया प्रयोग किया। राहुल गांधी की

राहुल गांधी को युवा नेता के तौर पर लॉन्च किया गया, लेकिन वे जनता से जुड़ने में नाकाम रहे। राहुल की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, 2014 में आलू से सोना बनाने वाला बयान हो या चुनाव प्रचार के दौरान छुट्टियां मनाना, राहुल की छवि एक लापरवाह नेता की है।

दूसरी बड़ी गलती युवा नेताओं को आगे न बढ़ाना रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमंता बिस्वा सरमा जैसे कई युवा नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस का ढांचा गांधी परिवार के इर्द-गिर्द घूमता है। पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से नेता नहीं चुने जाते। चाहे कोई कितना भी मेहनत करे, अगर वह गांधी परिवार के करीब नहीं है तो उसे महत्वपूर्ण पद नहीं मिलता। रॉयल फैमिली वाली छवि ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1990 के दशक तक कांग्रेस का हर गांव, हर मोहल्ले में मजबूत संगठन होता था। लेकिन अब संगठन खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ, भाजपा ने आरएसएस की मदद से मजबूत संगठन खड़ा कर लिया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रवाद, विकास और हिंदू पहचान के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाया। जबकि कांग्रेस इसका विरोध करने लगी। कांग्रेस विकास के मुद्दे पर भी भाजपा को चुनौती नहीं दे पाई। हर चुनाव में कांग्रेस सिर्फ मोदी विरोध करती है। आज के दौर में गठबंधन की राजनीति जरूरी है, लेकिन कांग्रेस इसमें भी नाकाम साबित हुई है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन से नुकसान होगा। यूपी में सपा बिहार में राजद और पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस को गंभीर सहयोगी नहीं मानते। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, यूपीए-2 सरकार के दौरान हुए इन घोटालों ने कांग्रेस की छवि खराब कर दी। भले ही कई मामलों में आरोपी बरी हो गए, लेकिन जनता के मन में जो नकारात्मक छवि बन गई, वह आज तक बनी हुई है। कांग्रेस इस छवि को बदलने में नाकाम रही। कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट है। अगर पार्टी को फिर से खड़ा होना है तो उसे कई कठोर फैसले लेने होंगे। सबसे पहले, पार्टी को गांधी परिवार की छाया से बाहर निकलना होगा और लोकतांत्रिक तरीके से नेतृत्व चुनना होगा। दूसरा जमीनी संगठन को फिर से मजबूत करना होगा। तीसरा आधुनिक संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग करना होगा। लेकिन सबसे जरूरी है एक नई विचारधारा और एजेंडा विकसित करना। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वह देश को कहां ले जाना चाहती है। सिर्फ भाजपा की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। ●

धरोहरों पर संकट

पुरातत्व विभाग के संरक्षण वाले अल्मोड़ा जिले में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर के शिखर का हिस्सा टूट गया है, जबकि जागेश्वर मंदिर की ईंटें गल चुकी हैं, यहां विभाग ही मरम्मत एवं सुधार संबंधी कार्य करा सकता है, लेकिन पुरातत्व विभाग की उपेक्षा के कारण इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।

हरीश भट्ट
रामनगर

उत्तराखंड में ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है जो पर्यटकों और पुरातत्वविदों को आकर्षित करते हैं। वैसे भी उत्तराखंड अपनी प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। बावजूद इसके तमाम ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो सामने नहीं आ पाई हैं। ऐसी धरोहरों को आज संरक्षण की दरकार है। हाल यह है कि संरक्षण के लिए राज्य और केंद्र सरकार की सूची में शुमार होने के बाद भी तमाम धरोहरों के प्रसार और संरक्षण की दिशा में कुछ खास काम नहीं हो पाया है। कत्यूरी, चंद, गोरखा, अंग्रेज शासकों ने यहां सैकड़ों साल राज किया। हिंदू ग्रंथों में केदारखंड और मानस खंड के रूप में कुमाऊं और गढ़वाल के पौराणिक इतिहास के बारे में स्पष्ट उल्लेख है। कुमाऊं पौराणिक इतिहास को अलग-अलग रूपों में समेटे हुए है। पुराने पांडवकालीन व ऐतिहासिक मंदिर, शिलालेख, इंडो यूरोपियन शैली में बने भवनों के अलावा तमाम ऐसी धरोहरें हैं जो संरक्षण के अभाव में दम तोड़ रही है। कुछ मुख्य धरोहरों के अलावा तमाम अन्य ऐसी गुमनाम धरोहर हैं जो यहां के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कुमाऊं के चार जिलों में अनेक पुरानी ऐतिहासिक धरोहरें आज भी पुरातत्व विभाग की संरक्षण सूची में शामिल नहीं हो पाई है। इसमें अल्मोड़ा जिले में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कनरा, पवनेश्वर मंदिर पुभाऊं, प्राचीन शिलालेख कसारदेवी, बोडसी देवालय बाड़ेछीना, ल्वेटा रॉक पेंटिंग, बद्रीनाथ मंदिर छत्तगुल्ला, मणिकेश्वर मंदिर बिता, चूड़ाकर्म महादेव मंदिर मासी। बागेश्वर जिले के ऐड़ी देवालय, टोटा देवालय, शिव मंदिर मोहली, धौभिणा बिरखम आदि। चंपावत जिले में शिव मंदिर मजपीपल, सूर्य मंदिर मण संरक्षण की सूची में शामिल हैं। जबकि पिथौरागढ़ के विष्णु मंदिर कोटली को पिछले साल ही भारत सरकार को स्थानांतरित किया गया है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण वाले अल्मोड़ा जिले में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर के शिखर का हिस्सा टूट गया है। जबकि जागेश्वर मंदिर की ईंटे गल चुकी हैं। यहां विभाग ही मरम्मत एवं सुधार संबंधी कार्य करा सकता है, लेकिन पुरातत्व विभाग की उपेक्षा के कारण इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पौराणिक धरोहरों को संरक्षित रखने का जिम्मा संभालने वाले पुरातत्व विभाग खुद अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। हालत यह है कि कुमाऊं के चार पर्वतीय जिलों के लिए यहां पुरातत्व अधिकारी समेत अन्य स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है। लिहाजा यहां की प्राचीन धरोहरों का जिम्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भरोसे है। ऊधमसिंह नगर के काशीपुर स्थित गोविषाण किला भी दो सुरक्षा कर्मियों के भरोसे छोड़ दिया गया है।

नेलांग घाटी में हिमालय की खड़ी पहाड़ी को काटकर दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता तैयार किया था, करीब 150 मीटर लंबी लकड़ी से तैयार यह सीढ़ीनुमा गड़तांग गली भारत-तिब्बत व्यापार की साक्षी रही है। उत्तरकाशी जिले में जाड़ गंगा घाटी में स्थित सीढ़ीनुमा यह मार्ग फिलहाल खस्ताहाल है।

गड़तांग गली का अस्तित्व खतरे में

इतिहास हमें उन चीजों की झलक दिखाता है जो शायद हमारे जीवनकाल में घटित न हुई हों, लेकिन जिनकी झलक कला, वास्तुकला और लुप्त हो चुकी संस्कृति के अवशेषों में देखी जा सकती है। उन अतीत के खजानों की अत्यंत सावधानी से रक्षा की जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद कर सकें। 17वीं शताब्दी में पेशावर के पठानों ने समुद्रतल से 11 हजार फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले की नेलांग घाटी में हिमालय की खड़ी पहाड़ी को काटकर दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता तैयार किया था। करीब 150 मीटर लंबी लकड़ी से तैयार यह सीढ़ीनुमा गड़तांग गली भारत-तिब्बत व्यापार का साक्षी रही है। उत्तरकाशी जिले में जाड़ गंगा घाटी में स्थित सीढ़ीनुमा यह मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार है। 1962 से पूर्व भारत-तिब्बत के व्यापारी याक, घोड़ा-खच्चर एवं भेड़-बकरियों पर सामान लादकर इसी रास्ते से आते-जाते थे। 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान गड़तांग गली ने सेना को अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन पिछले 46 वर्षों से गड़तांग गली का उपयोग और रखरखाव न होने के कारण इसका अस्तित्व मिटता जा रहा है। भारत सरकार ने उत्तरकाशी के इनर लाइन क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था। तभी से नेलांग घाटी एवं जाडुंग गांव को खाली करवा कर वहां अर्धसैनिक बलों को तैनाती की गई थी। यहां के गांवों में रहने वाले लोगों को एक निश्चित प्रक्रिया पूरी करने के बाद साल में एक ही बार अपने में देवी-देवताओं की पूजा करने की इजाजत दी जाती रही है। इसके बाद भारत के आम लोगों को भी नेलांग घाटी तक जाने की इजाजत गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 2015 में दे दी थी, हालांकि विदेशियों पर प्रतिबंध बरकरार है। आज की तकनीक को चुनौती देती एतिहासिक धरोहर गड़तांग गली की सीढ़ियां दम तोड़ती नजर आ रही है। जाड़ गंगा के ऊपर पथरीली चट्टानों पर बनी ये सीढ़ियां एक नायाब इंजीनियरिंग का नमूना है, लेकिन शासन-प्रशासन और वन विभाग की अनदेखी के कारण आज ये सीढ़ियां जीर्णशीर्ण हालत में हैं। जबकि पर्यटन के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क की ओर गड़तांग गली की सीढ़ियों के विकास के लिए लाखों की धनराशि खर्च की गई, लेकिन उसका प्रयोग मात्र खानापूर्ति के लिए किया गया। अगर यही स्थिति रही तो ये ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण के आभाव में समाप्त हो जाएगी।

पहाड़ का कोल्ड स्टोर कुठार

उत्तरकाशी जिले के कई गांवों में प्राचीन कुठार परंपरा हासिये पर जा रही है। अन्न भंडारण के लिए गोदाम के तौर पर कुठार का इस्तेमाल होता था। यमुनाघाटी के नगाणगांव में आज भी कुठार और पंचपुरे भवन देखने को मिल जाएंगे, जो मौजूदा समय में पहाड़ी इलाकों से लगभग पूरी तरह से विलुप्ति की कगार पर हैं। उत्तरकाशी जिले की गंगाघाटी में उपला टकनौर के मुखबा, धराली, पाटा संग्राली और यमुनाघाटी के पुरोला, मोरी, बड़कोट आदि गांवों में निर्मित कुठार और पंचपुरे भवन मौजूद हैं, जो अब बदलते वक्त के साथ दुर्लभ हो गए हैं। अब आवश्यकता है इस प्राचीन धरोहर के संवर्धन और संरक्षण की। उत्तरकाशी जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक और चारधाम यात्री आते हैं। आज जिस प्रकार से सरकार होमस्टे के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार दे रही है, वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए कुठारों का संवर्धन और संरक्षण होगा तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक और चारधाम यात्री यहां आएंगे वो इन प्राचीन कुठारों का दीदार कर सकेंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनका उपयोग किस रूप में होता था। इसलिए ग्राम पंचायतों को इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे आना चाहिए। वैसे कुठार में लोग सदियों में धान, गेंहू, कोदा, झंगोरा, मंडुवा, चैलाई, दालें, घी, तेल, चीनी व रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु रखते आए हैं। एक तरह से ये कुठार पहाड़ी कोल्ड स्टोरेज भी है। सुरक्षा की दृष्टि से सोने चांदी के बेशकीमती गहनों को भी लोग कुठार में ही रखते आए हैं। ज्यादातर गांवों में आज भी कुठार मौजूद हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ अन्न भंडारण में इनका अब कम ही उपयोग हो रहा है। इससे प्रचान संस्कृति के संवाहक रहे कुठार विलुप्ति की कगार पर हैं। कुठारों के निर्माण में पूरी तरह से सौ फीसदी देवदार की लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है। जिससे कुठार में भंडारण किया गया अनाज कभी भी खराब नहीं होता है। ये कुठार कोल्ड फ्रीज का भी काम करते हैं। यानी इनका तापमान मौसम के लिहाज से बदलता रहता है। नगाणगांव में आज भी कुछ कुठार सही सलामत हैं। दुनियाभर के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों से पढ़कर निकले बड़े से बड़े इंजीनियर (आर्किटेक्ट) पहाड़ों में बने इस तरह के कुठार व पंचपुरे भवनों के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते, जो आज से सदियों पूर्व बुजुर्गों, कारीगरों, मिस्त्रियों ने बिना शिक्षा-दीक्षा व बिना स्कूली ज्ञान के निर्मित किए हैं।

प्राचीन धरोहरों को संरक्षित रखने वाले पुरातत्व विभाग स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, हाल यह है कि कुमाऊं के चार पर्वतीय जिलों में पुरातत्व अधिकारी व स्टाफ की तैनाती ही नहीं है, यहां की प्राचीन धरोहरों का जिम्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भरोसे है, ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में गोविषाण किला दो सुरक्षा कर्मियों के भरोसे छोड़ दिया गया है।

गर्जिया देवी मंदिर खतरे में

नैनीताल जिले में प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के टीले में आई दरार लगातार बढ़ रही है। 2010 में बाढ़ आने के बाद से दरार बढ़ती जा रही है, साथ ही मिट्टी भी तेजी से गिर रही है, लेकिन 15 साल बाद भी टीले की मरम्मत और मंदिर के सुरक्षात्मक कार्य के लिए बजट पास नहीं हो पाया है। रामनगर में प्रसिद्ध गर्जिया या गिरिजा देवी मंदिर कोसी नदी की दो धाराओं के बीच एक टीले के ऊपर मौजूद है। 2010 में बाढ़ से टीले में दरार पड़ गई जिससे लगातार मिट्टी गिरती रहती है। जिससे मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसका सर्वे कई बार रुड़की के भूगर्भ वैज्ञानिक कर चुके हैं। इसके बाद सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए डीपीआर बनाई गई, लेकिन मरम्मत के लिए शासन से बजट ही पास नहीं हो पा रहा है। 2024 में बरसात के दौरान सिंचाई विभाग ने नदी के पानी से मंदिर को बचाने के लिए विशेष तिरपाल के जरिए पूरे टीले को कवर कर दिया था। इसी साल कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर भी टीले की सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर के नीचे ही माता के पदचिह्न रखकर दर्शन कराए गए थे। भक्तों को ऊपर टीले पर नहीं जाने दिया गया था। इन 15 सालों में कई बार सर्वे कर प्रस्ताव भी भेजे गए, लेकिन सरकार इसके स्थाई समाधान की तरफ नहीं बढ़ पाई, सिर्फ लीपापोती ही की जाती रही। हालांकि सिंचाई विभाग ने स्थाई सुरक्षा के लिए 9.29 करोड़ रुपये का डीपीआर बनाकर शासन को भेजा था, लेकिन इस बार भी मूल्यांकन समिति की बैठक में रुड़की से आई टेक्निकल टीम ने इसको मॉडिफाई करने की बात कहकर काम लटका दिया। गर्जिया देवी के मुख्य पुजारी मनोज पांडे का कहना है कि इन 15 सालों में कई बार तत्कालीन और वर्तमान मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक टीले की सुरक्षा का कार्य नहीं हो पाया है। हालांकि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मंदिर की सुरक्षा के उपाय होते दिखाए गए हैं। ये उपाय क्या पुख्ता है अथवा फिर से काम चलाऊ हैं? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन पर भी ग्रहण लग रहा है। हालांकि ये उत्तराखंड की वो धरोहर हैं जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से खंडहर में तब्दील हो जाएगी। यानी आने वाली पीढ़ी इन धरोहरों को सिर्फ किताबों में ही पढ़ पाएगी।

खतरे में देवदार

हिमालय की वादियों में पाए जाने वाला देवदार का विशाल वृक्ष धार्मिक आस्था से जुड़ा है, पर्यावरण और मानव जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, यह न सिर्फ अपनी प्राकृतिक व आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके औषधीय, आर्थिक और पर्यावरणीय गुण इसे अनमोल बनाते हैं, वर्तमान में आयुर्वेद के बढ़ते महत्व के बीच देवदार ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

डॉ.हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

देवभूमि उत्तराखंड अपने खूबसूरत नजारों और प्राकृतिक संपदा के लिए खूब जानी जाती है। उत्तराखंड में वैसे तो कई वन संपदा पाई जाती हैं, लेकिन राज्य के पहाड़ी इलाकों के जंगलों में पाया जाने वाला एक पेड़ ऐसा भी है, जिस पर देवताओं का वास माना जाता है। यह पेड़ उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला देवदार है। यह पेड़ शंकुधारी आकार लिए उगता है। देवदार का वृक्ष अपनी मजबूती, लंबी उम्र और औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। 'वुड ऑफ गॉड' यानी भगवान की लकड़ी कहे जाने वाले इस वृक्ष से न केवल सदियों तक टिकने वाला फर्नीचर तैयार होता है, बल्कि इससे प्राप्त तेल त्वचा रोगों, मस्सों और मुहांसों के उपचार में भी बेहद उपयोगी माना जाता है। देवदार का उपयोग मुख्य रूप से सूजन, गठिया (दर्द), त्वचा रोग, बुखार, कब्ज, खांसी और सांस की तकलीफों के इलाज के लिए किया जाता है। इसकी छाल, लकड़ी और उससे प्राप्त सुगंधित तेल का उपयोग चूर्ण, काढ़ा या लेप के रूप में किया जाता है। देवदार की तासीर गर्म होती है, जो वात और कफ दोष को कम करती है। हिमालय की वादियों में पाए जाने वाला यह विशाल वृक्ष धार्मिक आस्था से जुड़ा है। पर्यावरण और मानवीय जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके औषधीय, आर्थिक और पर्यावरणीय गुण इसे अनमोल बनाते हैं। वर्तमान में आयुर्वेद के बढ़ते महत्व के बीच देवदार ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

देवदार के औषधीय

देवदार को 'देवताओं की लकड़ी' के रूप में जाना जाता है। भारत में यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और सिक्किम जैसे राज्यों में मिलता है। इसकी ऊंचाई 40-60 मीटर तक हो सकती है। पहाड़ी परिवेश में रहने वाले परिवार जुकाम-खांसी होने पर देवदार को औषधि के रूप में उपयोग करते रहे हैं। यह फेफड़ों से अतिरिक्त कफ को बाहर निकाल देता है। यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बलगम को निकालकर खांसी जैसे कफ विकार रोगों से राहत दिलाने में मदद करता है। देवदार के सेवन से अस्थमा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सांस फूलने की स्थिति में राहत देता है। यानी अस्थमा जैसे रोगों में देवदार का सेवन रामबाण का काम करता है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण के कारण गठिया से संबंधित सूजन और दर्द जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए इसे जोड़ों पर लगाया जा सकता है। देवदार के तेल को एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण के कारण घावों पर भी लगाया जा सकता है। त्वचा पर देवदार के पत्ते का पेस्ट लगाने से त्वचा के संक्रमण के साथ इसके एंटीफंगल गुण खुजली को रोकने में मदद करते हैं। हिंदू धर्म में देवदार को पवित्र वृक्ष माना जाता है।

देवदार के संरक्षण की मांग

पुराणों में इसे भगवान शिव से जोड़ा जाता है और कई धार्मिक स्थलों पर इसके वृक्ष लगाए जाते हैं। इसकी शीतल छाया और सुगंधित वातावरण ध्यान और योग के लिए बेहतर माहौल बनाते हैं। आयुर्वेद में देवदार का विशेष स्थान है। वर्ष 1985 में जब चंपावत पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा था, तब तत्कालीन पर्यावरण प्रेमी जिलाधिकारी ने लोहाघाट नगर के प्रत्येक देवदार पेड़ की नंबरिंग कर विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कराया था, जिसमें लगभग 15 हजार पेड़ दर्ज थे। वर्ष 2013 में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा कराई गई गिनती में यह संख्या घटकर करीब 12 हजार रह गई थी। इसके बाद अवैध कटान और अतिक्रमण लगातार जारी रहा। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि दिनदहाड़े देवदार के वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलने लगी। वन विभाग ने जुर्माना तो लगाया, लेकिन यह हिम्मत कैसे और किसके संरक्षण में पैदा हुई, इस पर न तो गहन जांच हुई और न ही कोई स्थाई समाधान निकाला गया। वन प्रेमियों ने देवदार से आच्छादित क्षेत्र में इन दुर्लभ प्रजाति के वृक्षों के संरक्षण के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने एवं उनका नियंत्रण सीधे थाने से किए जाने की मांग उठाई थी, नगरीय क्षेत्र में देवदार वृक्षों की पूर्ण सुरक्षा वन विभाग को सौंपने का मुद्दा उठाया था। नगर पालिका और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नियमित गश्त की मांग भी उठी थी। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले परिवारों को लिखित में पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर उन्हें सहभागी बनाने की जरूरत बताई गई थी। ताकि स्थानीय निवासी इन धार्मिक और औषधीय महत्व के वृक्षों को अपनी धरोहर समझकर बचा सकें। क्योंकि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेगलुरु जैसे महानगरों से मायावती आश्रम और रीठा साहिब आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री इन देवदारों के पेड़ों का दीदार करते हैं।

- **1985 में जब चंपावत पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा था, तब तत्कालीन जिलाधिकारी ने लोहाघाट नगर के देवदार पेड़ की नंबरिंग कर विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कराया था, जिसमें लगभग 15 हजार पेड़ दर्ज थे, 2013 में तत्कालीन डीएम द्वारा कराई गई गिनती में यह संख्या घटकर 12 हजार रह गई थी।**
- **देवदार भारत के हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष होने के साथ ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है, इसका तना बेहद मजबूत होता है और यह 65 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, भारत में 1584 वर्ष पुराना देवदार का पेड़ लाहौल स्पीति में पाया गया है।**

लोहाघाट से 12 हजार पेड़ गायब

जिले का खूबसूरत लोहाघाट क्षेत्र जहां देवदार का घना जंगल है, वहां कई वर्षों से लगातार बढ़ते कंक्रीट के जंगल, अतिक्रमण और अवैध कटान से देवदार के वृक्षों पर संकट पैदा हो गया है। शहरी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों के सूखने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब जिला प्रशासन एवं वन महकमा सख्त हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर लोहाघाट वन विभाग जहां देवदार के सूखे पेड़ों के ट्रीटमेंट में लगा है। वहीं पेड़ों को सुखाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ भी वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल देवदार के वृक्षों पर मंडरा रहे संकट पर स्थानीय लोग भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर पालिका क्षेत्र में देवदार के दुर्लभ और ऐतिहासिक वृक्षों पर संकट गहरा रहा है। क्योंकि यहां अतिक्रमण की नीयत से रसायन डालकर सैकड़ों देवदार के पेड़ों को सुखाने की साजिश सामने आई है। उप प्रभागीय वन अधिकारी लोहाघाट सुनील कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने करीब एक दर्जन से अधिक देवदार के हरे पेड़ों में गार्डनिंग एवं विशेष ट्रीटमेंट किया है, ताकि उन्हें सूखने से बचाया जा सके। हालांकि लोहाघाट नगर क्षेत्र में देवदार के वृक्षों की सुरक्षा को लेकर वर्षों से एक बड़ी प्रशासनिक उलझन बनी हुई है। अधिकांश भूमि नजूल श्रेणी की है, जिसकी देखरेख राजस्व विभाग करता है, जबकि पेड़ों की सुरक्षा का दायित्व नगर पालिका अथवा वन विभाग के बीच स्पष्ट रूप से तय नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा एरिया वाइज विभागीय जिम्मेदारी तय करने की बात तो कही, लेकिन जमीनी हकीकत में यह व्यवस्था व्यावहारिक रूप से कठिन मानी जा रही है। लोहाघाट के सीनियर सिटीजन एवं वरिष्ठ पत्रकार दावा करते हैं कि कुछ ही वर्षो में नगर क्षेत्र में अतिक्रमण आदि के कारण 12 हजार से अधिक देवदार के पेड़ गायब हो चुके हैं।

1584 वर्ष पुराना देवदार लाहौल स्पीति में

देवदार भारत के हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष होने के साथ ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसका तना बेहद मजबूत होता है और यह 65 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। भारत में 1584 वर्ष पुराना देवदार का पेड़ लाहौल स्पीति में पाया गया। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल समेत दुनियाभर के कई देशों में सालों पुराने देवदार के वृक्ष आज भी मौजूद हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में नयनापीक, कैमल्स बैक की पहाड़ियों में देवदार का घना जंगल है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में देवदार के विशाल पेड़ हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर देवदार के विशाल पेड़ों के बीच ही स्थित है। देवदार के पेड़ों को भूनिर्माण परियोजनाओं में शामिल करने से उनकी सुंदरता और लचीलापन के साथ बाहरी स्थान बेहतर होते हैं। प्रत्येक प्रजाति अद्वितीय गुण प्रदान करती है जो विभिन्न वातावरणों और डिजाइन वरीयताओं के अनुकूल होती है। ये राजसी शंकुधारी पेड़ अच्छी तरह से सूखी मिट्टी, पर्याप्त धूप और नियमित रखरखाव से सजावटी केंद्र बिंदु के रूप में पनपते हैं। चाहे नजारे को फ्रेम करना हो, छाया प्रदान करना हो या मौसमी उत्सवों का प्रतीक हो, देवदार के पेड़ प्रकृति की स्थाई सुंदरता का उदाहरण देते हैं और संधारणीय भूनिर्माण प्रथाओं में कालातीत निवेश के रूप में काम करते हैं। उत्तराखंड में मनमाने ढंग से सड़क के किनारे देवदार के जंगलों में मिट्टी डालने से दुर्लभ प्रजाति के देवदार वृक्षों के अस्तित्व पर संकट पैदा हो रहा है। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से लोगों के हौसले बुलंद हैं और वह धड़ल्ले से नर्माण कार्यों से निकलने वाली मिट्टी को सड़कों के किनारे और देवदार वृक्षों की जड़ों में डालते जा रहेहैं। नगर और आसपास के क्षेत्रों में निजी तथा सरकारी भवनों का निर्माण करने वाले कुछ लोग जमीन की खुदाई से निकल रही मिट्टी को सरेआम सड़क किनारे और पेड़ों की जड़ों में डंप कर रहे हैं। मिट्टी पेड़ों की जड़ों में डंप किए जाने से देवदार वृक्षों को खतरा पैदा हो गया है। साथ ही सड़क संकरी होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है।

- **उत्तराखंड के नैनीताल में नयनापीक, कैमल्स बैक की पहाड़ियों में देवदार का घना जंगल है, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में देवदार के विशाल पेड़ हैं, जागेश्वर मंदिर परिसर देवदार के विशाल पेड़ों के बीच ही स्थित है, देवदार के पेड़ों को भूनिर्माण परियोजना में शामिल करने से उनकी सुंदरता और लचीलेपन के साथ बाहरी स्थान बेहतर होते हैं।**
- **लोहाघाट वन विभाग जहां देवदार के सूखे पेड़ों के ट्रीटमेंट में लगा है, वहीं पेड़ों को सुखवाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, फिलहाल देवदार के वृक्षों पर मंडरा रहे संकट पर स्थानीय लोग भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।**

20 करोड़ लोगों की आजीविका पर संकट

हिमालय की अद्वितीय व अटूट प्राकृतिक संपदा और आदिम जातियों की जीवन के प्रति गहरी लालसा के प्रमुख साधन रहे जंगल संपूर्ण भारत में तेजी से लुप्त हो रहे हैं। भारतीय वन विभाग अभी तक दावा करता रहा कि भारत के कुल भू-भाग में 19 प्रतिशत जंगल हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण ने खुलासा किया है कि बीते 10 साल के भीतर 3000 वर्ग किलोमीटर जंगलों का दोहन हो चुका है। यदि इसी रफ्तार से जंगल साफ हुए तो 100 सालों में दो तिहाई घने जंगल पुप्त हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपग्रह के माध्यम से दुनिया भर के जंगलों के फोटो लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें सरकारी दावों को पूरी तरह झुठा करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 8 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित रह गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1989 तक करीब 3290 लाख हेक्टेयर में फैले भू-क्षेत्र में से 19.5 प्रतिशत भू-भाग में जंगल थे, जिनकी कटाई 15 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से की जा रही है, लिहाजा वन घटकर केवल 8 फीसदी बताए गए हैं। वनों का आंकलन दस साल पहले की रिपोर्ट में दशाए गए आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन से होता है। दस साल पहले देश में कुल 7.83 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वन थे जो घटकर 24 फीसदी बचे हैं। वनों का विनाश, विकास के बहाने औधोगिकीकरण की भेंट चढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक बीते दो साल के भीतर ही 367 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र साफ कर दिया गया। जिससे देश में जंगल और पेड़ों की मौजूदगी घटकर 23.81 फीसदी रह गई है, जो 33 फीसदी होनी चाहिए थी। इस स्थिति ने जंगल से जुड़े 20 करोड़ लोगों की आजीविका पर संकट आ गया है। आधुनिक और औद्योगिक विकास के कारण पहले भी करीब 4 करोड़ वनवासियों को विस्थापित कर उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया था।

अविमुक्तेश्वरानंद व योगी में ठनी

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जगदगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष पांडेय ने जब से बटुकों के यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है तब से ये विवाद और बढ़ गया है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब योगी के इशारे पर किया जा रहा है।

उदय भान सिंह
लेखक

अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच महाकुंभ के समय से छत्तीस का आंकड़ा है। इसके बाद प्रयागराज में माघ मेले के दौरान रथ के साथ से संगम नोज जाकर स्नान पर अड़े अविमुक्तेश्वरानंद की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। क्योंकि प्रशासन उनसे पैदल जाकर स्नान करने को कह रहा था। इससे नाराज अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे गए। उसी समय अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि जब तक प्रशासन ससम्मान स्नान के लिए नहीं ले जाता, स्नान नहीं करुंगा। स्वामी के इस हठ पर कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार और डीएम मनीष कुमार वर्मा के मनाने के बाद भी जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं माने, तो पुलिस ने बलपूर्वक उनको वहां से हटा दिया था। जिससे पुलिस कर्मियों और साधुओं के बीच हाथापाई भी हो गई। कुछ साधुओं को पुलिसकर्मियों ने घसीट कर वहां से हटाया था। इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना शुरू कर दिया। 40 दिन का वक्त देते हुए योगी से उनके हिंदू होने का प्रमाण मांग लिया। यानी योगी को इसके लिए 10 मार्च का समय दिया गया। साथ ही दावा किया कि 11 मार्च को हम यह घोषित करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी हिंदू हृदय सम्राट है या फिर नकली हिंदू, जो भगवा पहनकर कालनेमि की शक्ल में लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। यदि योगी हिंदू होने का प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो वो असली हिंद नहीं नकली होंगे। योगी को पाखंडी ढोंगी है और दिखावे के लिए भगवा वस्त्र पहनना मान लिया जाएगा। योगी सिर्फ दिखावे के लिए ही अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। प्रयागराज की घटना के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के भी टारगेट पर हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने योगी पर प्रहार किए जा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब सनातन के ठेकेदार बनना चाह रहे हैं। विपक्षी दल सपा और कांग्रेस ब्राह्मणों में आक्रोश देखकर 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार और खुद की सरकार बनते देख रही है।

सपा व कांग्रेस की ब्राह्मण वोट पर नजर

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस खुलकर मैदान में उतरी हैं। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के सामने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई जिसमें भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया है। होर्डिंग में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मुलाकात की तस्वीर है। अजय राय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने नीचे बैठे हैं। जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को सनातन विरोधी बताते हुए अजय सिंह बिष्ट लिखा गया। होर्डिंग पर कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियां लिखी गई हैं-'जब नाश मनुज पर छाता है..पहले विवेक मर जाता है...।' इसके नीचे लिखा है 'सनातन विरोधी अजय सिंह बिष्ट' आगे लिखा है-'शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में।' स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को विरोधी दलों ने सनातन धर्म के सम्मान से जोड़ने कोशिश की है, सपा हो या कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में हैं। कांग्रेस के इस होर्डिंग को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जगदगुरू रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष पांडेय ने जब से यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है तब से ये विवाद और बढ़ गया है। क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब योगी के ही इशारे पर किया जा रहा है। हालांकि संत समाज चाहता है कि इस तरह के मामलों का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए, ताकि सनातन की बदनामी का सिलसिला रुक सके।

अभी तो ये भी पता नहीं है कि अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का दावा कितना सही है? क्योंकि ये केस भी कोर्ट में लम्बित है, लेकिन इतना साफ है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का व्यवहार किसी संत की गरिमा के अनुकूल नहीं है, वह खुलेआम राजनीति का खेल खेल रहे हैं। शायद इसलिए कोई भी संत समाज या अखाड़ा परिषद उनके साथ नहीं है।

अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बताते हैं। ये इस तरह का पहला मौका है कि खुद को शंकराचार्य कहने वाले किसी संत के खिलाफ इस तरह के घिनौने आरोपों में केस दर्ज हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, उनकी भूमिका भी पाक साफ नहीं है। आशुतोष बह्मचारी यूपी में शामली के रहने वाले हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि आशुतोष पुलिस रिकार्ड में पुराने हिस्ट्रीशीटर हैं। उनके खिलाफ संगीन आरोपों में बीस से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें सामूहिक बलात्कार, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और गौवध एक्ट के मामले शामिल हैं, लेकिन उन्हें किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ 24 जनवरी को प्रयागराज के झूंसी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद सहित पांच लोगों के खिलाफ दो बटुकों (नाबालिग शिष्यों) का यौन शोषण का आरोप लगाया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो आशुतोष ब्रह्मचारी याचिका और पीड़ित बटुकों को लेकर प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट पहुंच गए। जज ने कोर्टरूम को खाली कराकर दोनों बटुकों के बयान लिए, आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान दर्ज किया गया और उसके बाद कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस फाइल करने का आदेश दिया।

सपा के राज में पिटे थे अविमुक्तेश्वरानंद

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जांच में सहयोग करने के बजाये, गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर दी। जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं, जिन बटुकों के शोषण की बात कही जा रही है, वो उनके गुरूकुल के छात्र नहीं हैं। हालांकि पॉक्सो एक्ट में आरोपी की गिरफ्तारी पक्की होती है। चूंकि इस मामले में सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में पहुंच रहे हैं और एलान कर रहे हैं कि अगर पुलिस कोई एक्शन लेती है तो वो सड़कों पर उतरेंगे। अखिलेश यादव ने तो अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया। कहा कि योगी भगवा वस्त्र पहनकर विदेश दौरे पर गए हैं और उनके राज्य में एक शंकाराचार्य को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव के शासनकाल में इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद को वाराणसी पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा का लाठियों से पीटा था। उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराए गए थे। अविमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस की विचारधारा वाले संत माने जाते हैं। इसलिए वो राजनीतिक बयानबाजी करते रहते हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर भी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार का विरोध किया था। बहरहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप तो गंभीर हैं पर इनमें कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट तय करेगा। अभी तक तो ये भी पता नहीं है कि अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का दावा कितना सही है? क्योंकि ये केस भी कोर्ट के सामने लम्बित है। लेकिन इतना सही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का व्यवहार किसी संत की गरिमा के अनुकूल नहीं है। वह खुलेआम राजनीति का खेल खेल रहे हैं। शायद इसलिए ही कोई भी संत समाज, अखाड़ा परिषद, उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है।

- **लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के सामने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में होर्डिंग लगाई गई जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने नीचे बैठे हैं, होर्डिंग पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सनातन विरोधी बताते हुए अजय सिंह बिष्ट लिखा गया।**
- **कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुखिया अविमुक्तेश्वरानंद और योगी विवाद के बाद से सनातन के ठेकेदार बनना चाह रहे हैं, विपक्षी दल सपा और कांग्रेस ब्राह्मणों में आक्रोश देखकर 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार और खुद की सरकार बनते देख रही है।**

विवादित रहते हैं अविमुक्तेश्वरानंद

बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातनी पहचान और हिंदुओं की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन उनकी ये यात्रा विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रही है। इन्हीं लोगों में से एक कांग्रेस समर्थक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी हैं। वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर इतना भड़के कि उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम को सरकार का एजेंट करार दे दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बाबा बागेश्वर धाम की पद यात्रा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि धीरेंद्र शास्त्री नेताओं के मोहरे हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि लोगों को जातियों के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। अपनी खीज जाहिर करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि सनातन यात्रा में धीरेंद्र शास्त्री 'जात-पात की करो विदाई, हिंदू-हिंदू भाई-भाई' नारा लगा रहे हैं, जो एक राजनीतिक खेल है, जिसका सनातन धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे नारे को लेकर भी अविमुक्तेश्वरानंद ने बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को जातियों में नहीं बांटना चाहिए और एकमुश्त वोट देते रहना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि जाति ही हिंदुओं की पहचान है। अगर हमने जातिवाद को खत्म कर दिया तो हमारी खुद की पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हमेशा से कांग्रेस समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं। करीब चार माह पहले स्वामी गोविंदाचार्य सरस्वती ने उन्हें फर्जी बाबा करार दिया था। उस वक्त वाराणसी कोर्ट का आदेश दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि वाराणसी कोर्ट ने तो अविमुक्तेश्वरानंद को भगोड़ा घोषित किया था। अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ के नए शंकराचार्य के तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ताजपोशी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती का उत्तराधिकारी होने का झूठा दावा पेश किया था। स्वामी गोविंदानंद का कहना था कि उन्हें तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13 सितंबर 2022 को शंकराचार्य कहकर संबोधित किया था। ये वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के समय विरोध किया था।

वैश्विक

कूटनीति की अग्निपरीक्षा

पिछले छह माह से ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ाया है, 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय से दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, दोनों देशों को चेतावनी दी कि युद्ध नहीं रोका तो दोनों देशों के साथ अमेरिका व्यापार बंद कर देगा, युद्ध रुकवाने के दावे का शतक पूरा होने को है, 80 दफा इसे दोहराया जा चुका है।

भारत की कूटनीति भंवर में फंसी हुई है। दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। महाशक्तियों ने जिस तरह से दबंगई दिखाना शुरू कर दिया है, वह किसी भी देश के लिए आसान नहीं रह गया है। कूटनीति कम, दबंगई ज्यादा हो गई है। ऐसे हालात में अपने देश के हित साधना बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह करना छोड़ दिया है। वे सिर्फ 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मागा) के अभियान में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने टैरिफ युद्ध छेड़ दिया है। पिछले साल शुरू किया टैरिफ युद्ध अब अमेरिका को फिर से महान बनाने के अभियान 'मागा' से आगे निकलता दिख रहा है। अब यह इस मुकाम पर पहुंच गया है कि जो देश उनकी न माने उसे अंधाधुंध टैरिफ झेलना पड़ेगा। पिछले छह माह से ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय से ही दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया। उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी दी कि युद्ध नहीं रोका तो दोनों देशों के साथ अमेरिका व्यापार बंद कर देगा। युद्ध रुकवाने के दावे का अब शतक पूरा होने को है। कोई 80 दफा इसे दोहराया जा चुके हैं। ताजा दावा उन्होंने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 20 जनवरी को किया। ट्रंप के दावे से भारत कई बार असहज स्थिति में आ गया। शीर्ष नेतृत्व ने इस पर मौन बनाए रखा। राजनयिक स्तर पर मौन भी कई बार सीधा संदेश देता है। लेकिन एक सीमा के बाद संकेत देना पड़ता है। यह सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन, राजनीति में यह भी जरूरी नहीं होता कि शीर्ष नेतृत्व ही सामने आकर जवाब दे।

आलोक भदौरिया
विश्लेषक

व्यापार समझौता 8 माह से लंबित

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर या कोई अन्य कबीना मंत्री भी इसका खंडन कर सकते थे। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले रूस से क्रूड तेल खरीद बंद करने की भी पहली सूचना ट्रंप ने ही सोशल मीडिया एक्स पर दी। शुरुआत में इस पर लीपापोती की गई। तेल खरीद घटाने की सूचना आने लगी। बाद में निजी रिलायंस कंपनी के प्रेस नोट में साफ तौर पर बताया गया कि दिसंबर 2025 के बाद कोई भी तेल टैंकर नहीं आया है। अमेरिका की रणनीति साफ नजर रही थी। वह अपनी शर्तों के मुताबिक ट्रेड डीलआती दिख करना चाहता है। भारत से व्यापार समझौता वार्ता आठ माह से अधिक होने के बाद भी हो नहीं पाई है। इस बीच भारत ने एलएनजी के कुल आयात का दस फीसद अमेरिका से लेने की घोषणा कर दी। यही नहीं न्यूक्लियर संयंत्र में निजी भागेदारी का रास्ता भी खोल दिया गया है। दुर्घटना की स्थिति में निजी ऑपरेटर की जवाबदेही काफी हद तक कम कर दी गई। अमेरिका की रिएक्टर क्षेत्र में काफी दिलचस्पी है। कृषि सेक्टर पर उसकी निगाहें हैं। इसके बावजूद ट्रेड डील अब तक न होने का ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी के सिर फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को तब फोन कर लेते तो समझौता हो जाता। यह बेहद हास्यास्पद तर्क है। लेकिन, इससे भी बचकानी सफाई विदेश मंत्रालय ने दी। उसने सफाई दी कि पिछले साल मोदी और ट्रंप के बीच आठ दफा बातचीत हुई है। लेकिन, जिस अवधि की बात अमेरिकी प्रशासन कर रहा था, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। यह सही है कि भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर रोजगार कृषि क्षेत्र ही मुहैया कराता है। इसे अमेरिका के लिए खोलना भारत के किसानों और किसानी से जुड़े क्षेत्र के लिए बहुत घातक हो सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कई दफा यह दोहरा चुके हैं। वैसे पिछले कार्यकाल में भी पीयूष गोयल का मुखपत्र ऑर्गनाइजर में बयान छप चुका है कि कोई कंपनी अपने मुनाफे के लिए ही भारत में कारोबार कर रही है। उनका इशारा अमेजॉन की तरफ था। तो यह बयान कोई नया नहीं है। भारत सरकार का यह रुख हमेशा से रहा है। आसियान के साथ होने वाली रीजनल कंप्रेहैंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम (आरसीईपी) में भी भारत ने आखिरी क्षणों में अपने पैर खींच लिए थे। तब भी भारत के बाजारों को आसियान देशों के लिए पूरी तरह खोलने का मामला था। ऑस्ट्रेलिया दूध और दुग्ध पदार्थों के लिए भारत के बाजार को देख रहा था। लेकिन, तब और आज के दौर में एक फर्क है। भारत का रुख तब एकदम स्पष्ट था। सीधे तौर पर कृषि सेक्टर को खोलने के लिए मना कर दिया था और कहा भी था। अब इसके उलट स्थितियां हैं। अब हर बड़े मामले में चुप्पी बरती जा रही है। कहीं यह वजह तो नहीं है कि ट्रंप के हौसले इसलिए इस हद तक बढ़ चुके हैं? कि भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित करते वक्त बेड़ियां लगाई गई थीं। मेक्सिको जैसे छोटे देश ने भी इसकी कड़ी आलोचना की थी। लेकिन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना का विरोध जोरदार शब्दों में नहीं किया। इसके विपरीत दुनिया के तमाम देशों के शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं ने ट्रंप की बयानबाजी का सीधा जवाब दिया। मसलन, दावोस की बैठक में कनाडा के प्रधानमंत्री मॉर्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को आड़े हाथ लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैकरां ने भी स्पष्ट विरोध किया।

> **ट्रंप के पैतरों से निपटना वाकई कठिन है, वो कब, कौन सा बयान वह दे दें इसका अंदाज लगाना वाकई मुश्किल है, इसलिए मोदी सरकार ने भी हाल में संतुलन साधने की कोशिश की है, भारत एक तरफ चीन से व्यापारिक रिश्ते प्रगाढ़ कर रहा तो दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील पर बात हो रही है।**

ग्रीनलैंड पर ट्रंप का अड़ियल रुख

हालात इतनी तेजी से इस साल बदल रहे हैं कि अब तो 'नाटो' भी उनका (ट्रंप) निशाना बन रहा है। ताजा उदाहरण ग्रीनलैंड का लें। ट्रंप को यह चाहिए। वह खरीदने के लिए तैयार हैं। उनका तर्क लाजवाब है। यदि अमेरिका नहीं लेगा तो रूस और चीन इसे हथिया लेंगे। इससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। यूरोप के फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम देशों पर उन्होंने फिलहाल दस फीसद टैरिफ थोपने की घोषणा कर दी है। नाटो में शामिल देश न माने तो टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक अमेरिका की ही अगुआई को नाटो देश मानते आए हैं। लेकिन, पहली दफा इस तरह का बिखराव सामने आया है। ग्रीनलैंड को लेकर कमोबेश सभी यूरोपीय नेताओं ने खुलकर विरोध किया। शायद इस विरोध के मद्देनजर ट्रंप अपने कदम पीछे खींच लें। यूरोपीय यूनियन कमीशन की प्रेसीडेंट उर्सला वॉन डेर लेयेन ने खुलकर बयान दिया है कि अमेरिका के साथ होने वाला व्यापार समझौता फिलहाल टल गया है। यूरोपीय यूनियन के 27 में से 22 देश नाटो सदस्य हैं।

ट्रंप की धौंस

वेनेजुएला की घटना ने दुनिया को अचंभित कर दिया। किसी राष्ट्रपति का अमेरिका सेना द्वारा अपहरण पहली बार हुआ। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमार जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में ट्रंप का सुलूक भी हैरतअंगेज है। किसी राष्ट्रपति के साथ ऐसी बहस और वह भी टेलीविजन पर लोगों ने पहली बार देखी। किसी राजनयिक शिष्टाचार की परवाह नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार ऐसा किया। याद करें कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वार्ता जारी थी। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर दिए थे। इससे पहले इजरायल ने भी ईरान पर हमले कर डाले थे। ट्रंप के पैतरों से निपटना वाकई कठिन है। कब, कौन सा बयान वह दे दें इसका अंदाज लगाना कतई मुश्किल है। इसलिए मोदी सरकार ने भी हाल में संतुलन साधने की कोशिश की है। वे एक तरफ चीन से व्यापारिक रिश्ते प्रगाढ़ कर रहे हैं तो दूसरी ओर चीन का प्रतिनिधिमंडल भाजपा मुख्यालय में जाकर मिल रहा है। यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील करने की कगार पर है। कमिश्नर लेयेन तो पहले से ही इसे 'सभी व्यापार समझौतों में अव्वल' करार दे रही हैं। हालांकि रूस से तेल मंगाना लगभग बंद है। ईरान से पहले से ही तेल मामूली मात्रा में आयात किया जा रहा है। ब्रिक्स देशों के सैनिक अभ्यास में भारत का भाग न लेना भी चौंकाता है। तो अब रास्ता क्या बचा है? यह सही है कि राजनय में टाइमिंग का महत्व होता है। बोले शब्दों से ज्यादा कार्रवाई असर छोड़ती है। दुनिया के पटल पर छाई समस्याओं के लिए भारत की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन, भारत का मौन लंबा हो गया है। ट्रंप बार-बार नाम लेकर धौंसपट्टी जमा रहे हैं। लेकिन, इसकी काट क्या चुप्पी साधकर की जा सकती है? क्या इससे कोई रास्ता निकलेगा? बड़ा सवाल यही है। यह अग्निपरीक्षा का समय है। ●

> - **भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर रोजगार कृषि क्षेत्र ही मुहैया कराता है, इसे अमेरिका के लिए खोलना भारत के किसानों और किसानी से जुड़े क्षेत्र के लिए घातक हो सकता है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कई दफा यह दोहरा चुके हैं, पीयूष गोयल का ही बयान है कि कोई भी कंपनी अपने मुनाफे के लिए ही भारत में कारोबार करती है।**
> - **भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित करते वक्त बेड़ियां लगाई गई थीं, मेक्सिको जैसे छोटे देश ने भी इसकी कड़ी आलोचना की थी, लेकिन अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना का विरोध जोरदार शब्दों में नहीं किया।**

ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का बहिष्कार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी में शांति और इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' बनाने की घोषणा की है। इसका औपचारिक उद्घाटन हो गया। भारत, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन आदि 60 देशों को इसका सदस्य बनाने का न्यौता दिया गया था। सदस्य बनने के लिए एक अरब डॉलर देने हैं। ट्रंप आजीवन अध्यक्ष बने रहेंगे। उद्घाटन में भारत शामिल नहीं हुआ। न ही चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। बोर्ड ऑफ पीस को पहले संयुक्त राष्ट्र का विकल्प बनाने की कोशिश माना जा रहा था। बाद में ट्रंप ने ऐसा मान भी लिया। क्या भारत के इस कार्यक्रम में भाग न लेने का संदेश अमेरिकी प्रशासन ग्रहण करेगा?

कांग्रेस की गंदी व नंगी राजनीति

हैरानी की बात ये है कि भारत मंडपम में एआई समिट के खिलाफ आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत-अमेरिकन के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन था, तो क्या कांग्रेस ने चीन अथवा भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर भारत मंडपम के नंगा नाच किया? क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद भारत ही एआई के क्षेत्र में तीसरी बड़ी ताकत बनकर उभरा है।

डा.वीरेंद्र पुष्पक
वरिष्ठ पत्रकार

कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप ये मानते हैं कि देश पर राज करने का हक सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह की अराजकता पर उतरी है, जिस तरह की गंदी और नंगी राजनीति कर रही हैं, उससे तो सत्ता में वापसी मुश्किल लगती है। राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह संसद से लेकर सड़क तक उनका आचरण हैं उससे सत्ता भी उनसे दूर भाग रही है। जिस संसद में जनहित के फैसले होने चाहिए उस संसद को राहुल कांग्रेस हाइजैक कर लेती है। संसद की कार्यवाही बाधित की जाती है। संसद में जिस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग और व्यवहार विपक्ष, खासकर कांग्रेस द्वारा किया जाता है, उसे देश का हर कोना देखता है, सुनता है और समझता है और फिर समय आने पर देश अपने मताधिकार से जवाब देता है। फिर भी राहुल गांधी मान बैठे हैं कि वो देश के कानून, संविधान, संसदीय कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से ऊपर हैं। इसलिए राहुल कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता। जिस समय दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट में देश और विदेश के 100 मेहमान हिस्सा ले रहे थे उस समय यूथ कांग्रेस के नेताओं को भारत मंडपम में प्रदर्शन के लिए भेजा गया। जिन्होंने नंगा होकर (शर्ट लैस) प्रदर्शन किया, ताकि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों के सामने भारत की छवि धूमिल हो सके। हैरानी की बात ये है कि भारत मंडपम में एआई समिट के खिलाफ आंदोलन नहीं था बल्कि भारत-अमेरिकन के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन था। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल पैदा हो रहा है कि कांग्रेस ने क्या चीन अथवा भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर भारत मंडपम के नंगा नाच किया? क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद भारत ही एआई के क्षेत्र में तीसरी ताकत बनकर उभरा है। कांग्रेस की इस शर्मनाक हरकत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की एक रैली में जो प्रतिक्रिया दी वो कांग्रेस के लिए जलालत से कम नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक एआई समिट भारत का कार्यक्रम था। ये भाजपा का आयोजन नहीं था।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी में रहते हुए मोर्चा खोला है, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि अगर कांग्रेस के कर्ताधर्ता असहमति के स्वर का सामना नहीं कर सकते तो यह मुख्य विपक्षी दल के लिए 'विनाशकारी है' ऐसी कांग्रेस पार्टी को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।

नंगेपन से कांग्रेस के साथी भी हैरान

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा वैश्विक सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने भारत के वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। एआई समिट समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपको कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है। कांग्रेसियों ने वहां जो कुछ किया, वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से दिवालिया और दरिद्र हो गई है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट भाजपा का समारोह नहीं था। यह भारत का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। लेकिन, कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आज पूरे देश में कांग्रेस की थू-थू हो रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस तो संसद में अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देती। संसद को चलने नहीं देती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के साथी दलों को होता है। एआई समिट में कांग्रेस ने जो किया है, उससे साथी दल भी हैरान हैं। सबने इससे किनारा कर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि महिला सांसदों को भेज कर पीएम की सीट पर कब्जा करके आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। क्या कांग्रेसी इतने खोखले हो गए कि माताओं-बहनों को आगे कर रहे हो। कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। किंतु एक बात का मुझे संतोष है कि दिल्ली में भारत मंडपम में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं इसके लिए उनका सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस की आलोचना तक की है।

कांग्रेस एंटी इंडिया

भाजपा सांसद संबित पात्रा का सीधा आरोप है कि वैश्विक एआई समिट में बिना शर्ट के किया गया विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर रची गई एक सुनियोजित साजिश की हिस्सा थी, जिसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का सक्रिय परामर्श शामिल था। प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भागु चिब, राष्ट्रीय सचिव कृष्ण हरि, बिहार यूथ कांग्रेस के सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय कुमार, यूथ कांग्रेस नेशनल कोआडिनेटर नरसिम्हा यादव, ग्वालियर के जितेंद्र यादव सहित 11 यूथ कांग्रेस नेताओं को विशेष रूप से बुलाया गया था। इनमें से 8 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी प्रदर्शकारियों की तलाश की जा रही है। भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी गद्दार है। राहुल कांग्रेस देश को शर्मिंदा करने और उसकी छवि धूमिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इससे दो कदम आगे निकलते हुए कहा कि कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि उसके लिए एआई का मतलब एंटी-इंडिया है। यह आईएनसी (इंडियन नेशनल कांग्रेस) नहीं, बल्कि एएनसी (एंटी नेशनल कांग्रेस) हो गई है। क्योंकि एआई समिट में जहां एक तरफ बड़े-बड़े काम हुए, दुनिया में भारत का मान बढ़ा वहीं कांग्रेस ने एआई समिट पर काला दाग लगा दिया। पूरी प्लानिंग के साथ युवा कांग्रेस के नेता समिट में घुसे, कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट किया, मोदी और ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि रंग में भंग डालने वालों को वहां मौजूद आम लोगों ने ही दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। समिट में मौजूद टेक्नोक्रेट्स ने इसकी आलोचना की। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी के विरोध में इतनी अंधी हो गई है कि उसे ये भी नहीं दिखता कि उसकी करतूतों से देश की छवि पर क्या असर पड़ेगा?

देश का मूड नहीं समझ रही कांग्रेस

मैं जो चाहे वो कहूं मेरी मरजी, मैं चाहे जो करुं मेरी मरजी? राहुल गांधी की शायद यही रणनीति है। वो खुद और उनके दरबारी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते रहते हैं उससे कहीं बड़े तानाशाह तो कांग्रेस पार्टी में खुद राहुल गांधी बने हुए हैं, जिससे कांग्रेस खोखली हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सीनियर कांग्रेस लीडर ने राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी में रहते हुए मोर्चा खोला है। ये सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के लिए कर्ताधर्ता असहमति के स्वर का सामना नहीं कर सकते तो यह मुख्य विपक्षी दल के लिए 'विनाशकारी है'। ऐसी कांग्रेस पार्टी को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद मणिशंकर अय्यर ने अपने यूट्यूब चैनल पर 23 मिनट 10 सेकेंड का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय कांग्रेस में असहमति का सम्मान होने की बात कही। अय्यर का कहना है कि जब इंदिरा गांधी असहमति के कारण पार्टी तोड़कर अलग हुई और आपातकाल लगाया तो परिणाम क्या निकला? सबने देखा, कांग्रेस न सिर्फ हारी, बल्कि इंदिरा रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से हार गए थे। कांग्रेस का हर चुनाव में पतन हो रहा है। फिर भी राहुल गांधी देश का मूड नहीं समझ पा रहे हैं।

- **युवा कांग्रेस के नेता वैश्विक एआई समिट में घुसे, कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट किया, मोदी और ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए, हालांकि रंग में भंग डालने वालों को वहां मौजूद आम लोगों ने ही दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया, यानी जनता के बीच कांग्रेस ये दुर्गति हो गई है।**
- **कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने भारत के वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया, एआई समिट समारोह में विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपको कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी, कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है।**

राहुल ने खोखली कर दी कांग्रेस

सत्ता से बेदखल होने के बाद से राहुल गांधी की तानाशाही की वजह से कांग्रेस लगातार खोखली होती आ रही है। 11 वर्षों में कांग्रेस के वरिष्ठ साथी कांग्रेस का हाथ छोड़ गए। इनमें असम के हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने 2015 में भाजपा का दामन थामा, तब से नार्थ ईस्ट में भाजपा जहां मजबूत होती गई और वहीं कांग्रेस धीरे-धीरे हाशिए पर जाती रही। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च, 2020 में कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने न सिर्फ पार्टी से त्यागपत्र दिया था, बल्कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार भी गिरा दी थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से सांसद जितिन प्रसाद भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। उन्होंने 2021 में भाजपा का दामन थामा। वर्तमान में वो मोदी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नवंबर, 2021 में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। अब वो भाजपा का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस पार्टी को मई, 2022 में छोड़ दिया था। वर्तमान में वह समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा के सदस्य हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस की कार्यशैली और नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए अगस्त, 2022 में कांग्रेस से छोड़ गए। जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवरा भी कांग्रेस छोड़कर जनवरी, 2024 में शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल हो गए। वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह जनवरी 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मई 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हार्दिक ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व गंभीर नहीं है।

रेलवे की भूमि से हटेगा अतिक्रमण

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाना होगा, क्योंकि यह सरकारी संपत्ति है और रेलवे को इसका उपयोग करने का पूरा अधिकार है, नैनीताल हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

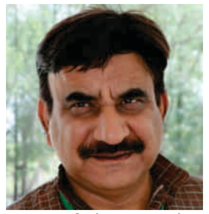

दिनेश मानसेरा
वरिष्ठ पत्रकार

24 फरवरी को बहुचर्चित हल्द्वानी के बनभूलपुरा के भविष्य का फैसला लगभग हो ही गया। रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाले करीब 5000 परिवारों को सुप्रीम कोर्ट ने बेदखल करने का फैसला सुना दिया है। क्योंकि अतिक्रमणकारी हल्द्वानी में रेलवे विस्तार में बाधा बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे की भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को उसी स्थान पर पुनर्वास की जिद करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपिन पंचोली की पीठ ने साफ-साफ टिप्पणी की कि जिन लोगों ने भूमि पर अतिक्रमण किया है, वो रेलवे पर शर्तें नहीं थोप सकते। न ही रेलवे को ये बता सकते कि जमीन का कैसे उपयोग किया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाना होगा, क्योंकि यह सरकारी संपत्ति है और रेलवे को इसका उपयोग करने का पूरा अधिकार है। नैनीताल हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से लगभग 50,000 लोगों को हटाने का आदेश दिया था, जिस पर जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया कि अतिक्रमणकारियों को रेलवे की जमीन पर रहने का कानूनी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला लंबे समय से चल रहा है। रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर जमीन पर बनभूलपुरा, गफूर बस्ती, इंदिरानगर और अन्य मोहल्लों में हजारों अवैध निर्माण बने हुए हैं, जहां अनुमानित 5,000 से अधिक परिवार (करीब 50,000 लोग) रहते हैं। रेलवे का कहना है कि ट्रैक विस्तार और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए इस जमीन की उसे सख्त जरूरत है। खासकर गौला नदी के कारण मौजूदा ट्रैक में दिक्कत आ रही है। यह इलाका रेलवे विस्तार के लिए उत्तराखंड में आखिरी संभावित जगह है, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाता है। जबकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यहां 50,000 लोग दशकों से रह रहे हैं, कई पट्टे वाली जमीन पर बसे हैं और रेलवे ने पहले कभी इस जमीन की मांग नहीं की है।

अफवाहें फैलती रहती हैं

जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में 2023 से 2026 तक जारी है। इस बीच राजनीतिक तौर पर कहा गया कि यहां 50 हजार लोगों को हटाया जाएगा, जबकि यहां से सवा चार हजार छोटे झोपड़ी नुमा और कुछ पक्के मकानों को ही हाई कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा माना था और इसकी पैमाईश करीब 29 एकड़ निकली थी। ये वो जमीन है जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी हुई है और रेलवे यहां अपने स्टेशन का विस्तार करना चाहता है। रेलवे ने अपनी लाइन से पंद्रह मीटर तक सीमांकन करते हुए करीब दो किलोमीटर तक अपने खंभे लगाए थे। जिसके बाद बनभूलपुरा क्षेत्र में हंगामा हुआ था। अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों के घरों को उजाड़ने की साजिश हो रही है जबकि सीमांकन में हिंदू-मुसलमान दोनों के घर थे। लेकिन सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया गया कि केवल मुस्लिम आबादी को ही हटाया जाएगा। उत्तराखंड में हल्द्वानी का ये इलाका सबसे ज्यादा अपराधिक क्षेत्र वाला माना जाता है, जहां बाहरी राज्यों से आए अपराधी पनाह लेते हैं। इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती थी।

कब और कैसे बस बनभूलपुरा

बनभूलपुरा कैसे बसा? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के सामने ही दूसरी तरफ रेलवे पटरी के बाद गौला नदी बहती है जिसमें से रेता बजरी पत्थर का खनन होता है। अंग्रेजी शासन काल से लेकर 70 के दशक तक रेलवे अपनी नई पुरानी परियोजनाओं के लिए पत्थर तुड़वा कर गिट्टी को इसी गौला नदी से लेता था, यहां जो ठेकेदार पत्थर तोड़ने का ठेका लेते थे वो रामपुर, बहेड़ी, बरेली, मुरादाबाद, स्वार-टांडा आदि से सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम मजदूर लेकर आए जिनसे वे पत्थर तुड़वाकर माल गाड़ी में गिट्टी भरवाते थे। ये मजदूर यहीं रेल पटरी किनारे झोपड़ी डाल कर रहने लगे। उस समय रेलवे ने भी इन्हें नहीं रोका क्योंकि ये रेलवे के लिए ही गिट्टी तोड़ने का काम कर रहे थे। दशकों तक ये पत्थर तोड़ने का काम करते रहे। इनके बच्चे भी यहीं हुए और वो भी इस काम के साथ गौला नदी से रेता बजरी चुरा कर घोड़ा बुग्गी से ढोकर शहर में बिक्री करने लगे। धीरे-धीरे इनकी झोपड़ियां पक्के घरों के रूप में तब्दील होती गई और अब रेलवे को अपनी नए रेल परियोजना के विस्तार पर काम करना था तो मंत्रालय को होश आया कि ये बनभूलपुरा क्षेत्र तो हमारी जमीन पर बसा हुआ है। यहां रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण है। अवैध कब्जे का ये मामला इज्जतनगर रेलवे अधिकारियों की अदालत से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा।

रेलवे पटरी के किनारे ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, नई बस्ती और इंद्रानगर बनभूलपुरा क्षेत्र के वो मोहल्ले हैं, जिन्हें भूल भुलैय्या भी कहा जाता है, इन इलाकों में पुलिस कर्मियों को भी जाने में दस बार सोचना पड़ता है, यहां थाने की पोस्टिंग से पुलिसकर्मी भी कतराते हैं, हिम्मत वाले और बलिष्ठ पुलिस कर्मियों की ही यहां तैनाती की जाती है।

हर अपराध होता है रेल पटरी के किनारे

इसी बनभूलपुरा में रेलवे की पटरी के किनारे घोड़ा बुग्गी वाले भी रहते है जो दिन-रात गौला नदी से अवैध खनन कर उत्तराखंड के वन विभाग के राजस्व को नुकसान पहुंचाते रहे है। इनकी संख्या एक दो नहीं बल्कि हजारों में है। इन्हीं में से कुछ लोग अब रेता बजरी चोरी करके डंपर और कुछ जेसीबी के मालिक बन बैठे हैं। यहां गौला नदी से चोरी का माल निकालने वाले ही अपना गैंग चलाते है। कई बार यहां रेता-बजरी स्टॉक करने को लेकर गैंगवार भी हुई है। गौला नदी से रेता बजरी चोरी करने वालों को वन विभाग या पुलिस विभाग भी पकड़ नहीं पाता। यदि कोई हाथ लग भी गया तो उनके राजनीतिक आका उन्हें छुड़ा लेते हैं। रेलवे पटरी के किनारे ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, नई बस्ती और इंद्रानगर बनभूलपुरा क्षेत्र के वो मोहल्ले हैं, जिन्हें भूल भुलैय्या भी कहा जाता है, इन इलाकों में पुलिस कर्मियों को भी जाने में दस बार सोचना पड़ता है। यहां थाने की पोस्टिंग से पुलिस कर्मी भी कतराते हैं, हिम्मत वाले और बलिष्ठ पुलिस कर्मियों की ही यहां तैनाती की जाती है। बनभूलपुरा वो इलाका है जहां राज्य का सबसे ज्यादा नशे का कारोबार होता है, बरेली से आने वाले स्मैक तस्कर यहां डेरा डाले रहते हैं। ट्रेन और बाइक पर आने वाले ड्रग के करियर यहां डिलीवरी देते है। चरस गांजा की खरीद फरोख्त का धंधा यहां बरसों से चलता रहा है।

लकड़ी की तस्करी

लंबे समय तक बनभूलपुरा क्षेत्र, चोरी की इमारती लकड़ी के लिए भी मशहूर रहा है, गौला नदी के पार जंगल से पेड़ों को काटकर, इमारती लकड़ी को घोड़ों पर लादकर यहां बनभूलपुरा क्षेत्र में छिपाया जाता था, यहां रहने वाले करीब तीन सौ से ज्यादा बढ़ई इस चोरी की लकड़ी को रातों रात चीर कर उनका साइज बनाकर उसे ठिकाने लगा देते थे।

- **ब्रिटिश काल से लेकर 70 के दशक तक रेलवे अपनी परियोजनाओं के लिए पत्थर तुड़वा कर गिट्टी को हल्द्वानी की गौला नदी से लेता था, यहां जो ठेकेदार पत्थर तोड़ने का ठेका लेते थे वो रामपुर, बहेड़ी, बरेली, मुरादाबाद आदि से सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम मजदूर लेकर आए जिनसे वे पत्थर तुड़वाकर माल गाड़ी में गिट्टी भरवाते थे।**
- **बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर अफवाह फैलाई जाती रही है कि मुसलमानों के घरों को उजाड़ने की साजिश हो रही है जबकि सीमांकन में हिंदू-मुसलमान दोनों के घर अतिक्रमण के दायरे में हैं लेकिन सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया जाता है कि केवल मुस्लिम आबादी को ही हटाया जाएगा।**

वन विभाग भी चीरी हुई लकड़ी को अपना नहीं बता पाता था। हल्द्वानी और आसपास जितने मकान रोज बनते हैं उसमें लगने वाली लकड़ी का दस प्रतिशत भी वन निगम से नहीं खरीदा जाता था। यानी सभी जगह चोरी की लकड़ी खपाई जाती थी। यूपी, बिहार यहां तक कि दिल्ली से लेकर कई अन्य राज्यों के अपराधी फरारी काटने के लिए इसी इलाके में शरण लेते है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में यदि कोई चोरी लूट की वारदात होती है तो पुलिस सबसे पहले अपराधी को बनभूलपुरा में ही खोजती है। उत्तराखंड पुलिस के हर शहर की कोतवाली और थाना क्षेत्र की फोटो डायरी में और अब कंप्यूटर रिकार्ड में बनभूलपुरा इलाके के अपराधियों के फोटो अवश्य मिलेंगे, ट्रेन में, शहरों में मोबाइल, पर्स, बैग, कुंडल, गले की चैन, छीना झपटी करने वालों के आश्रय स्थल के रूप में बनभूलपुरा क्षेत्र सबसे सुरक्षित माना जाता है। हल्द्वानी में जितने भी बदमाश पनपे वो बनभूलपुरा इलाके में पनपे और इन सभी का यहां के छोटे-छोटे अपराधियों को संरक्षण देने में भूमिका रही है। इनमें से ही कुछ तो बाद में यहां के पार्षद तक बन गए। निसंदेह इन पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का संरक्षण इसलिए भी रहा क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी थी जो इन पार्टियों का वोट बैंक है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहां के मुस्लिमों को इसी बात का डर दिखाती रही है कि भाजपा आएगी तो बनभूलपुरा को उजाड़ देगी। यहां के छोटे से बड़े अपराधियों को भी राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है और यही वजह है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से इन्हीं दोनों दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के मुद्दे की खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर पैरवी की है।

बनभूलपुरा ने रोका आईएसबीटी निर्माण

कांग्रेस शासन काल में गौला नदी पार स्टेडियम के करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से आईएसबीटी बनाया जाना था, वन विभाग से जमीन ट्रांसफर हो गई थी। लेकिन भाजपा सरकार आई तो स्थानीय लोगों ने इस आईएसबीटी का विरोध किया इसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि हिंदू समाज के लोगों को आईएसबीटी से बस पकड़ने के लिए इसी बनभूलपुरा बस्ती से होकर गुजरना पड़ता, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था या फिर लोगों को काठगोदाम अथवा तीनपानी से आना पड़ता जिसमें समय और पैसा अधिक लगता। बनभूलपुरा में अपराधी दिन रात सक्रिय रहते हैं आलम ये है कि इस इलाके में स्थानीय मुस्लिम महिलाएं तक बेपर्दा होकर निकलने में असहज रहती है। हिंदू महिलाओं को यहां जाना असुरक्षा महसूस कराता है। इसलिए भाजपा सरकार ने जन भावना को देखते हुए आईएसबीटी पर काम रुकवा दिया। यही नहीं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी लोगों को बदबूदार ढोलक-गफूर बस्ती से होकर गुजरना पड़ता है, रिक्शा से पीछे से उठाईगीर सामान निकाल कर भाग जाते है, स्टेशन परिसर में इन्हीं उठाईगिरों को पुलिस दौड़ाती रहती है। स्टेशन के बाहर यात्रियों के साथ जो व्यवहार होता है वो बयान करने लायक नहीं है। कुल मिलाकर रेलवे अतिक्रमण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिए कि अतिक्रमणकारियों को अवैध कब्जा तो छोड़ना ही होगा। यहां सिर्फ उन्हीं परिवारों को पीएम आवास योजना या सीएम आवास योजना के तहत आवास मिलेंगे तो इसके लिए पात्र होंगे। हालांकि बनभूलपुरा के सक्षम और संपन्न परिवारों ने अपने लिए नया ठिकाना (घर) बना लिया है। जो परिवार किराये के घर में रह रहे हैं वो नया घर तलाश रहे हैं। ●

सौदा इजराइल से सदमा पाकिस्तान में

पाकिस्तान पर नजर रखने वालों का कहना है कि नेतन्याहू के खिलाफ पाकिस्तान ने प्रस्ताव इसलिए पास किया क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि भारत-इजरायल और दूसरे देशों के बीच तालमेल इलाके की शांति और दुनिया भर में स्थिरता के लिए खतरा बनेगा, इजरायल पर मुस्लिम-बहुल देशों को अलग-थलग करने के मकसद से गुट बनाने का भी आरोप है।

केके चौहान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को इजराइल पहुंचे तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वैलकम किया। खुद नेतन्याहू पत्नी के साथ स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। नरेंद्र मोदी की पीएम के रूप में इजराइल की यह दूसरी यात्रा है। पहली बार 2017 में पीएम मोदी की इजराइल यात्रा ने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दी थी। क्योंकि इससे पहले किसी भी भारतीय पीएम ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। लिहाजा पीएम मोदी की इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि इजरायल में पीएम नरेंद्र मोदी के ग्रैंड स्वागत की तैयारियों की एक झलक इजरायल के मशहूर अखबार 'द जेरूसलम पोस्ट' के फ्रंट पेज पर दिखाई दी, जिसमें पीएम मोदी के स्वागत में पूरा का पूरा स्पेशल एडिशन निकाल दिया गया। अखबार के फ्रंट पेज पर बड़े-बड़े अक्षरों में 'नमस्ते' लिखा गया। यह सिर्फ एक दौरा नहीं है, बल्कि दो पुरानी सभ्यताओं के बीच दोस्ती का एक नया और सुनहरा अध्याय है, जो रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नेसेट स्पीकर अमीर ओहाना ने इजराइली संसद में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद उन्हें 'पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित किया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी यह पदक प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह कनेसट का सर्वोच्च सम्मान है। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत नेतृत्व के माध्यम से किए गए असाधारण योगदान के लिए यह मेडल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा विश्व नेताओं में से हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों ने सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर प्रदान किया गया था, जो विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च फिलिस्तीनी सम्मान है।

इजराइल से रक्षा क्षेत्र में समझौते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते और डील्स पर चर्चा हुई है। यह डील्स दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने वाली है। मुख्य फोकस डिफेंस को-ऑपरेशन पर रहा, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और उन्नत हथियार सिस्टम शामिल हैं। दोनों देशों के बीच 2026 में 8-10 अरब डॉलर तक की डिफेंस डील्स संभव हैं। इनमें इजराइल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है। यह 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत में लोकल प्रोडक्शन के लिए है, जो छोटी दूरी के रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन से बचाव करता है। साथ ही आयरन बीम (लेजर-बेस्ड), डेविड्स स्लिंग और एरो जैसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर एमओयू हुआ है। हर्मीस ड्रोन, हैरोन एमके-2 एमएएलई ड्रोन (जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग), एसपीआईसीई 1000 प्रिसीजन गाइडेड बम, रैम्पेज एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल, आइस ब्रेकर नेवल क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक एयर लोरा मिसाइल जैसी सिस्टम्स पर डील्स भी पक्की है। यह डील डायरेक्ट खरीद से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन पर फोकस है। काउंटर-ड्रोन टेक्नोलॉजी, लेजर सिस्टम, एआई क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर 17 एमओयू साइन हुए हैं। यह डील्स भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगी, क्योंकि इजराइल भारत का प्रमुख डिफेंस पार्टनर है (भारत इजराइल से हथियारों का 34 प्रतिशत खरीदता है)। आयरन डोम रक्षा प्रणाली रॉकेट और मिसाइल रोकती है। कम दूरी की मिसाइलों को लक्ष्य बनाती है। रेडार से रॉकेट को ट्रैक करती है। कंप्यूटर तुरंत अनुमान लगाते हैं। कहां गिरेगा, कितना नुकसान होगा। जो रॉकेट आबादी वाले क्षेत्र की ओर हों, उन्हीं को निशाना बनाकर मार गिराया जाता है, इससे अनावश्यक खर्च भी बचता है, आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ती है। दुनिया ने यह अनोखा मॉडल देखा है। बहुत से देश इससे सीख रहे हैं, यह आज हवाई सुरक्षा का नया मानक बन चुका है।

भारत-इजराइल संबंध मजबूत

पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए है। भारत-इजरायल के बीच इस दोस्ती को देखकर पाकिस्तान को जोर का झटका लगा है। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और दूसरे देशों के साथ क्षेत्रीय गठबंधन बनाने के बारे में बताया, जिसका नाम हेक्सागन अलायंस होगा। पाकिस्तान को पीएम नेतन्याहू की ये बात चुभ रही है। तभी तो पाकिस्तान ने इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। भारत और इजरायल रक्षा, व्यापार और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। भारत और इजरायल ने एक सुरक्षा एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया है जो भारत में हथियार की व्यवस्था को एक साथ विकसित करने पर फोकस है। यह समझौता आयरन डोम को भारत में इजरायल के सहयोग से विकसित करने पर हुआ है। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच भरोसे ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और इजरायल के बीच संबंध में मजबूती पाकिस्तान के परेशान और डरे होने की वजह है। 17 जून, 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान, भारतीय एयर फोर्स के मिराज-2000 ने द्रास और बटालिक सेक्टर में पाकिस्तान के घुसपैठियों को टारगेट किया था। कारगिल में लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल कर टारगेट पर निशाना लगाया गया था। इसके लिए भारतीय मिराज पर इजरायली लाइटनिंग पॉड्स का इस्तेमाल किया गया था। बालाकोट में ऑपरेशन बंदर और ऑपरेशन सिंदूर दोनों के दौरान भी दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की मजबूती देखी गई थी। भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को उड़ाने के लिए इजरायली लोइटरिंग एम्युनिशन, लेजर गाइडेड बम और गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। कारगिल युद्ध के दिनों से, भारत हेरॉन-टीओ और सर्चर मार्क 11 जैसे इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है।

इजराइल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है, यह 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत में लोकल प्रोडक्शन के लिए है, जो छोटी दूरी के रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन से बचाव करता है, साथ ही आयरन बीम (लेजर-बेस्ड), डेविड्स स्लिंग और एरो जैसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर एमओयू हुआ है।

पाकिस्तान में बेचैनी

भारत में हथियार विकसित करने के लिए दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर करने से पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान पर नजर रखने वालों का कहना है कि इसलिए नेतन्याहू के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में भारत-इजरायल और दूसरे देशों के बीच तालमेल को इलाके की शांति और दुनिया भर में स्थिरता के लिए खतरा बताया गया। इजरायल पर मुस्लिम-बहुल देशों को अलग-थलग करने के मकसद से गुट बनाने का आरोप है। भारत और इजरायल के बीच नजदीकी ना केवल पाकिस्तानी संसद, बल्कि वहां की मीडिया के प्राइम टाइम में भी चर्चा का विषय रहा। पाकिस्तान मीडिया में पाक-चीन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद और पूर्व डिप्लोमैट मलीहा लोधी ने दोनों देशों के बीच इस साझेदारी की आलोचना की। उनका कहना है कि इस गठबंधन का मकसद चीन और पाकिस्तान को तोड़ना है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि भारत-इजरायल साझेदारी मुस्लिम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी है। पाकिस्तान एक तरफ तो भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी की आलोचना करता है, वहीं दूसरी तरफ हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है। इससे पाकिस्तान का दोगलापन सामने आता है। भारत की इजरायल और रूस जैसे दूसरे देशों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप है, लेकिन उसने कभी भी हथियारों या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमलावर की तरह नहीं किया है। रक्षा साझेदारी का मकसद पाकिस्तान वाले अस्थिर इलाके में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दूसरे देशों के साथ अपनी रक्षा साझेदारी का इस्तेमाल हमलावर की भूमिका निभाने के लिए किया है। इजरायल में पीएम मोदी का जैसा स्वागत हुआ और दोनों देशों ने जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उससे पाकिस्तान चिंतित है क्योंकि वह पश्चिम एशिया में बड़े वैश्विक राजनीतिक बदलावों को लेकर आशंकित है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान रणनीतिक भारत-इजरायल साझेदारी से नाखुश है। हालांकि, उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इजरायल भारत का मुख्य डिफेंस सप्लायर बनकर उभर रहा है। भारत ने हमेशा कहा है कि इजरायल के साथ उसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और आपसी फायदे पर आधारित है।

- **पाकिस्तान एक तरफ तो भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी की आलोचना करता है, वहीं दूसरी तरफ हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है, इससे पाक का दोगलापन सामने आता है, भारत की इजरायल और रूस जैसे दूसरे देशों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप है, लेकिन उसने कभी हथियारों का इस्तेमाल हमलावर की तरह नहीं किया है।**
- **प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा विश्व नेताओं में से एक हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों ने सर्वोच्च पुरस्कार दिया है, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन ने राज्य का ग्रैंड कॉलर प्रदान किया गया था, जो विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च फिलिस्तीनी सम्मान है।**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल और भारत की साझा प्रेस कांफ्रेंस में साफ कहा कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में, आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे-से-कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है कि मानवता को कभी भी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। गाजा शांति योजना से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी आत्मीयता और गर्मजोशी ने मेरी यात्रा को यादगार बना दिया है। मैं एक बार फिर आपसे और इजराइल के लोगों से जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, जो सम्मान मिला है, इसके के लिए हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

क्या दिल्ली में रहेगा शिवराज का ठिकाना

मामा का मध्य प्रदेश से मोह नहीं छूटा, उनकी चालें, मुस्कानें और मुलाकातें साफ कह रही थीं कि उनका दिल अब भी मध्य प्रदेश की धरती के लिए धड़कता है, धड़के भी क्यों ना? जहां जन्म लिया, जहां से राजनीति का ककहरा सीखा और फिर 20 साल सत्ता के मुखिया रहे, दिल धड़कना तो लाजिमी ही है।

आलोक एम इंदौरिया
विश्लेषक, स्तंभकार

भारतीय जनता पार्टी की देश के बड़े नेताओं की सूची में शुमार और मोदी सरकार में कैबिनेट में देश की खेती किसानी संभालने वाले, यानी कृषि विभाग के काबीना मंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्हें सारे देश में मामा के नाम से ज्यादा जाना जाता है को लगता है, अब दिल्ली भा गई है। क्या दिल्ली उनका मुस्तकिल ठिकाना बनने जा रहा है? यह इसलिए कि विगत एक साल से उन्होंने जिस धुआंधार तरीके से मध्य प्रदेश को नापा था उससे तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनका मध्य प्रदेश से मोह नहीं छूटा है। उनकी चालें, मुस्कानें और मुलाकातें साफ कह रही थीं कि उनका दिल अब भी मध्य प्रदेश की धरती के लिए धड़कता है। धड़के भी क्यों ना? जहां जन्म लिया, जहां से राजनीति का ककहरा सीखा और फिर 20 साल सत्ता के मुखिया रहे। दिल धड़कना तो लाजिमी है लेकिन आदिवासियों के हक की आवाज हो, किसान सभा हो या उनकी पदयात्रा राजनीति के जानकार बताते हैं कि सीहोर से इंदौर तक उनकी मौजूदगी केवल सरकारी दौरे नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक पटकथा का संकेत लगती हैं। मगर हालिया देशव्यापी दौरे और उन दौरों में खासकर तमिलनाडु में इशारों ही इशारों में किए गए संकेतों से राजनीतिक हल्कों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि मामा शिवराज सिंह चौहान अब भोपाल नहीं बल्कि दिल्ली में ही अपनी राजनीतिक धूनी रमाएंगे। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के चर्चित भाजपा नेताओं में गिने जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी कैबिनेट के सितारे शिवराज सिंह चौहान को देश में भला कौन नहीं जानता है? 6 बार विधायक और 6 बार सांसद रहे शिवराज सिंह चौहान को सुर्खियों में बने रहना आता है और वह राजनीतिक चौपाल में अक्सर बहस का मुद्दा बने रहते हैं। भाजपा सरकार में चार बार मुख्यमंत्री बने रहने का खिताब भी सिर्फ उन्हीं के नाम दर्ज है और बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने 17 साल से अधिक सरकार चलाई है।

मामा की इंट्री एबीवीपी से

राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के रास्ते से दाखिल होने वाले शिवराज सिंह चौहान युवा मोर्चा और उसके बाद भाजपा की दहलीज पर आए। तकरीबन 40 साल से अधिक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने प्रदेश के साथ-साथ देश की राजनीति में खासा मुकाम बना लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने राजनीति में अपनी शानदार ब्रांडिंग की और वह मामा के उपनाम से सारे देश में जाने-जाने लगे। उनके द्वारा चलाई गई लाड़ली लक्ष्मी और लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की चार दीवारी से निकलकर सारे देश में फैल गई और भाजपा तो छोड़िए गैर भाजपा सरकारों ने भी इसका नाम बदलकर इसे अपने-अपने राज्यों में चलाना शुरू कर दिया। लगभग 17 साल से अधिक के शासन में उन्होंने मध्य प्रदेश के हर जिले और तहसील स्तर तक अपना बहुत मजबूत नेटवर्क स्थापित कर लिया। यानी कांग्रेस के दिग्गी राजा के बाद भाजपा के मामा एकमात्र ऐसे नेता है जिनका सारे प्रदेश में न केवल जबरदस्त नेटवर्क है बल्कि हर क्षेत्र में उनके समर्थक भी है।

शिवराज के राज में बंपर जीत

2023 के विधानसभा चुनाव के बाद आलाकमान ने मध्य प्रदेश का निजाम बदल डाला और मोहन यादव के हाथों में मध्य प्रदेश का निजाम सौंप दिया गया। उनकी निजामत सारे प्रदेश में काबिज हो गई। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बंपर सफलता दिलवाने में शिवराज के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेहद अहम भूमिका रही है इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ठीक जिस तरह लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एकदम नए नवेले मुख्यमंत्री होने के बाद भी उल्लेखनीय भूमिका रही थी। खैर मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने वाले मामा बेशक दिल्ली चले गए हो, कैबिनेट में खेती किसानी कर रहे हो, मगर उनका दिल मध्य प्रदेश में ही रहता था। शायद इसी के चलते किसी आशा में उनकी आमदरफ्त और मूवमेंट मध्य प्रदेश में विगत एक वर्ष में ज्यादा ही बढ़ गया था। इसके कारण कई बार प्रदेश में असहजता की स्थिति निर्मित होती थी और मुख्यमंत्री के आसान हिलने की खबरें भी राजनीतिक हल्कों में अक्सर घूमती रहती थी। यह बात अलहदा है कि मोहन यादव को आलाकमान ने इस प्रदेश का निजाम थमाया था जिसके कारण उनकी राजनीतिक सेहत पर फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मध्य प्रदेश के भाजपाई कबीले में एक तरह से राजनीतिक हलचल तो मची ही रहती थी।

पुराने नेता मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं

यह सही है कि शिवराज नागपुर के बेहद निकट हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम सुर्खियों में बना रहा था। मगर अचानक दूसरे नाम पर मोहर लग गई और नितिन नवीन भाजपा के नवीन अध्यक्ष बन गए। इसके साथ ही सकल भाजपा की धारा पूरी तरह से बदल गई। आलाकमान के द्वारा जिस तरह से नई पीढ़ी को आगे लाने वाली लाइन पर काम शुरू किया गया और पुराने को मार्गदर्शक की भूमिका में डाला जा रहा है उसके चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अपेक्षाकृत युवा और नए चेहरे को बनाया। संभावनाएं ऐसी भी व्यक्त की जा रही है कि इस कड़ी में निकट भविष्य में तमाम पुराने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है। इसके कारण तमाम नेताओं ने अपनी राजनीति में परिवर्तन किया है। संभव है इसी के चलते शिवराज ने यह तय किया होगा कि वे अब अपनी राजनीति का केंद्र मध्य प्रदेश की जगह फाइनली दिल्ली ही बनाएं और वहीं सक्रिय रहकर देश की राजनीति करें। क्योंकि उनकी मध्य प्रदेश में सक्रियता के राजनीतिक मायने यही निकाले जाते हैं कि उनका प्रदेश से मोह छूट नहीं रहा। यदि लगातार इस प्रकार की खबरें आलाकमान तक पहुंचेंगी तो संभव है यह उनके राजनीतिक करियर के लिए जोखिम भरा हो सकता है। शायद इसी कारण इशारों ही इशारों में उन्होंने हाल ही में तमिलनाडु में महिलाओं की सभा में कहा था की मामा का घर दिल्ली में है जबकि हकीकत में मामा का घर मध्य प्रदेश के भोपाल में है। संभव है मामा का यह बयान एक भावुक अपील हो, मगर गहराई से सोचें तो यह राज्य की राजनीति से कथित दूरी का प्रतीक बन गया या फिर बना दिया गया।

मोहन यादव ही अब एमपी का चेहरा

बरहाल शिवराज के इस बयान के इन दिनों निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे उनके निकट भविष्य में राज्य से दूरी और केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहने से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने एक कृषि मंत्री के रूप में जिस तरह से सारे देश को नापा है और मोदी सरकार से सीधे किसानों को जोड़ने का काम किया है वह उल्लेखनीय है। उनकी इस सक्रियता के मायने भी यही निकाले जा रहे हैं कि वह अब दिल्ली में ही स्थाई ठिकाना बनाएं रखेंगे। इधर मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने थाम रखा है उससे प्रदेश की राजनीति में किसी को कुछ करने के लिए ज्यादा बचा नहीं है। वैसे भी भाजपा एक सेट पैटर्न पर चलती है। यह सही है कि एक समय शिवराज इस मध्य प्रदेश का एकमात्र चेहरा हुआ करते थे मगर बदलते दौर की राजनीति में अब मोहन यादव ही मध्य प्रदेश का एकमात्र चेहरा है और मध्य प्रदेश की राजनीति में यह स्वीकार लिया गया है। यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान की ओर से कोई चुनौती आने की संभावना अब नहीं है। अगर भाजपा का ट्रेंड देखें तो यह बात समझ आ जाएगी कि जब भाजपा शिवराज सिंह चौहान को लेकर आई थी, तब उमा भारती हर दृष्टि से मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी नेता थीं। लेकिन तब भी शिवराज सिंह चौहान को लाया गया था। मोहन यादव को भाजपा के पीढ़ी परिवर्तन सिद्धांत की वजह से सत्ता में लाया गया। रही बात शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता की तो वह पार्टी के लिए फायदेमंद ही रहेगी। भाजपा के मूल कैडर में न तो विद्रोह करने की क्षमता होती है और न उसकी इच्छा होती है। उन्हें पता होता है कि वह इसी संगठन से निकले हुए हैं। पार्टी भले ही शिवराज को राष्ट्रीय राजनीति में ले गई लेकिन वह मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जड़ों को सामाजिक सराकारों के जरिए मजबूत बनाए रखेंगे। जिसका लाभ भाजपा को ही मिलेगा। ●

- **शिवराज सिंह चौहान के देशव्यापी दौरे और उन दौरों में खासकर तमिलनाडु में इशारों ही इशारों में किए गए संकेतों से राजनीतिक हल्कों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि मामा शिवराज सिंह चौहान अब भोपाल नहीं बल्कि दिल्ली में ही परमानेंट अपनी राजनीतिक धूनी रमाएंगे।**
- **मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बंपर सफलता दिलवाने में शिवराज के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेहद अहम भूमिका रही है इस बात को नकारा नहीं जा सकता, ठीक जिस तरह लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एकदम नए नवेले मुख्यमंत्री होने के बाद भी उल्लेखनीय भूमिका रही है।**

- **राजनीति में अपनी शानदार ब्रांडिंग की और मामा के उपनाम से सारे देश में जाने-जाने वाले शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई लाड़ली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की चार दीवारी से निकलकर सारे देश में फैल गई और भाजपा तो छोड़िए गैर भाजपा सरकारों ने भी इसका नाम बदलकर इसे अपने-अपने राज्यों में चलाना शुरू कर दिया।**
- **आलाकमान द्वारा जिस तरह से नई पीढ़ी को आगे लाने वाली लाइन पर काम किया गया और पुराने को मार्गदर्शक की भूमिका में डाला जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा और नए चेहरे को बनाए जाने से ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि इस कड़ी में निकट भविष्य में कुछ पुराने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है।**

भालुओं की नींद उड़ी

उत्तराखंड में बर्फबारी असंतुलित हो चुकी है, इसलिए भालू प्राकृतिक गोद से उतरकर मानव बस्तियों में घुस रहे हैं, ऐसे में सवाल है कि भालू की नींद को कैसे पूरा किया जाए? क्योंकि उत्तराखंड में जलवायु असंतुलन न केवल भालुओं की नींद हराम कर रहा है बल्कि वन विभाग एवं आमजन की नींद भी उड़ा रहा है।

राकेश मैन्दोला
देहरादून

उत्तराखंड की पहाड़ियों में प्रकृति की खूबसूरत फिजा में जहां वन संपदा पूरे भारत में सबसे अधिक हैं वहीं वन संपदा के साथ वन्यजीवों का भी बोलबाला है, लेकिन वर्तमान में जलवायु असंतुलन ने भालुओं की नींद उड़ा रखी है और भालुओं ने आमजन की नींद उड़ा रखी है। यानी जलवायु असंतुलन ने सभी को परेशान कर रखा है। वैज्ञानिकों एवं वन्यजीव विशेषज्ञों की राय माने तो भालू तीन माह शीत निद्रा अर्थात हाइबरनेशन में रहता है। बर्फबारी कम होने के कारण भालू हाइबरनेशन में जाने में परेशानी महसूस करते हैं। कारण स्पष्ट है कि बर्फबारी का समय पर ना होना और कम होना, जिससे भालू आबादी में प्रवेश कर रहे हैं। इसी साल जनवरी-फरवरी में भालुओं के हमलों की 9 घटनाएं हो चुकी हैं। जबकि पिछले वर्ष 2025 में 116 घटनाएं हुई थीं, जिसमें आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी,108 लोग घायल हुए थे। एक तरह से बर्फबारी का असंतुलित होने के कारण भालुओं के जीवन में भी असंतुलन पैदा हो रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञों एवं वानिकी विशेषज्ञों की राय माने तो भालू बर्फबारी के बाद जब शीत निद्रा में जाते हैं तभी भालू का जीवन एवं प्रकृति का संतुलन माना जाता है। गढ़वाल मंडल के वन संरक्षक आकाश वर्मा के अनुसार भालू कुछ इलाकों में सक्रिय हैं। जो भोजन की तलाश में आबादी तक पहुंच रहे हैं उनकी सक्रियता का एक बड़ा कारण बर्फबारी में कमी है, जिससे उनकी शीत निद्रा नहीं हो पा रही है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार एक फीट बर्फ जमी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यह उत्तराखंड के ग्लेशियरयों की सेहत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। सामान्य रूप से जब जलवायु का संतुलन ठीक स्थिति में होता है तब दिसंबर से जनवरी के बीच कम से कम 5 से 6 बार अच्छी बर्फबारी हो जाती है, लेकिन यह लगभग एक दशक से नहीं हो पा रही है। वन्यजीव विशेषज्ञ डा.नागेंद्र टोडरिया का मानना है कि जलवायु संतुलन हिमालय क्षेत्र के सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। लेकिन जलवायु के असंतुलन, प्रदूषण, विकास की प्रक्रियाओं ने कहीं ना कहीं जलवायु को बदला है, जिससे उत्तराखंड में बर्फबारी असंतुलित हो चुकी है। इसलिए भालू प्राकृतिक गोद से उतरकर मानव बस्तियों में घुस रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भालू की नींद को कैसे पूरा किया जाए? क्योंकि उत्तराखंड में जलवायु असंतुलन न केवल भालुओं की नींद हराम कर रहा है बल्कि वन विभाग एवं आमजन की नींद भी उड़ा रहा है।

हिंसक हो रहे हैं भालू

कुल मिलाकर पहाड़ों पर भालुओं का जीवनचक्र बदल रहा है। बर्फबारी और समय पर ठंड नहीं होने से भालू की नींद पूरी नहीं हो रही है। इतना ही नहीं पहले की तरह ना तो भालू को आसानी से भोजन मिल पा रहा है और न ही उसके आवास स्थल सुरक्षित रह गए हैं। यानी जलवायु परिवर्तन का भरपूर असर भालुओं के जीवन पर सीधे तौर से दिखाई देने लगा है। इसलिए भालू हिंसक हो रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी जिलों में जंगली भालुओं के हमले चिंता का सबब बन रहे हैं। कई गांवों में हर शाम भालू की दहशत से सन्नाटा पसर जाता है। राज्य गठन के बाद 25 सालों के आकड़े गवाह हैं कि भालुओं के हमलों में उत्तराखंड में 71 लोगों की जान जा चुकी है। 2 हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं। पिछले 5 सालों में भालुओं के हमले अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। भालुओं के आक्रामक रवैये पर वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के पूर्व साइंटिस्ट और भालू एक्सपर्ट डॉ. एस सत्या कुमार ने भी चिंता जाहिर की है। वन्यजीव विशेषज्ञ डा.नागेंद्र टोडरिया का मानना है कि इस बार सर्दियों की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में भालुओं का व्यवहार चिंता का विषय बना है। सामान्य तौर पर नवंबर तक हाइबरनेशन में चले जाने वाले भालू इस बार पहाड़ी इलाकों में सक्रिय देखे जा रहे हैं। कम बर्फबारी और ठंड में देरी के कारण भालू अब भी जागे हुए हैं, जिससे उनकी आक्रामकता बढ़ती दिखाई दे रही है। कई इलाकों में भालू इंसानों और मवेशियों पर हमला कर रहे हैं। इसके कई कारण है। सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। क्योंकि अब हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी कम हो रही है। इससे ठंड भी कम पड़ रही है। जिससे ठंडे इलाकों में रहने वाले भालू का हाइबरनेशन (शीत निद्रा) का समय कम हो गया है। भालू इसलिए हाइबरनेशन करते हैं ताकि सर्दियों के कठिन मौसम में जब भोजन कम हो तो वो जिंदा रह सकें। लेकिन उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट से लेकर मिजोरम सहित हिमालय के नीचे के गर्म मैदानी जंगलों में काला भालू हाइबरनेशन नहीं कर पा रहा है। उत्तराखंड में अब मॉनसून के दौरान भारी बारिश भी भालू समेत दूसरे वन्यजीवों के लिए मुसीबत बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन परिस्थितियों में वन्यजीवों के आवास स्थलों पर भी मलबा आ जाता है, जिससे वन्यजीवों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है और नई जगह जाने के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही उनके भोजन का संकट भी गहरा जाता है। इन हालातों से यह स्पष्ट है कि एक नहीं बल्कि ऐसे कई कारण हैं जिससे भालू अपना सामान्य व्यवहार छोड़ रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात भालुओं का हाइबरनेशन में नहीं जाना ही माना जा रहा है।

- **भालू इसलिए शीत निद्रा करते हैं ताकि सर्दियों के कठिन मौसम में जब भोजन कम हो तो वो जिंदा रह सकें, लेकिन उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क व कॉर्बेट से लेकर मिजोरम सहित हिमालय के मैदानी जंगलों में काला भालू हाइबरनेशन नहीं कर पा रहा है, उत्तराखंड में तो मॉनसून के दौरान भारी बारिश भी भालू समेत दूसरे वन्यजीवों के लिए मुसीबत बन रही है।**
- **भालू पढ़े-लिखे नहीं हैं, नैतिक-अनैतिक की परिभाषाएं नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं कि जब उनके साथ गलत होगा तो उन्हें सोना नहीं है बल्कि गुफाओं से निकलना है और गलत करने वालों को उनकी भूल का अहसास कराना है, फिर भी सामने वाला न माने तो पंजों और दांतों का जो पैनापन प्रकृति ने उन्हें दिया है, उसका इस्तेमाल करना है।**

वैज्ञानिकों एवं वन्यजीव विशेषज्ञों की राय माने तो भालू तीन माह शीत निद्रा अर्थात हाइबरनेशन में रहता है, लेकिन बर्फबारी कम होने के कारण भालू हाइबरनेशन में जाने में परेशानी महसूस करते हैं, कारण स्पष्ट है कि बर्फबारी का समय पर ना होना और कम होना, जिससे भालू आबादी में प्रवेश कर रहे हैं।

क्या है हाइबरनेशन

शीतकाल में कम से कम तीन महीने गुफा में जाकर शीतनिद्रा (हाइबरनेशन) में जाने वाले भालू अब सो नहीं पा रहे हैं। मौसम के बदलने से और मनुष्य की बनाई गलत व्यवस्थाओं से उनके व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। हाइबरनेशन जानवरों द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों (जैसे अत्यधिक ठंड या भोजन की कमी) में ऊर्जा बचाने के लिए अपनाई जाने वाली एक गहरी निष्क्रियता की अवस्था है, जिसमें उनके शरीर का तापमान, हृदय गति और श्वासन दर नाटकीय रूप से धीमी हो जाती है, जिससे वे महीनों तक जीवित रह सकते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि भालू पूरी सर्दी अपनी गुफा में ही व्यतीत करते हैं। लेकिन इस बार वह शीत निद्रा में जाने की जगह आबादी वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनकी नींद में गंभीर खलल पड़ रही है। इसलिए भी भालू आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंसानों पर अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं। भालू पढ़े-लिखे नहीं हैं। नैतिक-अनैतिक की परिभाषाएं नहीं जानते। लेकिन वो इतना जानते हैं कि जब उनके साथ गलत होगा तो उन्हें सोना नहीं है बल्कि अपनी गुफाओं से बाहर निकलना है और गलत करने वालों को उनकी भूल का अहसास कराना है और फिर भी सामने वाला अपनी गलती न माने तो पंजों और दांतों का जो पैनापन प्रकृति ने उन्हें दिया है, उसका इस्तेमाल करना है, गलती करने वाले को अपनी आक्रामकता दिखानी है। वन्यजीव है लिहाजा हिंसा उसकी प्रवृति में है। कुल मिलाकर मौसम का यह चक्र और जलवायु परिवर्तन ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले सालों में भालुओं के व्यवहार में और भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि पहले ही जिस तरह के हमले पर्वतीय जिलों में भालुओं के देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ है कि भालू अब अपने सामान्य व्यवहार को छोड़ कर नए जीवन चक्र को अपना रहे हैं। जो मानव वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से चिंताजनक है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन का असर अब जंगलों तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड के पहाड़ों में भालुओं की यह बेचैनी एक गंभीर चेतावनी है कि प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा रहा है और इसका असर इंसान और वन्यजीव दोनों पर पड़ रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञ कहते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में इसके लिए अब तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसके बाद सजग रहने की जरूरत है।

भालुओं से सावधान रहने की जरूरत

काले भालू हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र के अलावा नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्यों में पाए जाते है। ये मांस खाते है, लेकिन कम खाते है। भालू को बीज, फल, जड़ी-बूटी. घास, बांस आदि अधिक पसंद है। यह जंगल में रहता है और इंसानों को नजरअंदाज करता है। मगर कम ऊंचाई वाले पहाड़ी स्थानों पर कूड़ा बढ़ गया है। गांव के आसपास फूलों व फलों आदि की खेती हो रही है। भालुओं को यहां बिना किसी मेहनत के खाना हर समय मिल रहा है। पिछले कुछ समय में चमोली जिले के जोशीमठ और घाट क्षेत्रों में मवेशियों पर भालुओं के हमलों की कई घटनाएं सामने आई थी। अचानक बढ़े इन हमलों ने स्थानीय निवासियों की नींद उड़ा दी थी। रात के समय भालू खेतों और घरों के पास तक पहुंच जाते थे। मवेशियों के अलावा खेतों में खड़ी फसल व अनाज के भंडार तक को नुकसान पहुंचा रहे थे। गांव के आसपास आने की वजह से मानव-भालू संघर्ष बढ़ा रहा था। वन विभाग की ओर से समय समय पर अपील की जाती है कि ग्रामीण घरों के बाहर खाद्य सामग्री, कचरा, फल सब्जियां खुले में न रखें, जिससे भालू आकर्षित न हों। रात के समय अकेले न निकले, बाहर रोशनी की समुचित व्यवस्था बनाए रखें और बच्चों को अकेले कहीं न भेजें। इसके साथ ही पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें और घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जाए। किसी भी स्थिति में भालू को उकसाने, उस पर पत्थर से हमला करने जैसे कार्य न करें, इससे स्थिति गंभीर हो सकती है। जंगल में आग लगाने, भालू को भगाने के लिए पटाखे छोड़ने या पकड़ने की कोशिश करने को कानूनन अपराध बताया गया है। यदि भालू सामने आ जाए तो घबराएं नहीं, शांत रहें और उसे अपनी पीठ दिखाकर भागने की कोशिश न करें। सुरक्षित स्थान पर जाएं, आंखें न मिलाएं और मौके से धीरे-धीरे दूरी बनाएं। यानी भालू को नजरअंदाज करने की कोशिश करें। इससे उसके हमले से बचा जा सकता है। ●

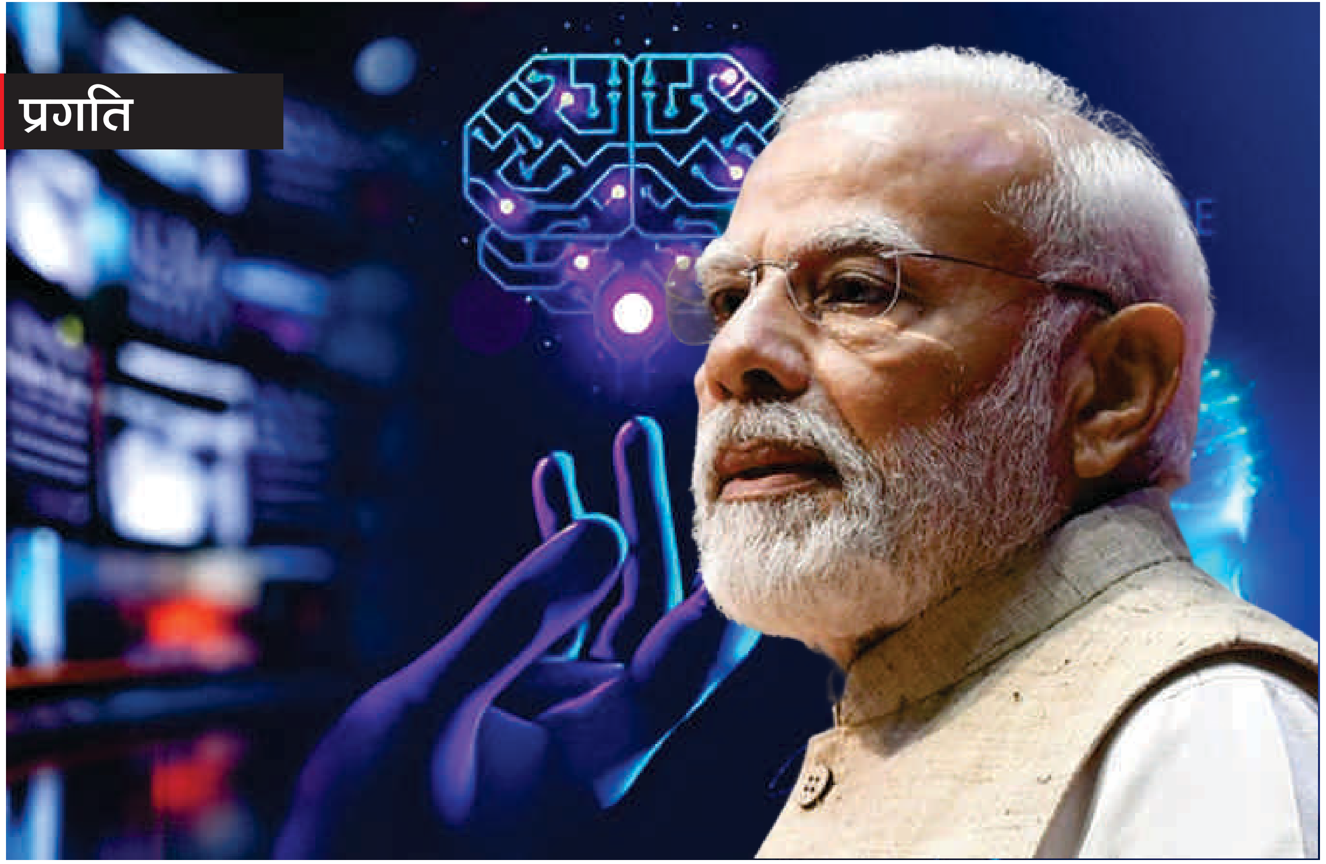

एआई का बड़ा बाजार भारत

भारत ने इस बार एआई समिट की थीम 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' रखी थी, इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आम इंसान के हित में इस्तेमाल करने पर जोर देना था, भारत हमेशा से एआई के नैतिक और जनहितकारी इस्तेमाल पर बल देता रहा है, इस समिट में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी प्रगति को भी दुनिया के सामने रखा।

बाबू सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

राजधानी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल इंपैक्ट समिट में 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों और कंपनियों के साथ 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस एआई समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा, ब्रिटेन के दो पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और ऋषि सुनक शामिल हुए। स्विटजरलैंड, स्पेन, स्लोवाकिया, सर्बिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, ग्रीस, मॉरीशस, भूटान, श्रीलंका और कजाखस्तान के साथ बोलीविया, गयाना और सेशेल्स के नेता भी शिरकत करने पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी एआई समिट को संबोधित किया। इससे पहले फ्रांस और दक्षिण कोरिया इस तरह के सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। ये पहला मौका है जब ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट किसी विकासशील देश में हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम करने वाली सैकड़ों कंपनियों के सीईओ भी इस समिट का हिस्सा बने। इनमें ओपन एआई के संस्थापक सैम आल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स शामिल हुए। भारत ने इस बार एआई समिट की थीम 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' रखी थी। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आम इंसान के हित में इस्तेमाल करने पर जोर देना था। भारत हमेशा से एआई के नैतिक और जनहितकारी इस्तेमाल पर बल देता रहा है। इस समिट में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी प्रगति को दुनिया के सामने रखा। विश्व भर से आए राजनीति और व्यापार जगत के नेताओं को ये दिखाया गया कि एआई के क्षेत्र में भारत जैसे देश में कितनी संभावनाएं हैं और भारत एआई का इंफास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कितने डेटा सेंटर्स और कितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार कर रहा है। भारत में एआई का इस्तेमाल किस तरह प्रशासन, स्वास्थ्य, रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में किया जा रहा है। एआई का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं के समाधान करने के लिए होना चाहिए न कि भारी भरकम शब्दों से इसे परिभाषित करके इससे डराया न जाए। यानी एआई का उपयोग ट्रैफिक नियंत्रण के लिए, सड़कों पर ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए, आपातकालीन सेवाओं के लिए, जनकल्याणकारी योजाओं की मॉनिटरिंग के लिए, किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए, वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाए तो समाज का फायदा है।

- **भारत एआई में भय नहीं, भाग्य देखता है, हमारे युवा नए-नए टूल्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को एआई के मामले में सोच बदलनी होगी, गोपनीयता छोड़नी होगी, एआई को लोकतांत्रिक नजरिए से देखना होगा, कोडिंग जाहिर करनी होगी, तभी इसे मानवता के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।**
- **ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का कहना था कि आने वाले दिनों में भारत एआई का सबसे बड़ा बाजार बनेगा, ऑल्टमैन ने कहा कि ये सही है कि एआई के आने से नौकरियों पर फर्क पड़ेगा, लेकिन इस चुनौती का हल भी एआई से ही निकलेगा।**

एआई सबके पास हो

फाइनेंस और अकाउंटिंग के कामों में एआई सॉफ्टवेयर की सटीकता कमाल की है। गोल्डमैन साक्स ने ये एआई सॉफ्टवेयर तैयार किया है। पहले सॉफ्टवेयर कंपनियां कोडिंग का काम करती थी, अब ये काम एआई बड़ी आसानी से कर देता है। इसलिए ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एआई की वजह से लोग बेरोजगार न हों। एआई ने कुछ क्षेत्रों में तो कमाल का काम किया है। रोग-प्रतिरक्षा चिकित्सा पर एक एआई डिवाइस तैयार की गई है जो कैंसर के इलाज में कारगर साबित हो रही है। लंदन पुलिस ने चेहरे की पहचान टैकनोलोजी पर आधारित एआई सॉफ्टवेयर तैयार किया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले दोषियों पर एआई के जरिए नजर रखी और एक महीने में 105 अपराधियों को जुर्म करने से पहले ही दबोच लिया। इसी तरह यूपी की आयुर्विज्ञान यूनीवर्सिटी ने एक एआई टूल तैयार किया है, जो 20 सेकंड में चेहरे को स्कैन करके सेहत का हाल बता देगा। नेचर मैगजीन में छपे एक लेख में बताया गया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एआई टूल तैयार किया है, जो किसी भी व्यक्ति की एक दिन की नींद पर नजर रखेगा और 130 बीमारियों के जोखिम के बारे में पहले ही आगाह कर देगा। हालांकि अभी एआई सॉफ्टवेयर तैयार करने में भारत काफी पीछे है। इसलिए अब भारत का फोकस हार्डवेयर की तरफ है, डेटा सेंटर्स बनाने पर है और एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एआई के इस्तेमाल और एआई के विकास में जोड़ा जा सके। यानी एआई सबके पास हो, सबके लिए हो।

एआई के खतरों से भी सावधान हैं

राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का एआई विजन बता दिया। उन्होंने कहा, भारत एआई में भय नहीं, भाग्य देखता है, हमारे युवा नए-नए टूल्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को एआई के मामले में सोच बदलनी होगी, गोपनीयता छोड़नी होगी। एआई को लोकतांत्रिक नजरिए से देखना होगा, कोडिंग जाहिर करनी होगी, तभी इसे मानवता के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कम शब्दों में कई बड़ी बातें कहीं। भारत एआई में विश्व का अग्रणी बनना चाहता है, हमारे देश के पास टेलेंट भी है, युवा शक्ति भी है और सरकार का समर्थन भी है। मोदी ने कहा हम एआई के खतरों के बारे में भी सावधान हैं। एआई बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है एआई के कारण युवाओं की नौकरियां जा सकती हैं, एआई लोगों को डीपफेक के जरिए गुमराह कर सकता है। इस तरह के सारे खतरों का जिक्र आज हुआ। एआई हमारे सामने है, इसे रोका नहीं जा सकता। अब ये हम पर है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, इंसानों की भलाई के लिए या समाज को नष्ट करने के लिए। एआई जिस रफ्तार से आगे बढ रहा है, उस पर नियंत्रण भी उतनी ही रफ्तार से करना होगा। यहां रुकने और सोचने का न समय है, न अवसर है।

भारत एआई का सबसे बड़ा बाजार बनेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का एआई की दुनिया के बड़े-बड़े लीडरों ने समर्थन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, 10 साल पहले मुंबई में एक रेहड़ी वाला बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता था, आज वही रेहड़ी वाला पलक झपकते ही अपने फोन पर पेमेंट ले रहा है। मैक्रों ने कहा, ये सिर्फ तकनीकी तरक्की की कहानी नहीं है, ये एक सभ्यता की कहानी है, भारत ने दुनिया में वो कर दिखाया, जो कई अन्य देश नहीं कर सके। भारत ने एक अरब 40 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान बनाई, भारत ने ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया, जिसमें हर महीने 20 अरब रुपये के लेनदेन की प्रॉसेसिंग होती है। गूगल-अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि उनके पिता रघुनाथ पिचाई ने उन्हें एआई का एक बड़ा चैलेंज दिया है। जब वो अपने माता-पिता को गूगल की स्वचालित कार वैमो में बैठाकर घुमाने ले गए, तो उनके पिता ने कहा, ये सब तो अच्छा है, तुम ऐसी कार भारत की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर चलाकर दिखाओ तो जानें। सुंदर पिचाई ने कहा कि वह अपने पिता का ये सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। पिचाई ने कहा एक वो जमाना था जब वो खुद कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार होकर चेन्नई से आईआईटी खडगपुर जाया करते थे, विशाखापत्तनम के रास्ते। आज उसी विशाखापत्तनम में गूगल एक फुल स्टैक एआई हब 15 अरब डालर के निवेश के साथ स्थापित कर रहा है। इसके तैयार होने के बाद इस हब में गीगावाट स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता होगी। ये समुद्र के भीतर एक केबल से जुड़ा होगा, जिसके जरिए पूरे भारत में लोगों को रोजगार और कारोबार के अवसर मिलेंगे। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का कहना था कि आने वाले दिनों में भारत एआई का सबसे बड़ा बाजार बनेगा। ऑल्टमैन ने कहा कि ये सही है कि एआई के आने से नौकरियों पर फर्क पड़ेगा, लेकिन इस चुनौती का हल भी एआई से ही निकलेगा।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, 10 साल पहले मुंबई में एक रेहड़ी वाला बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता था, आज वही रेहड़ी वाला पलक झपकते ही अपने फोन पर पेमेंट ले रहा है, भारत ने एक अरब 40 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान बनाई, भारत ने ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया, जिसमें हर महीने 20 अरब रुपये के लेनदेन की प्रॉसेसिंग होती है।

जियो करेगा 10 लाख करोड़ का निवेश

एआई समिट में मोदी 7 देशों के राष्ट्रपतियों, 9 देशों के प्रधानमंत्रियों, 50 से ज्यादा देशों के मंत्रियों और दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों के प्रमुखों को संबोधित किया। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कैसे जियो इंटेलिजेंस ने एआई का देसी मॉडल डेवलप करने के लिए फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा से टाईअप किया है। अंबानी ने कहा जिस तरह जियो ने सस्ता डेटा और वाई-फाई पूरे देश में उपलब्ध कराया है, उसी तरह अब जियो एआई को भी बेहद कम दाम में घर-घर पहुंचाएगा। इसके लिए जियो ग्रुप अगले 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। रिलायंस के चैयरमैन अंबानी ने कहा मैं एक साहसिक भविष्यवाणी करना चाहता हूं, 21वीं सदी में भारत एआई के सेक्टर में दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक बनकर उभरेगा, आने वाले समय में दुनिया का कोई भी देश, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा जेनरेशन और एआई के इस्तेमाल के मामले में भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। जियो ने भारत को इंटरनेट के दौर से जोड़ा। अब हम भारत को इंटेलिजेंस के युग से जोड़ेंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को अपनाने में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। जनरेटिव एआई ऐप्स डाउनलोड करने और चैटबॉट्स यूज करने में भारत दुनिया में सबसे आगे है और उसने कई एआई कंपनियों की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। सेंसर टावर के डेटा के मुताबिक, जनरेटिव एआई ऐप्स के लिए भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन गया है और यहां सालाना आधार पर एआई ऐप्स डाउनलोड में 207 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।●

सरकार गिरती क्यूं नहीं है?

2014 में भाजपा सत्ता में आई तो विपक्षी पार्टियों को लगा कि इस बार बिल्ली कि भाग से छींका टूट गया है, कोई बात नही 2019 में मोदी को ऐसी पटकनी देंगे कि इनके सारे अंजर-पंजर ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन जनाब भाजपा चाणक्य की फॉलोवर वाली पार्टी है, जो बड़े वाले आठ कदम पीछे जब रखती हो तो समझ जाओ कि वो एकदम से 108 कदम आगे

प्रदीप डीएस भट्ट
व्यंग्यकार, मेरठ

आपने अपने टेलीविजन पर बांगर सीमेंट का एक विज्ञापन अवश्य ही देखा होगा जिसमें बोमन ईरानी कहते हैं 'ये दीवार टूटती क्यों नहीं...' तभी पार्श्व में एक आवाज गूंजती है 'ये दीवार बांगर सीमेंट से बनी है टूटेगी कैसे...।' आजकल अपने देश के हालत भी कमोवेश कुछ ऐसे ही हैं। सभी विपच्क्षी (विपक्षी) पार्टियों के नेताओं के पता नहीं कहां-कहां सूजन आई पड़ी है। हर दिन हर दो घंटे में कोई न कोई लपड़ियाया सा नेता घंटा बजाकर घोषणा करता है...बस कल सरकार चली जाएगी या फला...फला दिन तक मोदी खुदई इस्तीफ दे देंगे और झोला लेकर हिमालय चले जाएंगे। अब इन घुडचंदों को कौन बताए कि मोदी और इस्तीफा अजी किस जमाने के आदमी हो तुम...बेटा मोदी का बस चले तो वो तुम्हारा इस्तीफा तुम्हारी घरवाली से लिखवा ले और भाई साहब वो घरवाली भी चांदी जैसे दांत चमकाती हुई हर-हर मोदी घर-घर मोदी करते हुए इस्तीफा सोने की तश्तरी में सजाकर प्रधान सेवक के चरणों में समर्पित कर दे। यानी 'तुम्हारी बिल्ली तुम्हें ही म्याऊं' और ये चले हैं जी इस्तीफा-इस्तीफा खेलने। मियां कभी चाय पे भी चर्चा किया करो सच्ची-सच्ची कह रिया हूं कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा।

विपक्ष के लिए भी जी राम जी योजना ?

जब 2014 में भाजपा सत्ता में आई तो विपक्षी पार्टियों को लगा कि इस बार बिल्ली कि भाग से छींका टूट गया है। कोई बात नही 2019 में हम मोदी को ऐसी पटकनी देंगे कि इनके सारे अंजर-पंजर ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन...लेकिन...जनाब भाजपा चाणक्य की फॉलोवर वाली पार्टी है। और वो बड़े वाले आठ कदम पीछे जब रखती हो तो समझ जाओ कि वो एकदम से एक सौ आठ कदम आगे जमाने वाली है, अब कर लो क्या करोगे। 2019 में पूरे कमल वाली पार्टी जोर से झांसी वाली रानी की तरह लड़ी और लो जी 302 सीटें लेकर विपक्ष का पिछ्वाड़ा लाल कर दिया। सरसों के झांज वाले तेल में जबरन पकाए गए नारे 'चौकीदार चोर है...' पर सुपर पावर ने ऐसी आमा-आमा की कि पप्पू भैया का बिना शर्त को माफी मांग कर ही पिंड छूटा। धारा 302 तो पहले से ही फेमस है अब भाजपा की 302 सीटों ने ऐसा कहर ढाया कि जिधर देखो उधर खलबली ही खलबली मची रही। मतलब वोटिंग की जगह वेटिंग मशीन लग गई। अब इसी बौड़मगिरि में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने अपनी बौड़मगिरि का मुजरा हर जगह पेश करना शुरू कर दिया। और तो और जिसने कभी वोटिंग मशीन का बटन तक भी नहीं देखा था वो भी बहुत बड़े ज्ञानी बाबा की तरह हर चैनल पर फुदक-फुदक कर वोटिंग मशीन ज्ञान पेलने लगा। लेकिन नतीजा तो वही ढाक के तीन पात होना था और हुआ भी। अब कीट पतंगों की तरह विपक्षी दल भी तिलमिलाए-तिलमिलाए से इधर से उधर और उधर से इधर अपना दुखड़ा सुनाते फिर रहे हैं। लेकिन वे जिसे भी सुनाने जाएं उसके पास उसका खुद का पर्सनल सा कुछ ज्यादा ही बड़ा दुखड़ा तैयार है। अब सब अपनी सुनाना चाहते पर दूसरे की सुनने को कोई राजी ही नहीं। अब बेचारा करे तो क्या करे सिवाए अगले पांच बरस तक ठलुआ बैठकर इंतजार करे या मोदी सरकार की जी राम जी योजना में काम करें। कम से कम एक साल में सवा सौ दिन का रोजगार तो मिल ही जाएगा और इससे वक्त अच्छा कट जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि देश के बेरोजगार नेताओं को बेरोजगारी का विधवा विलाप भी नहीं करना पड़ेगा।

भाजपाई कहते हैं कि पीएम मोदी अठारह-अठारह घंटे काम करते है, विपक्षी इसे तंज में देखते है लेकिन इसके पीछे का असली सच है कि पीएम मोदी पिछले ग्यारह सालों से रात को सो नहीं पाते है, क्योंकि उन्हें भय है कि पुण्य प्रसून, संजय शर्मा और इन जैसे न जाने कितने लपड़ झंडीस पुत्रकार न जाने कब उनकी सरकार गिरवा दें।

होनहार सेक्युलर पुत्रकार

हमारे देश के होनहार सेक्युलर पुत्रकार खादी का चोला पहनकर फोन पर ही कैबिनेट तक बना देते थे अब उनके फोन में इत्ता भी बैलेंस नहीं बचा कि वो मिस कॉल भी मार सकें। यानी 'गरीबी में आटा गीला' वाली नौबत आ गई है भाई साहब! एक बहुत पुरानी कहावत है 'पहली जीत मंगाए भीख' अब ऐसे महारथियों की आत्मा दिन में तीन बार भविष्यवाणी करने को उछाले मारती है। वो भविष्यवाणी कर भी देते हैं, लेकिन ससुरी पूरी एक भी नी हो रई। ऐसी पुण्य आत्माओं में एक नाम है पुण्य प्रसून बाजपेई! भाई साहब एक ठो घटना याद आ गई जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री बने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चैनल का पत्रकार उनसे सवाल कर रहा था और अटल जी अपने अंदाज ए बयां से सबको संतुष्ट भी कर रहे थे कि पुण्य प्रसून की आत्मा खड़ी हुई और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बोला मैं पुण्य प्रसून बाजपेई फलाना से तुरंत अटल जी ने कहा यहां एक ही बाजपेई काफी है। अब तनिक सोच के देखो कित्ता बड़ा दाग लगा था उस दिन बेइजत्ती में। तो हुजूर आजकल ये सरकार गिरवाने वाले नजूमियों की लिस्ट में अव्वल वाले पायदान पर कब्जा जमाए बैठे हैं। जब दरबे से निकलते हैं तो हाथ रगड़-रगड़ कर बताते हैं कि मोदी सरकार बस गिरने ही वाली है, सच में वो अपने फाइनेंसर की ऐसी चाटुकारिता करते हैं कि उनकी वीडियो तक वायरल हो जाती है। एक वीडियो मैंने भी देखी जिसमें वो अपने फाइनेंसर केजरीवाल से पूछ रहे हैं सर मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है...। ऐसे पुत्रकारों को शायद पत्रकारिता के नाम पर कलंक कहा जाए तो कोई बड़ा गुनाह नहीं होगी?

सरकार गिराने वाली जमात

अरे भैया ये अकेले ना हैं जिन्हें सरकार गिरवाने का शौक हो इस जमात में आकाश, रविश कुमार, अभिसार, अजित अंजुम जैसे पुत्रकार मोदी सरकार को कभी भी ऐसे गिरा देते हैं जैसे इनकी जेब में सरकार रखी हो और जब चाहा तब जेल उलट दी...। और हां बरखा रानी वो भी तो हैं ये वही बरखा हैं जिसे जनता ने कोरोना काल में लाशों पर रखने वाली लड़कियों को गिनकर पत्रकारिता का धर्म निभाते देखा था वो भी टीवी पर। किसी को उस चैनल का नाम याद आया हो तो उसकी स्मृति को नमन वो भी दूर से कर लें। जब से भाजपा हुकुमत में आई है और मोदी प्रधान सेवक बने हैं इनके सपनों को पंख तो क्या लगते उल्टे ये पंखों के बगैर उड़ नहीं पा रहे। खैर एक वो भी जमाना था जब ये सेक्युलर पुत्रकार सरकारी सहुलियतों का दुपट्टा ओढ़ फिजाओं में तैरते थे, देश-विदेश ऐश करते थे। सेक्युलर सरकारें, सेक्युलर पुत्रकारों के लिए रेड कारपेट बिछा देती थी। अब मोदी राज में ये तथाकथित सेक्युलर पुत्रकार अर्श से फर्श पर आए तो रीढ़ और पीठ ने काम करना बंद कर दिया, कमर ऐसी टूटी कि एसी रूम से बेदखल हो गए और अब जब भी मुंह में खुजली होती है तो उसे मिटाने के लिए यूट्यूबर बनकर दर-दर भटक और मटक रहे हैं।

54 साल का युवा पुत्रकारों का फेवरेट पीएम

ये सारे के सारे ज्योतिषी बने बैठे हैं ये और बात है कि इनकी एक्को भविष्यवाणी सीधी नहीं पड़ती,उल्टे मोदी के प्रकोप से इन सगरों की आत्मा अंधेरी काल कोठरी में चमगादड़ की मानिंद उल्टी लटकी हुई है। अरे हां एक ठो नाम तो छूट ही गया वो लखनऊ वाले 4 पीएम वाले संजय शर्मा अगर किसी को मोदी सरकार गिरवानी हो तो बेहद सस्ते दामों पर ये और पुण्य दोनों विशेषज्ञ सरकार गिरवा देते है। सुबह, दोपहर और शाम कभी भी सरकार गिरवा सकते है। रात में गिराने के स्पेशलिस्ट है। सरकार गिराने के लिए बहुत उम्दा थीम देते है, कयामत की रात, कातिल रात। कभी-कभी तो लगता है पहले रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्में लिखते थे। रामसे ब्रदर्स से ध्यान आया जब भी उनकी हॉरर फिल्म में कोई बेहद डरावन सीन आने को होता था तो तुरंत उस डर को कम करने के लिए एक मसखरा हाजिर हो जाता था। बस कुछ ऐसा ही हाल है इन लपाड़ियाओ का। वैसे ये इत्ते काबिल वाले पुत्रकार हैं कि अगर किसी पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा न हो तो ये बढ़िया वाली पत्तल चाटकर आपको दूसरे दल से मुख्यमंत्री एक्सपोर्ट भी करा देते हैं, लेकिन बात अगर प्रधानमंत्री बनवाने की हो तो इनके पास एक अदद प्रधानमंत्री भी है। आप चाहें या न चाहें लेकिन ये महाशय हर पार्टी को कंविंस करते हैं कि पार्टी आपकी हुई तो क्या हुआ प्रधानमंत्री तो ये 54 साल का कुंवारा, युवा, उर्जावान सड़क नापने वाला बंदा ही बनेगा। अब इस चक्कर में इंडी गठबंधन भिंडी ठगबंधन हुआ जा रहा है। अब इन घपड़चौथ को कौन समझाए कि भारत में गांव के पधान का भी एक ही सपना होता है कि कुछ जुगाड़ लगे तो वो भी प्रधानमंत्री बन जाए भले ही दो दिन के लिए और केजरू महाराज तो प्रधानमंत्री पद की हवस में पंजाब तोड़कर उसका प्रधानमंत्री बनने तक का ख्वाब पाले बैठा था।

- **अटल जी प्रधानमंत्री बने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चैनल का पत्रकार उनसे सवाल कर रहा था और अटल जी अपने अंदाज ए बयां से सबको संतुष्ट भी कर रहे थे कि पुण्य प्रसून की आत्मा खड़ी हुई और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बोला मैं पुण्य प्रसून बाजपेई फलाना से तुरंत अटल जी ने कहा यहां एक ही बाजपेई काफी है।**
- **देश के होनहार सेक्युलर पुत्रकार खादी का चोला पहनकर फोन पर ही कैबिनेट तक बना देते थे अब उनके फोन में इत्ता भी बैलेंस नहीं बचा कि वो मिस कॉल भी मार सकें, यानी 'गरीबी में आटा गीला' वाली नौबत आ गई है भाई साहब!**

मोदी के चौकीदार बनने का रहस्य

भाजपाई कहते हैं कि पीएम मोदी अठारह-अठारह घंटे काम करते है। विपक्षी इसे तंज में देखते है लेकिन इसके पीछे का असली सच है कि पीएम मोदी पिछ्ले ग्यारह सालों से रात को सो नहीं पाते है। क्योंकि उन्हें भय है कि पुण्य प्रसून और संजय शर्मा और इन जैसे जाने कितने लपड़ झंडीस पुत्रकार न जाने कब उनकी सरकार गिरवा दें। इसी डरावनी संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को चौकीदार कहकर संबोधित कर दिया था। डर सबको लगता है जनाब पर ये डर ससुरा मोदी का कुच्छो नहीं बिगाड़ पा रिया है। अब जिससे भय भी भयभीत हो उसी को तो मोदी कहा गया है। यकीन न आए तो कोशिश करके देख लो मियां। अगर शरीर के अंग प्रत्यंग से ढाई-ढाई सौ ग्राम धुंआ न निकले तो हमसे कहना। अब तो हालत ये हो गई है कि चंद्र बाबू नायडू और नीतीश बाबू खुदई मोदी जी को फोन करके पूछते हैं जनाब पुण्य के पुण्य कम तो नहीं हो गए जो एक हफ्ते बीत जाने पर भी सरकार गिरने का दावा नहीं कर रहा या उस 4पीएम वाले संजय का क्या हुआ लगता है उसकी आंखों का तेज आपने घटा दिया है। अब मोदी तो मोदी ठहरे एक कातिल मुस्कान बिखेरते हुए कहते हैं पुण्य का तो पुण्य अभी बाकी है पर लगता है इस संजय को शर्म आ गई है वैसे संजय को शर्म आए ऐसा नहीं भी हो सकता क्योंकि... तभी चंद्र बाबू नायडू बीच में टोकते हुए मोदी जी को कहते होंगे जनाब आपकी जलेबी जैसी बात म्हारे पल्ले न पड़ री है। मोदी फिर ठहाका लगाते हुए कहते होंगे मैं दिमाग में आने वाली चीज हूं समझ में आने वाली नहीं हाहाहाऽऽऽऽ।

ट्रंप सनक में दुनिया संकट में

दुनिया के रणनीतिकार और कूटनीतिक विशेषज्ञ यह बात भली-भांति समझते हैं कि ईरान में जिस तरह की ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, वह ईरान के बहाने चीन, रूस और भारत को डराने की कोशिश है, क्योंकि आज अमेरिका के अंदर यह दहशत है कि ये तीन देश अमेरिका के वर्चस्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं।

अतुल सिन्हा
टीवी जर्नलिस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब उम्र हावी हो रही है। वो कब क्या कह दें, फिर जो कहा उस पर पलटी मार दें ये शायद ट्रंप खुद भी नहीं जानते होंगे। ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि हमने ईरान पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन इसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। वो झूठ बोलने वाले दुनिया के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। क्योंकि इन्हीं ट्रंप ने आपरेशन सिंदूर के दौरान दावा कर दिया था कि भारत-पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने कराया है। शांति दूत ने यूक्रेन-रूस युद्ध रुकवाने के दावे किए, लेकिन सब झूठे साबित हुए। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा दिए थे। दावे पर दावे किए कि उन्होंने दुनिया में चल रहे 8 युद्ध रुकवा दिए हैं, लेकिन शांति दूत ट्रंप ने इसी साल पहले 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को किडनेप कर अमेरिका की जेल में डाल दिया। इसके ग्रीनलेंड कब्जाने की कोशिश की। अगले महीने यानी 28 फरवरी को शांति दूत ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर एक ही झटके में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत उसके 40 टॉप कमांडरों की हत्या के साथ खामेनेई के परिवार के कई सदस्यों की भी हत्या कर दी। ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत कर दुनिया भर में ऊर्जा का संकट पैदा कर दिया। ईरान सहित मिडिल ईस्ट में तेल के कुए तेल नहीं बल्कि आग और काला धुआं उगल रहे हैं। तेल का उत्पादन और सप्लाई प्रभावित हो गई है। तेल के रेट आसमान छूने लगे हैं। ऊर्जा संकट से दुनिया की अर्थ व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। शेयर बाजार लगातार गोते लगा रहे हैं। एक तरह से ट्रंप की सनक ने अमेरिका सहित दुनिया को संकट में डाल दिया है। जिस तरह से युद्ध चल रहा है और ईरान दावा कर रहा है कि वो 6 महीने तक युद्ध लड़ सकता है, उससे लगता है कि युद्ध का दायरा बढ़ेगा और आशंका है, ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है। क्योंकि ईरान आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के ट्वीट से पहले ही रूस से भारत को कच्चे तेल की सप्लाई शुरू हो गई थी, करीब 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल एक हफ्ते में भारत पहुंच गया, रूसी तेल के दो टैंकरों में 14-14 लाख बैरल तेल था, इनमें से एक ओडिशा का पारादीप पोर्ट पहुंचा, जबकि दूसरा गुजरात के वडीनार पोर्ट पर पहुंचा।

भारत के कारोबार पर असर

अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से भारत की अर्थ व्यवस्था भी प्रभावित होने लगी है। भारतीय निर्यातक पश्चिम एशिया के ऑर्डर रद्द होने का सामना कर रहे हैं। शिपिंग लाइने अब 'वॉर-रिस्क सरचार्ज' के तहत 40 फीट के कंटेनरों पर 1,500 डालर से 4,000 डालर तक अतिरिक्त चार्ज मांग रही हैं। इससे बासमती चावल, चाय, मसाले, फार्मास्युटिकल उत्पाद और सिंथेटिक फाइबर के शिपमेंट प्रभावित हो रहे हैं। दुबई का जेबेल अली पोर्ट यानी मुख्य व्यापारिक केंद्र पर जहाजों की आवाजाही रुकने से हजारों टन कृषि उत्पाद और अन्य सामान फंस गया है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। युद्ध के माहौल के कारण शिपिंग और इंश्योरेंस लागत में 500 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है और एक बड़ा हिस्सा होर्मुज के रास्ते आता है, युद्ध के कारण इसके बंद होने से तेल की कीमतों में 65 प्रतिशत से अधिक का उछाल आ चुका है। लगभग 14,500 करोड़ रुपये के फार्मास्युटिकल निर्यात पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि शिपिंग कंपनियां माल लेने से हिचकिचा रही हैं। कुल मिलाकर, ईरान-इजरायल का यह संघर्ष भारत की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रहा है, जिससे माल ढुलाई महंगी हो गई है और व्यापार के लिए अनिश्चितता का माहौल बन गया है।

अमेरिकी को अब झूठ का सहारा

युद्ध के दौरान अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बैसेंट ने ऐलान किया कि अमेरिका ने भारत को रूस से तीस दिन तक कच्चा तेल खरीदने की छूट दी है, ये छूट अस्थाई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत ने न तो किसी से तेल खरीदने की इजाजत मांगी और न ही किसी की इजाजत पर तेल खरीदना शुरू किया बल्कि सच ये है कि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात वित्त मंत्री के बयान से पहले ही बढ़ा चुका था। भारत-रूस से लगातार तेल खरीदता आ रहा है, हां कुछ दिनों से तेल की मात्रा जरूर कम की थी। लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री ने जिस अंदाज से और जिन शब्दों से भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट देने का ऐलान किया वो चौकाने वाला इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की बातें करने के आदी हो चुके हैं। युद्ध के बीच अमेरिका को कहना पड़ा कि जंग के कारण खाड़ी से कच्चे तेल की सप्लाई बंद है, इससे ईंधन का संकट पैदा हो सकता है। अगर ऐसा ही था तो फिर अमेरिका ने सिर्फ भारत पर ही मेहरबानी क्यों की? क्यों नहीं दूसरे देशों को रूस से कच्चा तेल खरीदने की इजाजत दी? फिर भी भारत के विपक्षी दल आदतन अमेरिकी वित्त मंत्री के ऐलान पर तो भरोसा कर रहा है, लेकिन भारत सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे। विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों की बौछार कर दी, देश को अमेरिका के सामने गिरवी रखने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, सबने मोदी पर हमले किए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अमेरिका से इजाजत मांगी किसने? सवाल ये भी कि क्या अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बयान से पहले भारत ने रूस से तेल का आयात बंद कर दिया था? स्कॉट बेसेंट के इस ट्वीट की टाइमिंग और उसकी भाषा राजनयिक शिष्टाचार के भी खिलाफ है। क्योंकि उनका ये ट्वीट भारत में सियासी मुद्दा बन रहा है। खैर अमेरिका अपने हितों को देख रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं हैं, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा, किस देश से नहीं, इसका फैसला करने का हक अमेरिका को किसने दिया है? सच ये है कि स्कॉट बेसेंट के ट्वीट से पहले ही भारत रूस से तेल की खरीद को बढ़ाने का फैसला कर चुका था। जब अमेरिका को ये खबर मिली तो श्रेय लेने के लिए वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से ऐसा ट्वीट जानबूझ कर कराया। ये एक तरह से अमेरिका की फितरत बन चुकी है। हालांकि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के ट्वीट से पहले ही रूस से भारत को कच्चे तेल की सप्लाई शुरू हो गई थी।

करीब 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल एक हफ्ते में भारत पहुंच गया। रूसी तेल के जिन दो तेल टैकरों को डायवर्ट कर भारत भेजा गया उसमें 14-14 लाख बैरल तेल था। इनमें से एक टैंकर ओडिशा का पारादीप पोर्ट पहुंचा, जबकि दूसरा गुजरात के वडीनार पोर्ट पर पहुंचा। इसके अलावा रूसी तेल लेकर सिंगापुर जा रहे एक और टैंकर को भारत की तरफ डायवर्ट किया गया। रूस से जब अतिरिक्त कच्चा तेल भारत पहुंच गया तब स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि अमेरिका ने भारत को रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने की छूट दी है, तो इस पर कौन यकीन करेगा? वैसे भी भारत पहले से ही अपनी जरूरत का करीब 20 प्रतिशत तेल रूस से ही आयात कर रहा है। भारत तेल और गैस के लिए सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर निर्भर नहीं है। भारत में दूसरे रास्तों से भी तेल आता है। सबसे सुकून की बात ये है कि इस समय एलपीजी को लेकर है, जिसका भारत में पर्याप्त भंडार है और उत्पादन को लेकर भी किसी तरह की कोई दिक्तत नहीं है। सरकार ने सभी रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। भारत में 33 करोड़ लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ी तो जिस एलपीजी का इस्तेमाल उद्योगों में हो रहा है, उसे रसोई घरों में खपत की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया कि भारत में अभी तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जंग लंबी खिंचती है तो तेल के आयात के दूसरे रास्ते खोजने होंगे। भारत सरकार इसी पर काम कर रही है।

अमेरिका और ईरान युद्ध से भारत की अर्थ व्यवस्था भी प्रभावित होने लगी है, भारतीय निर्यातक पश्चिम एशिया के ऑर्डर रद्द होने का सामना कर रहे हैं, शिपिंग कंपनी 'वॉर-रिस्क सरचार्ज' के रूप में 40 फीट के कंटेनरों पर 1,500 डालर से 4,000 डालर तक अतिरिक्त चार्ज मांग रही हैं, इससे बासमती चावल, चाय, मसाले, फार्मास्युटिकल उत्पाद और सिंथेटिक फाइबर के शिपमेंट प्रभावित हो रहे हैं।

नाकामी छिपा रहे ट्रंप?

पिछले दो दशकों में जिस तरह से दुनिया के कारोबार में डॉलर दिन पर दिन कमजोर हुआ है और सारी संभावनाओं और अनुमानों को सही साबित करते हुए चीन एक विश्व आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है, उससे अमेरिका हिल गया है। पिछले दशक में दुनिया के कारोबार करीब 93 फीसदी अमेरिकी डॉलर में होता था। लेकिन अब दुनिया के कारोबार में डॉलर का हिस्सा महज 58 से 60 फीसदी रह गया है, जिसका मतलब यह है कि दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार का सिर्फ 58 से 60 फीसदी हिस्सा ही डॉलर में है। यानी तेल और हथियार का जो कारोबार सिर्फ डॉलर से ही होता था, उसमें बड़ा हिस्सा बिना डॉलर के संपन्न हो रहा है। वास्तव में अमेरिका की सबसे बड़ी घबराहट और हताशा इसी बात को लेकर है। इसलिए वह किसी भी कमजोर देश को मटियामेट कर देने की अपनी हरकत के जरिये दुनिया को डराने-धमकाने पर आमादा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को किस तरह उन्होंने व्हाइट हाउस से जलील करके निकाला और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ किस तरह ट्रंप की तू-तू-मैं-मैं हुई, यह दुनिया ने देखा है। इसके बावजूद ट्रंप के दिल में यह हुड़क मची हुई कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। इसके लिए वह बीच-बीच में नोबेल कमेटी को अप्रत्यक्ष रूप से हड़काने का भी काम करते रहे हैं और कई बार यह भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है। सवाल है आखिर उनकी इस विध्वंसकारी सनक की असली वजह क्या है? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो कर रहे हैं, उसके पीछे क्या उनकी अपनी निजी अकड़ है अथवा इस सबके पीछे कोई गहरी राष्ट्रीय हताशा काम कर रही है? अगर गौर से देखें तो पिछले 13 महीनों में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया को अपनी सनक से हलकान कर रखा है, उसका कारण सिर्फ उनकी निजी इच्छा या अहंकार भर नहीं है। इसके पीछे अमेरिका की गहरी हताशा है कि आने वाले दिनों में दुनिया में उसका पिछले कई दशकों से जारी वर्चस्व कायम रहेगा या खत्म हो जाएगा? क्योंकि पूरी दुनिया के रणनीतिकार और कूटनीतिक विशेषज्ञ यह बात भली-भांति समझते हैं कि ईरान में जिस तरह की ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, वह दरअसल ईरान के बहाने चीन, रूस और भारत को डराने की कोशिश है। क्योंकि सब कुछ के बावजूद आज अमेरिका के अंदर यह दहशत है कि ये तीन देश अमेरिका के वर्चस्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। ●

लोकपर्व से जुड़ा कंडाली फूल

देवभूमि की लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देख कर पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कंडाली महोत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसका भोटिया समाज 12 वर्षों तक बेसब्री से इंतजार करता है, इस मेले का खासकर 'रं समाज' यानी भोटिया परिवार के लोगों को इंतजार रहता है, क्योंकि ये कंडाली महोत्सव उनकी विरासत से जुड़ा हुआ है।

कमल कपूर
वरिष्ठ पत्रकार

देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और लोक संस्कृति अपने आप में अनौखी व अद्भुत है। जिसे देखने हर साल देश-विदेश से लाखों टूरिस्ट उत्तराखंड का रुख करते हैं। यानी टूरिस्ट देवभूमि की लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देख कर अभिभूत हो जाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कंडाली महोत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसका भोटिया समाज 12 वर्षों तक बेसब्री से इंतजार करता है। इस ऐतिहासिक मेले का खासकर 'रं समाज' यानी भोटिया परिवार के लोगों को इंतजार रहता है। क्योंकि ये कंडाली महोत्सव उनकी विरासत से जुड़ा हुआ है। बूंदी गांव में पांगू में कुंभ की तर्ज पर 12 साल बाद कंडाली पर्व मनाया जाता है। कंडाली पर्व की लोककथा एक महिला के इकलौते बेटे की मौत से जुड़ी बताई जाती है। दरअसल पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील की चौदांस पट्टी में 'रं संस्कृति' के लोग निवास करते हैं, जो अपनी लोक संस्कृति और सामाजिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। चीन और नेपाल सीमा से सटे सीमांत के चौदांस क्षेत्र में बारह वर्षों बाद बुराई का प्रतीक माने जाने वाली कंडाली वनस्पति को नष्ट किया जाता है। कंडाली महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। लोकमान्यता है कि ग्रामीणों द्वारा कंडाली नामक वनस्पति को नष्ट करने से आने वाले 12 वर्षों के लिए क्षेत्र को संभावित सभी कष्टों से मुक्त होना माना लिया जाता है। 'रं समाज' कंडाली पर्व को ठीक कुंभ की तर्ज पर 12 वर्ष में एक बार मनाता है। पर्व में रिल और तलवार से दुश्मन का प्रतीक मानी जाने वाली वनस्पति (कंडाली) को नष्ट करने की परंपरा सदियों पुरानी है। लोक कथाओं के अनुसार सदियों पूर्व इस क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का इकलौता 12 वर्षीय पुत्र बीमार पड़ गया था। उस समय सिर्फ जड़ी-बूटी से ही उपचार किया जाता था। जब बीमार बच्चे का कंडाली के पौधे से उपचार किया गया तो, लड़के की मौत हो गई। इकलौते बच्चे की मौत के बाद महिला ने वनस्पति को श्राप दिया कि बारहवें वर्ष में जब तेरी टहनियां भी बारह हो जाएंगी तब तुझे भी नष्ट कर दिया जाएगा। तब से ही 12 साल में कंडाली उत्सव का आयोजन कर उसके पौधों को नष्ट किए जाने की परंपरा है। यानी स्थानीय लोग इस पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में अपने पैतृक घर पहुंचते हैं। लोग इस विरासत से आने वाली युवा पीढ़ी को भी रूबरू कराने के लगातार प्रयास करते हैं।

कंडाली की पैदावार और खूबसूरती

कंडाली या स्ट्रोबिलैन्थिस वॉलिची, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक झाड़ी है। यह एक बहुवर्षीय पौधा है जो कई वर्षों तक बिना फूलों के बढ़ता रहता है। जब इसके खिलने का समय आता है, तो इस पर घने गुच्छों में तुरही के आकार के सुंदर, बैंगनी-नीले फूल खिलते हैं। ये फूल पूरी झाड़ी को ढक लेते हैं, जिससे दूर से देखने पर पूरी पहाड़ी नीली दिखाई देती है। कंडाली एक 'प्लीटेसियल प्रजाति है। यह एक वानस्पतिक शब्द है जिसका उपयोग उन पौधों के लिए किया जाता है जो एक लंबे, अनुमानित अंतराल के बाद सामूहिक रूप से खिलते हैं, बीज पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। कंडाली के मामले में यह चक्र 12 वर्षों का होता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कंडाली और उसकी प्रजाति के अन्य पौधे ऐसा असाधारण व्यवहार क्यों करते हैं? विली ऑनलाइन लाइब्रेरी और राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र में प्रकाशित वैज्ञानिक शोध-पत्र इस घटना को 'मास्ट सीडिंग' या 'मास्टिंग' कहते हैं। यह एक विकासवादी रणनीति है जिसके पीछे गहरे पारिस्थितिक कारण हैं। मास्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रजाति के सभी पौधे एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ, एक ही समय पर खिलते हैं और भारी मात्रा में बीज पैदा करते हैं। जब 12 साल के लंबे अंतराल के बाद अचानक लाखों-करोड़ों बीज उपलब्ध हो जाते हैं, तो बीज खाने वाले शिकारी जैसे चूहे और कीड़े उन सभी को नहीं खा पाते। उनकी आबादी सीमित होती है और वे इस अचानक आई भोजन की बाढ़ का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इस प्रकार, अधिकांश बीज सुरक्षित बच जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं। जिन पर 11 वर्षों में फूल नहीं खिलते, उन वर्षों में इन शिकारियों को भोजन नहीं मिलता, जिससे उनकी आबादी भी नियंत्रित रहती है। जब पूरी घाटी एक साथ फूलों से भर जाती है, तो यह परागणकों जैसे मधुमक्खियों और अन्य कीड़ों के लिए एक विशाल और आकर्षक दावत बन जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि हर पौधे को परागण के लिए पर्याप्त अवसर मिले, जिससे निषेचन और बीज निर्माण की सफलता दर बहुत बढ़ जाती है।

तंडारी त्योहार के पीछे एक और मान्यता ये है कि सदियों पहले, जब बाहरी आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र के एक किले पर हमला किया, तो उन्होंने खुद को छिपाने के लिए इन्हीं ऊंची कंडाली झाड़ियों का इस्तेमाल किया था, जब स्थानीय लोगों ने युद्ध जीत लिया, तो गांव की महिलाओं ने गुस्से में उन झाड़ियों को श्राप दिया और अपनी तलवारों और दरांती (रैप) से उन्हें नष्ट कर दिया था।

फूल खिलने पर मनाया जाता है त्योहार

वैज्ञानिक मानते हैं कि इन पौधों में एक प्रकार की 'आंतरिक घड़ी' होती है जो उन्हें वर्षों की गिनती करने में मदद करती है। यह कैसे काम करती है, यह अभी भी गहन शोध का विषय है, लेकिन यह सिंक्रनाइज़ेशन प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। किंतु कंडाली फूल का यह अनूठा 12-वर्षीय जैविक चक्र पिथौरागढ़ के रं समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले प्रसिद्ध कंडाली महोत्सव का आधार है। यह त्योहार प्रकृति और संस्कृति के गहरे जुड़ाव का एक जीवंत प्रमाण है। इस त्योहार के पीछे एक और ऐतिहासिक लोककथा है। लोक मान्यता है कि सदियों पहले, जब बाहरी आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र के एक किले पर हमला किया, तो उन्होंने खुद को छिपाने के लिए इन्हीं ऊंची कंडाली झाड़ियों का इस्तेमाल किया था। जब स्थानीय लोगों ने युद्ध जीत लिया, तो गांव की महिलाओं ने गुस्से में उन झाड़ियों को श्राप दिया और अपनी तलवारों और दरांती (रैप) से उन्हें नष्ट कर दिया था, जिन्होंने दुश्मन को छिपने में मदद की थी। कंडाली महोत्सव उसी घटना की याद में मनाया जाता है। हर 12 साल में जब कंडाली के फूल खिलते हैं, तो रं समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में इकट्ठा होते हैं। वे गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान में, कंडाली की झाड़ियों पर हमला करके उन्हें नष्ट करते हैं। इसके बाद एक भव्य दावत का आयोजन होता है। यह एक ऐसा अनूठा त्योहार है जिसका कैलेंडर किसी ग्रह या तारे से नहीं, बल्कि एक फूल के खिलने से तय होता है।

कंडाली महोत्सव में शत्रु की प्रतीक वनस्पति कंडाली को नष्ट करने की परंपरा सदियों पुरानी है, मान्यता है कि सदियों पूर्व इस क्षेत्र की एक महिला का इकलौता 12 वर्षीय पुत्र बीमार पड़ गया जिसका कंडाली के पौधे से उपचार किया गया तो, लड़के की मौत हो गई, बेटे की मौत के बाद महिला ने कंडारी वनस्पति को श्राप दिया कि 12वें वर्ष में जब तेरी टहनियां 12 हो जाएंगी तब तुझे भी नष्ट कर दिया जाएगा।

2035 में होगा कंडाली महोत्सव

कंडाली पर्व में स्यंड़सै (शिव), गबला (गणेश) के अलावा ईष्ट, ग्राम देवताओं सहित पूर्वजों का आह्वान कर पूजा की जाती है। उत्सव में पहले दिन की उपासना चिलमन से शुरू होती है। चिलमन का मतलब तन और मन को पवित्र बनाना है। दूसरे दिन मैमसा होता है, यानी भोटिया समाज अपने पूर्वजों का गौरव गान कर उनसे मानसिक संबंध स्थापित करता है। कंडाली महोत्सव में पारंपरिक व्यंजनों को परोसा जाता है और लोग अपने पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर पर्व को मनाते हैं। साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं पारंपरिक परिधान में नाचते-गाते इस कंडाली वनस्पति को नष्ट करते हैं। इस पर्व में पारंपरिक परिधान लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। कंडाली महोत्सव साल 2023 में आयोजित हुआ था, इसके बाद अब 2035 में कंडाली महोत्सव आयोजित होगा। कंडाली का वानस्पतिक नाम आर्टिका डायोसिया है। ये भारत और नेपाल के उच्च मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। कंडाली वनस्पति एक पुष्पीय पौधा है। इस पौधे में प्रतिवर्ष एक फूल खिलता है। बारहवें वर्ष में बारह फूल खिल जाते हैं। इसके साथ इसे क्षेत्र के लिए अभिशप्त भी मानते हुए नष्ट करते हैं। इस पौधे को कंडाली के साथ किर्जी भी कहा जाता है। चौदास घाटा में कंडाली और बूंदी में इसे किर्जी नाम से जाना जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी घाटी की जो वर्षों तक हरी-भरी और शांत रहती है और फिर अचानक, एक निर्धारित समय पर यानी 12 वर्षों में पूरी की पूरी घाटी बैंगनी-नीले फूलों के एक जीवंत समुद्र में बदल जाता हो। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि पिथौरागढ़ की ऊंची घाटियों की एक वास्तविक और विस्मयकारी सच्चाई है, जो हर 12 साल में एक बार घटित होती है। यह चमत्कार कंडाली नामक एक पौधे के पुष्पन का है। कंडाली के रहस्यमयी पुष्पन के पीछे छिपे विज्ञान और संस्कृति की पड़ताल करने पर समझ आएगा कि यह पौधा इतने लंबे अंतराल के बाद एक साथ पूरे क्षेत्र में कैसे खिलता है? इस अनूठी घटना ने पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध कंडाली महोत्सव को कैसे जन्म दिया? और इस फूल का महत्व केवल इसकी सुंदरता और दुर्लभता से कहीं बढ़कर क्यों है?

औषधीय गुण भी हो सकते हैं

कंडाली का महत्व केवल इसके दुर्लभ पुष्पन और सांस्कृतिक जुड़ाव तक ही सीमित नहीं है। शोध जर्नलों में प्रकाशित अध्ययन बताते हैं कि स्ट्रोबिलैन्थिस जीनस के पौधों में औषधीय गुण भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस जीनस की विभिन्न प्रजातियों में कई बायोएक्टिव यौगिकों की उपस्थिति पाई है। प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि इन यौगिकों में सूजन-रोधी रोगाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण हो सकते हैं। यह इस पौधे के महत्व में एक और आयाम को जोड़ता है, जो भविष्य में औषधीय अनुसंधान के लिए एक संभावित स्रोत हो सकता है। कुल मिलाकर पिथौरागढ़ की घाटियों का कंडाली फूल एक पौधे से कहीं बढ़कर है। यह एक जैविक पहेली है जो 'मास्ट सीडिंग' जैसी जटिल विकासवादी रणनीतियों को प्रदर्शित करती है। यह एक सांस्कृतिक मील का पत्थर है जो एक पूरे समुदाय के त्योहार और उसकी पहचान को परिभाषित करता है। यह एक संभावित औषधीय खजाना भी है। कंडाली की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक पुष्पी पौधे का जीवन चक्र किसी क्षेत्र के वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने-बाने में गहराई से बुना जा सकता है, जो हर 12 साल में खिलने वाले एक साधारण फूल को एक बहुप्रतीक्षित और पूजनीय घटना में बदल देता है। ●

दिल्ली से पांडवों की यादें गायब

आज की दिल्ली में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का नाम-ओ-निशान तक नहीं है, पर दिल्ली में अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड, डलहौजी रोड और औरंगजेब रोड अवश्य मिलेंगी, ये वो मुगल शासक हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, तलवार के बल पर हिंदुओं का धर्मान्तरण कराया, भारत की संपदा को लूटी।

शालिनी चौहान
नई दिल्ली

दिल्ली को दिलवालों का शहर कहा जाता है। यह वही दिल्ली है, जिसका इतिहास महाभारत काल (द्वापर युग) से शुरू होता है, महाभारत काल में ही पहली बार हस्तिनापुर से बाहर खांडवप्रस्थ नामक स्थान पर पांडवों ने मानव बस्ती बसाई थी, देवराज इंद्र की मदद से बसाए गए इस शहर का नाम पांडवों ने इंद्रप्रस्थ रखा था, लेकिन विडंबना देखिए आज की दिल्ली में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का नाम-ओ-निशान तक नहीं है। किंतु दिल्ली में अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड, डलहौजी रोड और औरंगजेब रोड अवश्य मिलेंगी। ये वो मुगल शासक हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, तलवार के बल पर हिंदुओं का धर्मान्तरण कराया। भारत की संपदा को लूटा, इन आक्रमणकारी मुगलों की कहानियां इतिहास में इस तरह से दर्ज की गई जैसे भारत की तरक्की में सिर्फ मुगलों की ही भूमिका रही है। हो भी क्यों नहीं मुगलों और अंग्रेजों से आजाद हुए भारत में वामपंथी इतिहासकारों ने देश के भविष्य को गुमराह करने वाला इतिहास पढ़ाया। इसे बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ने तन मन धन से सहयोग किया। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के नाम गीता और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में दर्ज न होते तो आज इन्हें भी महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, राणा सांगा, वीर दुर्गादास राठौड़, छत्रसाल बुंदेला, रानी दुर्गावती, महाराजा सूरजमल, लाचित बोरफुकन, गुरु गोबिंद सिंह और बाबा बंदा सिंह बहादुर की तरह भुला दिया गया होता। अकबर को महान बताने वाले इतिहासकारों ने कभी महाराणा प्रताप के प्रताप की गाथा नहीं बताई। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का गुणगान नहीं किया। वामपंथियों ने भारत की समृद्ध संस्कृति को मिटाने का पाप किया है। इसलिए देश की राजधानी दिल्ली में मुगलों और अंग्रेजों की पहचान तो हैं, लेकिन दिल्ली की धरती पर इंसान को बसाने वाले पांडवों की पहचान मिटा दी गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि युग बदला, सदियां बदलीं और अलग-अलग राजवंशों का शासन देखते हुए दिल्ली आज राजनीति का केंद्र बन चुकी है। इंद्रप्रस्थ से दिल्ली तक के सफर में किस-किसने यहां राज किया? इसे समझने की आवश्यकता है।

इंद्रप्रस्थ से दिल्ली बनने का किस्सा

इंद्रप्रस्थ के दिल्ली बनने की कहानी तो महाभारत काल से ही जुड़ी है। प्राचीन इतिहास में दर्ज है कि कुंती के सबसे बड़े बेटे कर्ण के वंशज ढिल्लू राजा हुए। उन्होंने 800 ईसा पूर्व दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली में आबादी को बसाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश भी पुष्टि करती है कि राजा ढिल्लू ने ही आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के शुरु में दिल्ली पर शासन किया था। उन्हें धिल्लू और दिलू नाम से भी जाना गया। कालांतर में उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ गया। वैसे कुछ आधुनिक इतिहासकार राजा ढिल्लू को मौर्य वंशज मानते हैं और उनका शासनकाल ईसा पूर्व पहली शताब्दी में बताते हैं। लेकिन ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ ही बताया जाता है। इंद्रप्रस्थ को कुछ ग्रंथों में श्रीपत भी कहा गया है। यही वह स्थान है जिसे पांडवों ने अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। शुरूआत में यह क्षेत्र खांडवप्रस्थ नाम से जाना जाता था। एक ऐसा इलाका जो बंजर, निर्जन और रहने योग्य नहीं था। लेकिन जब भगवान श्रीकृष्ण की प्रेरणा पर मयासुर ने यहां भव्य महल और किले का निर्माण किया, तो यह स्थान एक समृद्ध नगर बन गया। कहते हैं कि इस शहर की सुंदरता और वैभव स्वर्ग की राजधानी इंद्रलोक से भी तुलना की जाती थी। आज भी दिल्ली में पुराना किला और उसके आस-पास का क्षेत्र इंद्रप्रस्थ नाम से प्रसिद्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य भी बताते हैं कि यह वही स्थान है जहां कभी पांडवों का गौरवशाली नगर बसा था। यह वही नगर है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि शहर का प्रसिद्ध पुराना किला इंद्रप्रस्थ के अवशेषों पर निर्मित है, जो दिल्ली के पौराणिक महत्व और भारतीय सभ्यता से उसके गहरे संबंध को दर्शाता है। इसी संदर्भ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने एक बार फिर एक रोचक मुद्दा उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि अब समय आ गया है जब राजधानी का नाम अंग्रेजी में 'दिल्ली नहीं' नहीं, बल्कि 'ढिल्ली' लिखा जाना चाहिए।

1639 में शाहजहां ने राजधानी के लिए नया स्थान ढूंढ़ा और दिल्ली में पुराने किले से कुछ ही दूरी पर उत्तर में राजधानी बसानी शुरु की, इसके लिए उसने किला उर्दु-ए-मौला बनवाया, जिसे अब लाल किला कहा जाता है, साल 1648 में शाहजहां ने अपनी राजधानी इसी इलाके में शिफ्ट कर दी, जिसे शाहजहांनाबाद कहा गया, शाहजहानाबाद को ही अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है।

गोयल का तर्क है कि 'दिल्ली' शब्द का कोई भाषाई या सांस्कृतिक अर्थ नहीं बनता है, जबकि 'ढिल्ली' शब्द हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास से गहराई से जुड़ा है। उनके अनुसार जब आम बोलचाल में हर कोई 'दिल्ली' कहता है, तो अंग्रेजी में भी इसका सही उच्चारण 'ढिल्ली' ही लिखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में गलत स्पेलिंग 'देहली' प्रचलन में आ गई थी, जिसे अब सुधारा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के दौर (13वीं से 16वीं शताब्दी) में इस नगर को आमतौर पर 'डिल्ली' कहा जाने लगा था। यह नाम आज भी प्रचलन में है। हालांकि 'डिल्ली' शब्द की उत्पत्ति को लेकर मतभेद हैं, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इसका संबंध पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शासन करने वाले राजा ढिल्लू से हो सकता है। मामलुक, खिलजी और तुगलक जैसे अनेक राजवंशों के अधीन यह शहर राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना। प्रत्येक शासक ने अपनी राजधानी के रूप में अलग-अलग नगरों जैसे लाल कोट, सिरी फोर्ट, महरौली, फिरोज शाह कोटला, शेरगढ़, जहांपनाह और तुगलकाबाद की स्थापना की, लेकिन लोग इन सबको मिलाकर 'डिल्ली' ही कहते रहे।

अनंगपाल ने बसाया था लाल कोट

आधुनिक काल में दिल्ली का इतिहास तोमर राजवंश के अनंगपाल से जुड़ता है। मान्यता है कि 1020 के करीब अनंगपाल ने रॉयल रिजॉर्ट आनंदपुर को बसाया था। समय के साथ वह अपना राज्य लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में ले गए। जिसको लाल कोट कहा गया। सौ साल तक इस लाल कोट पर तोमर राजाओं ने शासन किया। 1164 ईस्वीं में पृथ्वीराज तृतीय (राय पिथौरा) ने अपने किले को और बड़ा करने के साथ ही कई भवन बनवाए। इससे शहर का नाम किला राय पिथौरा पड़ गया। पृथ्वीराज तृतीय 12वीं सदी के अंतिम दिनों में मुगल आक्रमणकारियों से हार गए थे। साल 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी तो लाल कोट से ही शासन शुरू किया था। यह 13वीं सदी के अंतिम दशक की बात है। दिल्ली पर खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। इनके शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली के उपनगरों में लूटमार की थी। इनसे बचने के लिए जलालुद्दीन के उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी (शासनकाल 1296-1316) ने कुतुबमीनार के उत्तर-पूर्व में कुछ दूरी पर एक गोलाकार किले में नया शहर बसाया, जिसका नाम सिरी था। इसी सिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी बनाया था। वर्तमान में इसको ही सिरी फोर्ट कहा जाता है। साल 1321 में खिलजी राजवंश का शासन खत्म हुआ और दिल्ली की सत्ता तुगलक वंश के हाथों में आ गई। गयासुद्दीन तुगलक (साल 1320 से 1325 तक शासनकाल) ने तुगलकाबाद नाम से अपनी नई राजधानी बसाई थी। हालांकि वहां पानी की कमी के कारण राजधानी को वापस सिरी लाया गया था।

गयासुद्दीन के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने अचानक सिरी के बजाय देवगिरी को दौलताबाद नाम से नई राजधानी बनाई थी। हालांकि 1354 में उसके उत्तराधिकारी फिरोजशाह ने फिर से राजधानी बदल दी और पुराने इंद्रप्रस्थ के पास यमुना के किनारे अपनी राजधानी बसाई। इसे वर्तमान में फिरोज शाह कोटला कहा जाता है।

समय के साथ इस दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ से डिल्ली, फिर शाहजहांनाबाद और अंततः दिल्ली हो गया, हर नाम इसकी गौरवशाली ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है, हालांकि हाल में इस नाम को बदलने के सुझाव पर सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस विषय ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा जरूर छेड़ दी है

मुगल शासन

यह 14वीं शताब्दी के आखिरी दिनों की बात है। जब दिल्ली पर आक्रमण कर तैमूर लंग ने खूब लूटपाट की थी। फिर 1414 से 1451 तक यहां सैय्यद वंश का राज रहा। साल 1451 से 1526 तक लोदी राजवंश ने इस पर कब्जा कर लिया। साल 1526 में दिल्ली को मुगल बादशाह बाबर ने अपने कब्जे में कर लिया पर उसने राजधानी दिल्ली के बजाय आगरा को बनाया। बाबर के बाद हुमायूं ने 1530 में सत्ता संभाली और यमुना के किनारे दीन पनाह नाम से नया शहर बसाया। हालांकि, 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं से सत्ता छीन ली और हुमायूं के दीन पनाह शहर का नाम बदलकर शेर शाही कर दिया। आगरा में शेरशाह द्वारा बनवाए गए किले को आज पुराना किला कहा जाता है। शेरशाह सूरी से एक बार फिर हुमायूं ने सत्ता हासिल कर ली और उसके बाद अकबर और जहांगीर ने अपना शासन आगरा से ही चलाया। साल 1639 में शाहजहां ने राजधानी के लिए नया स्थान ढूंढ़ना शुरू किया और दिल्ली में पुराना किला से कुछ ही दूरी पर उत्तर में राजधानी बसानी शुरू की। इसके लिए उसने किला उर्दु-ए-मौला बनवाया, जिसे अब लाल किला कहा जाता है। साल 1648 में शाहजहां ने अपनी राजधानी इसी इलाके में शिफ्ट कर दी, जिसे शाहजहांनाबाद कहा गया। शाहजहानाबाद को ही अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है।

राजा धीलू और दिल्ली

दिल्ली ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है, जो भारत का प्रमुख वाणिज्यिक, परिवहन, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार इस नगर का नाम राजा धीलू के नाम पर पड़ा, जिन्होंने ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। समय के साथ इस नाम के कई रूप प्रचलित हुए जैसे दिल्ली, देहली, ढिल्ली और धिल्लि जो संभवतः राजा धीलू के नाम से ही उत्पन्न हुए हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां ने एक भव्य दीवारों से घिरा नगर बसवाया, जिसे 'शाहजहांनाबाद' नाम दिया गया। आज यही क्षेत्र 'पुरानी दिल्ली' के नाम से प्रसिद्ध है। इस शहर में लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें और बाजार हैं। शाहजहांनाबाद न केवल मुगल साम्राज्य की राजधानी था बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार का भी केंद्र था। इसकी गलियां, हवेलियां और बाजार आज भी उस समय की शाही भव्यता की झलक पेश करते हैं। ब्रिटिश काल में 'दिल्ली' नाम को आधिकारिक रूप से अपनाया गया, हालांकि स्थानीय लोग तब भी इसे 'डिल्ली' ही कहते थे। 1911 में अंग्रेजों ने कोलकाता से राजधानी हटाकर दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया। आजादी के बाद दिल्ली का निरंतर विस्तार हुआ, और नई दिल्ली को भारत सरकार के प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। समय के साथ इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ से डिल्ली, फिर शाहजहांनाबाद और अंततः दिल्ली हो गया। हर नाम इसकी गौरवशाली ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। हालांकि, हाल में इस नाम को बदलने के सुझाव पर सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस विषय ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा जरूर छेड़ दी है।

आत्मकथा

समाज के लिए लड़ता अभिमन्यु

'खड़कदा' नैनीताल पढ़ने आए थे, पर वहां जलालत की जिंदगी हाथ आई, उन दिनों किसी समय वापस गांव जाने का विचार आता तो 'लोग क्या कहेंगे?' की कसक से मन घिर जाता, वे फिर अपनी नियति मान कर उसी यातनापूर्ण वातावरण में रहने को मजबूर हो जाते।

अरुण कुकसाल
चामी, पौड़ी, गढ़वाल

संघर्ष वाहनी प्रारंभ से ही 'चिपको' और 'वन आंदोलन' का फर्क जनता को बताती आई थी। लोग इस बात को समझ रहे थे कि चिपको (पर्यावरणवादी) नेताओं को सरकारी सेमीनारों में सादर बुलाया जाता है और वन आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से सरकारी दमन होता है। दरअसल पर्यावरणवादी (चिपको नेता) सरकारी संरक्षण में इस आंदोलन को भटकाने में सफल रहे। वन विधेयक-1980 उन्हीं की कारगुजारियों का परिणाम था। चिपको नेताओं और वन आंदोलनकारियों की नीति-नियत के मूलभूत अंतर को इंगित करते खड़कदा के विचार 70 के दशक के उत्तराखंड का सामाजिक-राजनीतिक सच था। 'चिपको' शब्द नवजात अवस्था में ही 'पर्यावरणवादी' नाम हासिल कर सरकारी पनाह पा गया था। बाद में सरकारी संरक्षण-संपर्क में वो पर्यावरणवादी पुरस्कारों और अपने सगे-संबंधियों को ऊंचे ओहदों से चिपका कर खुद को 'चिपको' की पहचान बनाने में कामयाब रहे। इसके दूसरी ओर वन आंदोलनों के पक्षकार आम उत्तराखंडी जनता के जल-जंगल-जमीन के हक के लिए उनके साथ आज भी लड़ाई के अग्रिम मोर्चों पर तैनात हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, साहित्यकार और बड़े भाई खड़क सिंह खनी की आत्मकथा 'सूरज को तो उगना ही था' को पढ़ने के बाद लगा कि कितना कम जानते थे, हम उनके बारे में? आज जाना कि उनकी आत्मीय मुस्कान के पीछे जीवन की कितनी जटिलताएं उन पर डेरा डाले रहती थी। हम तो बस हर समय मुस्कराते हुए हौसला देते 'खड़कदा' को ही जानते थे। उनसे मुलाकातें कम होती थी। पर हमारा दावा था कि हम उनके अंतरंग मित्र हैं। परंतु अगर हम उनके अंतरंग मित्र थे, तो उन्हें जीवन की विकटताओं से उभारने के लिए हम कब और कितने समय उनके साथ खड़े रहे? मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि उनसे अंतरंगता का हम मित्रों का दावा, ये किताब सिरे से नकार देती है।

गरीबी के साथ रहने की आदत

'खड़कदा' की जिंदगी के कुछ हिस्सों में सिमटी यह पुस्तक दुनिया की दुनियादारी के कई चेहरे हमारे सामने लाती है। सामाजिक-राजनीतिक बेहतरी के लिए संघर्षशील संगठनों का सच, भ्रम, ह्रश्र इस किताब के पन्नों में जहां-तहां पसरा है। किताब का नायक चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु सा है। वह जीवन भर सामाजिक अन्यायों का विरोध करता रहा, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में आए अभावों को मूक-दर्शक बनकर सहता रहा। वह दृढ़निश्चयी नायक आने वाली पीढ़ी पर विश्वास करते हुए, उनके द्वारा सामाजिक क्रांति के सपने के साकार होने की आशा में दुनिया से विदा लेता है। 'खड़कदा' यहीं पर 'नायक' से 'महानायक' बनकर फिर से हम मित्रों का आज भी हौसला आफजाई करते हुए नजर आते हैं। बात 1975 के आस-पास की है। अल्मोड़ा के नैलपड़ गांव का युवा 'खड़कदा' नैनीताल के तल्लीताल में एक किराये के खोमचे में अखबार, चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, टाफी आदि बेचा करते थे। गरीबी और सामाजिक उपेक्षा-अपमान से 'खड़कदा' की बचपन में ही मुलाकात होने से इनके साथ रहने की उन्हें आदत हो गई थी। अतः बे-परवाह और बे-खबर 'खड़कदा' के लिए उस दौर के वे दिन-रात बिंदास थे। परंतु, मौज-मस्ती के इस आलम में 'खड़कदा' देश-दुनिया की हलचलों पर पैनी नजर रखते थे। घर-घर अखबार बांटते-बेचते हुए, खबरों से बढ़ते लगाव ने उनकी सामाजिक संवेदनशीलता-चेतना को समझ और दिशा देने की शुरुआत कर दी थी। एक दिन उनके मित्र चंद्र सिंह कार्की ने तब के युवा डॉ. शमशेर सिंह बिष्ट से उनकी मुलाकात कराई। 'शमशेरदा' व 'खड़कदा' में मुलाकातों का जो सिलसिला उस दिन शुरू हुआ था, वो फिर दोनों के बीच ता-उम्र चलता रहा। नैनीताल में डॉ. शमशेर बिष्ट से मुलाकात के बाद 'खड़कदा' की जीवनशैली और दिशा बदलने लगी। 'सामाजिक अन्याय और भेदभाव को जनक्रांति से खत्म किया जा सकता है।' ये मूल मंत्र 'खड़कदा' को 'शमशेरदा' ने जो दिया फिर तो जीवन-भर इसी जनक्रांति के वे वाहक बने रहे।

'खड़कदा' की जिंदगी के कुछ हिस्सों में सिमटी यह पुस्तक 'सूरज को तो उगना ही था' दुनिया की दुनियादारी के कई चेहरे हमारे सामने लाती है, सामाजिक-राजनीतिक बेहतरी के लिए संघर्षशील संगठनों का सच, भ्रम, ह्रश्र इस किताब के पन्नों में जहां-तहां पसरा है।

जीवन के कडुवे अनुभवों ने किया मजबूत

नैनीताल की फुटपाथी दुकानदारी को तिलांजलि देकर 'खड़कदा' आजीवन सामाजिक कार्यकर्ता बने रहे। साथ ही उन्होंने 'पत्रकारिता' को जीविका चलाने और 'साहित्य सृजन' को जीवनीय अनुभवों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाया था। खड़कदा को जानने के लिए उनके बचपन से बात शुरू करते हैं। अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लाक के नैलपड़ गांव में जन्मे खड़क सिंह खनी ने जागनाथ विद्या निकेतन, शौकियाथल (जागेश्वर) से 1970 में 10वीं पास की। यह नैलपड़ गांव के लिए गौरव की बात थी। क्योंकि वे गांव के पहले हाईस्कूल पास युवा थे। परिवार की गरीबी से जूझते हुए पिता ने हिम्मत कर उन्हें रामजे इंटर कालेज, अल्मोड़ा में 11वीं में प्रवेश दिलाया। परंतु शहरी चमक-दमक के कुप्रभाव में 'खड़कदा' आ गए और 11वीं में फेल हो गए। गरीबी के कारण पढ़ाई यहीं छूट गई। वे अब अपने गांव में रह कर घरेलू कार्यों में सहयोग देने लगे। कम उम्र में ही शादी हो गई थी। आगे पढ़ने की इच्छा बलवती हुई तो अपने ससुर के भरोसे नैनीताल आ गए। 'खड़कदा' नैनीताल आकर स्कूली पढ़ाई से नहीं जुड़ सके, पर जीवन के कडुवे अनुभवों से मिली सीख ने उन्हें जीवन भर तन-मन से मजबूत बना दिया। 'बर्तन धोते-धोते सफेद हो चुकी हाथों की अंगुलियों में पानी पड़ते ही ऐसा महसूस होता था, जैसे किसी ने अंगुलियां छील कर उनमें लाल मिर्च के पाउडर का लेप लगा दिया हो। असहनीय जलन से वो कहार उठते थे। ऐसे में उन्हें मां की याद आती। उन्होंने काम छोड़कर घर वापस जाने का निर्णय लिया यहां न तो वो पढ़ाई कर पाए और न कमा कर घर कुछ रुपये भेज पाए। पर अब किस मुंह से घर जाऊं? न लत्ते, न कपड़े और न घर जाने का खर्च।'

वैवाहिक जीवन में बिखराव

'खड़कदा' नैनीताल पढ़ने आए थे, पर वहां जलालत की जिंदगी हाथ आई। उन दिनों किसी समय वापस गांव जाने का विचार आता तो 'लोग क्या कहेंगे?' की कसक से मन घिर जाता। वे फिर अपनी नियति मान कर उसी यातनापूर्ण वातावरण में रहने को मजबूर हो जाते। निरंतर गिरते स्वास्थ्य का परीक्षण डाक्टर से कराया तो उनमें 'क्षय रोग' की पुष्टि हुई। 'क्षय रोग आश्रम, गोठिया' में 3 माह के इलाज के बाद 'खड़कदा' अपने काम में फिर से जुट गए। स्थितियां अब कुछ बेहतर थी। नजदीकी लोगों की मदद से वे अपना व्यवसाय चलाने लगे। लेकिन नैनीताल में कारोबार को समेटने के बाद 'खड़कदा' 'पर्वतीय युवा मोर्चा' से जुड़ कर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली आदि समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत रहते। सामाजिक भेदभाव, अन्याय, उत्पीड़न, घूसखोरी के विरुद्ध उनके आंदोलन दूर-दूर तक चर्चा में आने लगे। 'खड़कदा' की हिम्मत का यह आलम था कि उन्होंने एक बार घूसखोर पटवारी को उसी की हथकड़ी पहना कर डीएम अल्मोड़ा के सामने पेश कर दिया था। 'खड़कदा' की जागरूकता की तारीफ करते हुए तत्कालीन डीएम मुकुल सनवाल ने पटवारी को निलंबित कर दिया था। यह सच है कि सार्वजनिक जीवन की तुलना में पारिवारिक मन-भेद व्यक्ति में अधिक टूटन लाते हैं। दुर्भाग्यवश 'खड़कदा' और उनकी पत्नी में आपसी तालमेल नहीं हो सका। लिहाजा आपसी सहमति से वे दोनों वैवाहिक जीवन से अलग हो गए। कुछ समय बाद माता-पिता को पता चला कि उनकी पूर्व पत्नी का पुर्नविवाह हो गया है। फिर तो मां की हठ और दबाव में उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। इस तरह 'खड़कदा' को जीवन को नए ढर्रे में आने में कुछ समय लगा। वे अब जीविका के कामों को पूरी मेहनत से करते। परंतु सामाजिक कार्यों में ज्यादा सक्रियता होने से कई मुश्किलें सामने रहती। उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए कई दिनों तक घर से बाहर रहना होता था। इससे घर के कार्य प्रभावित होते थे।

पलायन रोकने की पहल

'पर्वतीय युवा मोर्चा' ने 1977 में पलायन रोकने और युवाओं को अपने ही परिवेश में रोजगार देने के उद्देश्य से 4 स्थानों पर 'लेबर को-ऑपरेटिव सोसायटी' का संचालन किया था। सिलंगी सोसायटी का कार्य खड़क सिंह खनी के संयोजन में चलने लगा। 'लेबर को-ऑपरेटिव सोसायटी' लीसा निकालने, सड़क, रास्ता, गूल, नहर निर्माण, उपजों को बेचने आदि कार्य करती थी। को-ऑपरेटिव सोसायटी व पर्वतीय युवा मोर्चा पलायन रोककर पहाड़ों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार का 'मॉडल' लोकप्रिय और सफल करना चाहता था। 'पर्वतीय युवा मोर्चा' को विस्तार देते हुए 1977 में गैर चुनावी राजनीति के केंद्र में 'उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी' का गठन किया। 'खड़कदा' वाहिनी के प्रतिनिधि बनकर वन आंदोलन में भाग लेने लगे। एकांत मिलता तो वे अपने मन की व्यथा लिखने लगते। चर्चित उपन्यास 'किस्मत की ठोकर' इसी दौर में उन्होंने लिखा। जीविका के लिए रोजगार और सामाजिक क्रांति के लिए आंदोलन दोनों विपरीत दिशा में संतुलन रखना कठिन हो रहा था। परंतु 'खड़कदा' आंदोलन में आक्रामक और परिवार के प्रति गंभीर रहते। वन आंदोलन के बाद वे 1983 में प्रारंभ हुए 'नशा नहीं रोजगार दो' आंदोलन में शामिल हुए। 'खड़कदा' का जीवन उतार-चढ़ाव में ही बीता। वे कई बार शरीर और मन से कमजोर हुए। परंतु जीवन को जीवटता से जीने के आदी 'खड़कदा' कभी निराश नहीं हुए। 'ब्लड कैंसर' के बाद भी उनकी मुस्कराहट होंठों पर हर वक्त तरोताजा रहती थी। 13 सितंबर, 1997 को 'ब्लड कैंसर' का पता चलने से लेकर अपनी मृत्यु के दिन 28 जुलाई, 2006 तक 'खड़कदा' अपने काम से कभी विमुख नहीं रहे। इस दौर में कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हल्द्वानी की यात्राएं की। एक अंतहीन दर्द के साथ इन 9 सालों को उन्होंने अपनी फक्कड़ी के अंदाज में ही बिताया। सच के लिए लड़ना, बेबाकी से कहना और मित्रों पर अटूट विश्वास रखकर वे अपने को कभी अकेला महसूस नहीं होने देते थे। वे अपनी बीमारी के लिए सरकारी सहायता के सख्त खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं शुरू से ही जब से बीमारी का पता चला, जनता के भरोसे रहना चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि जनता मेरे इलाज के लिए पूरा खर्च जुटा देगी। मुझे इलाज के लिए सरकार का मोहताज नहीं होना पड़ेगा जिन्हें मैं जनविरोधी मानता हूं। 'खड़कदा' ने 'उत्तर उजाला', 'दि संडे पोस्ट' और 'हिंट' अखबार उनकी पत्रकारिता के विभिन्न समयों के पड़ाव थे। निर्भीकता और निष्पक्षता उनके समाचारों-लेखों की पहचान थी। अखबारों के मालिकों के जो भी हित रहे हों 'खड़कदा' सामाजिक हित से कभी विमुख नहीं हुए। 'किस्मत की ठोकर' और 'अंतिम उपहार' (उपन्यास), 'आदत जो बन गई', 'कमूली' 'और मैं बन गया' (कहानी) उनकी चर्चित रचनाएं हैं। उनकी जीवनी के कुछ अंश 'आशाएं अभी शेष हैं' धारावाहिक रूप में 'दि संडे पोस्ट' में प्रकाशित हुई थी। 'खड़कदा' बचपन से मृत्यु तक जीवन के सभी मोर्चों पर अकेले ही लड़ते रहे। इस आशा के साथ कि जन आंदोलनों से मानवीय जीवन में सामाजिक समरसता और समानता का भाव कायम होगा। वे बच्चे की तरह हर नए आंदोलन से उम्मीद रखते कि इसके बाद समाज में जरूर बदलाव आएगा। आंदोलनों का पटाक्षेप होता पर 'खड़कदा' की उम्मीद आने वाले समय के लिए कायम रहती। 'सूरज को तो उगना ही था' (एक आत्मकथा) पुस्तक का प्रकाशन 'इंडिपेंडेंट मीडिया इनीशिएटिव सोसायटी' के अपूर्व जोशी ने 2007 में किया था। खड़क सिंह खनी अपनी इस आत्मकथा को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि 28 जुलाई, 2006 को ब्लड कैंसर ने उन्हें हमसे छीन लिया था। यह आत्मकथा 'खड़कदा' की है। परंतु इसके हर पन्ने पर हम सामाजिक जनजीवन के सच और भ्रम से सामना करते हैं। हमारी इंसानियत पर कुरीतियों का कुठाराघात किस हद तक हुआ? इसका आंकलन 'खड़कदा' ने अपनी आत्मकथा में किया है। किताब में 'खड़कदा' के संस्मरणात्मक लेख रोचकता के साथ आज के संदर्भ में प्रेरक हैं। ●

• नैनीताल में डॉ. शमशेर बिष्ट से मुलाकात के बाद 'खड़कदा' की जीवनशैली और दिशा बदलने लगी, 'सामाजिक अन्याय और भेदभाव को जनक्रांति से खत्म किया जा सकता है' ये मूल मंत्र 'खड़कदा' को 'शमशेरदा' ने दिया तो फिर जीवन भर इसी जनक्रांति के वे वाहक बने रहे।

• 'खड़कदा' की हिम्मत का यह आलम था कि उन्होंने एक बार घूसखोर पटवारी को उसी की हथकड़ी पहना कर डीएम अल्मोड़ा के सामने पेश कर दिया था, 'खड़कदा' की जागरुकता की तारीफ करते हुए तत्कालीन डीएम मुकुल सनवाल ने तुरंत पटवारी को निलंबित कर दिया था।

संजू बाबा का संघर्ष

संजय दत्त की जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूटा जब बचपन में उनकी मां नरगिस का निधन हो गया, मां की मौत ने संजय की जिंदगी में भूचाल ला दिया था, संजय पूरी तरह ड्रग्स के नशे में डूब गए, इस लत ने संजू को अंदर से खोखला कर दिया, हालांकि पिता सुनील दत्त ने अपने लाडले को इस तरह बर्बाद होते देख उन्हें सुधारने के लिए दिन-रात एक कर दिया।

अरुण सिंह
मुंबई ब्यूरो

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त लंग्स कैंसर की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि असल जिंदगी में इस बीमारी ने संजू को अपने आगोश में ले लिया है, लेकिन यह भी सच है कि बॉलीवुड के 'संजू बाबा' की रियल जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही है। छोटी उम्र में मां की मौत, ड्रग्स की लत और जेल जाने तक, संजय दत्त की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। कैसा है संजय दत्त की जिंदगी का सफर इसे जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल संजय दत्त ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर की थी। सबसे पहले वह 'रेश्मा और शेरा' फिल्म में नजर आए थे। यह फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 1981 में संजय ने रॉकी फिल्म से बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत की। पहली ही फिल्म ने संजय दत्त को रातोंरात स्टार बना दिया। किंतु संजय दत्त की जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूटा जब बचपन में ही उनकी मां नरगिस का निधन हो गया। अचानक हुई मां की मौत ने संजय की जिंदगी में भूचाल ला दिया था। मां की मौत के बाद संजय पूरी तरह ड्रग्स के नशे में डूब गए। इस लत ने संजू को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। हालांकि पिता सुनील दत्त ने अपने लाडले को इस तरह बर्बाद होते देख उन्हें सुधारने के लिए दिन-रात एक कर दिया। सुनील दत्त इलाज के लिए संजू को अमेरिका तक ले गए, जहां दो साल के इलाज के बाद उनकी वापसी मायानगरी में हुई। बॉलीवुड में वापसी के बाद संजू ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं। 1987 में उन्होंने ऋचा शर्मा से शादी कर ली, लेकिन शायद संजय की किस्मत में खुशियां ज्यादा देर तक नहीं लिखी थी। शादी के नौ साल बाद ब्रेन ट्यूमर के कारण ऋचा की मौत हो गई। ऋचा की मौत के बाद संजय एक बार फिर अकेले पड़ गए और उनका फिल्मी ग्राफ भी गिरने लगा था। हालांकि कुछ समय बाद संजू ने रिया पिल्लई से दूसरी शादी कर ली, लेकिन यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और जल्द ही दोनों का तलाक हो गया।

हथियारों की दीवानगी ने जेल पहुंचाया

1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में संजय दत्त को आरोपियों में से एक माना गया था। पुलिस जांच में उनका नाम सामने आने के तुरंत बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय वो मॉरिशस में फिल्म 'आतिश' की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन मुंबई बम ब्लास्ट में नाम आने के कारण उन्हें मुंबई लौटना पड़ा, जहां एयरपोर्ट पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि मुंबई ब्लास्ट के दशकों बाद इस मुकदमें की पैरवी करने वाले सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि संजय दत्त को धमाकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस समय संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि उनके पास से एके-56 राइफल बरामद हुई थी। उज्ज्वल निकम ने माना कि संजय दत्त हथियारों का दीवाना था, जिसके कारण वह अंडरवर्ल्ड के अपराधियों के साथ जुड़ गया था। उज्ज्वल निकम ने इंटरव्यू में बताया कि भले ही मुंबई ब्लास्ट में संजू की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन अवैध हथियार खरीदने के लिए डी कंपनी के अबू सलेम से वो मिले थे। धमाकों से पहले अबू सलेम हथियारों से भरा एक टेंपो लेकर संजू के पास आया था। संजय दत्त ने हथियारों में से एक एके-56 राइफल अपने पास रख ली और बाकी हथियार लौटा दिए थे। संजय दत्त ने पूछताछ में जांच एजेंसियों को हथियार रखने और अबू सलेम के अपने घर आने की बात कबूली थी। इसके बाद संजय पर टाडा कानून के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें छह साल की जेल हुई थी। 1993 से लेकर 2006 तक संजू को आतंकवादी कहकर बुलाया जाता था, लेकिन साल 2006 में मुंबई बम धमाकों के मामले की सुनवाई कर रही टाडा अदालत ने कहा कि संजय एक आतंकवादी नहीं है और उन्होंने अपने घर में गैरकानूनी रायफल अपनी हिफाजत के लिए रखी थी। संजय पर टाडा के आरोप खत्म कर दिए गए थे और उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया था।

'मैं हूं खलनायक' नाम सुनकर ही हर किसी के जहन में संजय दत्त का नाम आ जाता है, 90 के दशक में बनी फिल्म 'खलनायक' आज भी लोगों को याद है, इस फिल्म की कहानी जितनी जबरदस्त थी उससे कहीं ज्यादा इसके गाने हर किसी की जुबां पर बने रहते हैं।

2008 में मान्यता से शादी

2006 में भले ही संजू को टाडा के खिलाफ राहत मिल गई, लेकिन उनका फिल्मी करियर पूरी तरह समाप्त हो गया था। हालांकि फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' से उन्होंने एक बार फिर वापसी की और अपने काम से सभी के मुंह बंद कर दिए। इसके बाद 2008 में संजू बाबा ने मान्यता से शादी कर ली। यहां से संजय ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी शुरू की। संजय की जिंदगी पर बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। 2018 में उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म 'संजू' में रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया था। अपने 40 साल के फिल्मी करियर में संजय दत्त का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। एक वक्त मशहूर अभिनेत्री रेखा के साथ उनके अफेयर की खबरों ने भी जोर पकड़ा था। कई खबरों में दावा किया गया था कि संजय और रेखा ने शादी तक कर ली है। यही नहीं संजय दत्त और धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित के शादी करने की खबरें भी जोरों पर चली थीं, लेकिन अचानक संजू पर 'टाडा' लग गया और वह जेल चले गए। इसके बाद माधुरी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और दोनों का रिश्ता टूट गया था। 1986 में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव के करियर को बनाने के लिए 'नाम' फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने संजय दत्त को भी लिया था। यह फिल्म संजय दत्त के करियर का टर्निंग पाइंट बन गई और संजय ने बॉलीवुड में अपने पैर मजबूती से जमा लिए। संजय दत्त के अभिनय से अमिताभ इतने प्रभावित हुए थे कि कुमार गौरव और संजय दोनों को उन्होंने अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया और सोने की चेन उपहार में दी थी। बॉलीवुड के भाई जान यानी सलमान खान भी संजू बाबा के बहुत बड़े फैन रहे हैं। 90 के दशक में सलमान ने संजय दत्त वाली हेअर स्टाइल भी रखी थी। संजय ने ही सलमान को बॉडी बनाने और जिम जाने के लिए प्रेरित किया था।

'मैं हूं खलनायक' संजू का टर्निंग प्वाइंट

'मैं हूं खलनायक' नाम सुनकर ही हर किसी के जहन में संजय दत्त का नाम आ जाता है। 90 के दशक में बनी फिल्म 'खलनायक' आज भी लोगों को याद है। इस फिल्म की कहानी जितनी जबरदस्त थी उससे कहीं ज्यादा इसके गाने हर किसी की जुबां पर बने रहते हैं। आज भी इस फिल्म के गानों को सुना जाता है, लेकिन क्या आप जानते है इस फिल्म के लिए संजय दत्त पहली पसंद नहीं थे, बल्कि बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स के नाम इस किरदार के लिए पहले से तय थे।

1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में संजय दत्त को आरोपियों में से एक माना गया था, पुलिस जांच में उनका नाम आने के तुरंत बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उस समय वो मॉरिशस में फिल्म 'आतिश' की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन मुंबई बम ब्लास्ट में नाम आने के कारण उन्हें मुंबई लौटना पड़ा था।

हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई फिल्म 'खलनायक' में जैकी श्राफ और नाना पाटेकर को लेना चाहते थे। एक आर्ट फिल्म के रूप में खलनायक फिल्म का मुंबई में शानदार मुहूर्त भी हुआ लेकिन फिल्म इससे आगे बढ़ नहीं सकी। नाना पाटेकर जब तक फिल्म में थे तो वो बल्लू का किरदार निभा रहे थे। जब नाना फिल्म से बाहर हुए तो आमिर खान को लगा कि अब मौका है और वो एक निगेटिव रोल करके 'डर' के हाथ से निकल जाने की कमी पूरी कर सकते हैं। लेकिन आमिर के हाथ से ये मौका भी निकल गया क्योंकि सुभाष घई ने उन्हें बल्लू के रोल की बजाय राम का यानी पुलिस इंस्पेक्टर वाला रोल ऑफर किया था। बल्लू का रोल अनिल कपूर भी निभाना चाहते थे, लेकिन सुभाष घई, अनिल कपूर के अपनी इच्छा जताने से पहले ही ये रोल संजय दत्त को दे चुके थे। संजय दत्त का फिल्म 'खलनायक' का हिस्सा होना ही सुभाष घई के लिए कास्टिंग के मामले में बड़ी जीत थी। घई इससे पहले 1982 में रिलीज हुई फिल्म 'विधाता' में साथ काम कर चुके थे। फिल्म 'खलनायक' की कास्ट आखिरकार संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित के साथ फाइनल हुई। ये वह वक्त था जब संजय दत्त बहुत तनाव भरे जीवन से गुजर रहे थे। माधुरी दीक्षित इस फिल्म से पहले भी संजय दत्त के साथ काम कर चुकी थीं, लेकिन फिल्म 'खलनायक' की शूटिंग के दौरान ही उन्हें समझ आ गया कि ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट होने जा रही है। हां, मैं हूं खलनायक स्लोगन और हाथों में हथकड़ी लगाए संजय दत्त के पोस्टर गली-गली लग चुके थे। यह वो दौर था जब मुंबई ब्लास्ट मामले में संजय से पूछताछ पर पूछताछ चल रही थीं। दत्त परिवार एक बड़े भंवर में फंसता जा रहा था। ऐसे में उन्हें सुभाष घई का यह तरीका जरा भी पसंद नहीं आया कि संजय की फिल्म 'खलनायक' का इस तरह से प्रचार किया जाए। इसमें साफ तौर पर अवसरवादिता नजर आ रही थी, लेकिन सुभाष घई का इस मामले में इतना ही कहना था कि फिल्म के प्रमोशन की रणनीति बहुत पहले ही बनाई जा चुकी थी। इसलिए यह कहना कि संजय की मौजूदा हालत को कैश करने के लिए इस तरह का प्रमोशन हो रहा है तो यह गलत था। खैर कुछ भी संजू बाबा की जिंदगी संघर्षपूर्ण रही है। ●

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय
9897450817, 9897791284
ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ
अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं
निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)

मेष-

इस माह प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना करेगा। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। जीवनसाथी के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। आपका प्रिय आपसे वादे की मांग करेगा, लेकिन ऐसा वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें। अगर आपको एक दिन की छुट्टी पर जाना है तो चिंता न करें, आपकी गैरहाजिरी में सभी काम ठीक से चलते रहेंगे। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और लाभकारी समय की ओर ले जाएंगे। अपने साथी पर किया गया संदेह एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है। उपाय: किसी नेत्रहिन की मदद करे कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

वृषभ:-

इस माह आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आपका ज्यादातर समय दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। प्यार का भरपूर लुत्फ मिल सकता है। कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करें। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं, तो हालात बेहतर होते हुए महसूस करेंगे। उपाय: हरे तोते व तोती के जोड़े को आजाद कराए कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

मिथुन:-

इस माह किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मन खुश करेगी। ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया समय है, जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। आपका घर मेहमानों से भर सकता है जो आपको खुशियां देगा। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाओं का आइडिया देगा। अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोचने का समय आ गया है। क्या आपको पता है कि आपका जीवनसाथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है। उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद-ब-खुद नजर आएगी। उपाय: बट वृक्ष पर जल चढ़ा कर चार परिक्रमा लेकर मिट्टी का टीका लगाएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

कर्क:-

इस माह दूसरों के सफलता की सराहना कर आप सहानुभूति का लुत्फ ले सकते हैं। आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। परिवार के लिए किसी अच्छे और ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए समझ-बूझकर थोड़ा खतरा उठाया जा सकता है। एक तरफा प्यार आपके लिए काफी खतरनाक साबित होगा। आपके काम की गुणवत्ता देखकर आपके वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। जरूरत के वक्त आपका जीवनसाथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। उपाय: गाय को हरा चार खिलाने से कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 1

सिंह:-

इस माह आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। जेवर और एंटीक सामान में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जो आपको राहत दे सकती है। आपका रुमानी संबंध आज थोड़ी परेशानी में पड़ सकता है। दफ्तर में आप तारीफ पाएंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, जिसे आप सुनना चाहते थे। जरूरत के वक्त आपका जीवनसाथी आपके परिवार को तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। उपाय: गाय को आलू पर हल्दी लगाकर खिलाए कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

कन्या:-

नियमित व्यायाम करने से वजन नियंत्रित रहेगा। अतिरिक्त धन को रिअल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। घर पर मेहमानों का आना बढ़िया और खुशगवार वातावरण बना देगा। सावधान रहें, कोई आपसे दिल्लगी या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिस कार्य का चयन करेंगे उससे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। जीवनसाथी की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। उपाय: काले सफेद कुत्ते को दूध व रोटी खिलाएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 7

तुला:-

इस माह कुछ बदलाव आपके रूप-रंग को आकर्षक बनाएगा। बैंक से जुड़े लेन-देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोशिश करें की कोई आपकी बातों या काम से आहत न हो और पारिवारिक जरूरतों को समझें। नये रोमांस की संभावना प्रबल है, प्रेम का फूल आपकी जिंदगी में जल्दी ही खिल सकता है। नए ग्राहकों से बात करने के लिए बेहतरीन समय है। अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उनके खोने या चोरी होने की संभावना है। आप और आपका जीवनसाथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे। उपाय: मंगल शांति मंत्र 21 बार सुबह शाम जपे कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

वृश्चिक:-

प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। एक बार ये गुण आपके अंदर रच-बस जाएं, तो हर हालात में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर आएंगे। आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। जिंदादिल और गर्मजोशी पूर्ण व्यवहार आपके आस-पास के लोगों को खुश कर देगा। आपके प्यार के बीच कोई आ सकता है। लंबे समय से लटके कार्य जल्द पूर्ण होंगे। उपाय: घर से निकलते हुए इत्र लगाएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 2

धनु:-

इस माह सेहत में गड़बड़ी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो आपके हालात और जरूरतों को समझते हैं। रोमांटिक मुलाकात बहुत रोमांचक रहेगी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं होगी। आने वाले कुछ दिनों में बहुत से अच्छे मौके आपको मिलेंगे। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। अपने जीवनसाथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदा हो सकते हैं। उपाय: केले के पेड़ की पूजा करे कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

मकर:-

इस माह अपने काम पर एकाग्रता रखने में परेशानी महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाये कुछ ऐसा करें जो आपकी कमाई में इजाफा कर सके। आप अपने साथी के नजरिए को नजर अंदाज करेंगे, तो वह अपना आपा खो सकता है। अपने प्रिय की ईमानदारी पर शक न करें। आप जीतोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे। अपने जीवनसाथी की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसान कर सकते हैं। उपाय: जल प्रधान वस्तुओं का सेवन करें (नारियल पानी, पपीता, खीरा आदि) कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

कुंभ:-

इस माह खुद को उत्साही बनाए रखने के लिए अपनी कल्पनाओं में कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर बनाएं। परिवार की मदद से आर्थिक तौर पर फायदा होगा। परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेंगी। अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज़ देखने को मिल सकता है। आप यात्रा कर रहें है तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। इस माह जीवनसाथी के साथ की एहमियत महसूस करेंगे। उपाय: बैडरूम में कृस्टिल बॉल लगाने से कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

मीन:-

इस माह आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसने-हंसाने की शैली है, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करके देखें। पैसा अचानक आपके पास अएगा, जो अपके खर्च को संभाल लेगा। दोस्तों के साथ घूमें-फिरें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेम के नजरिए से यह माह आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में हालात आपके पक्ष में रहेंगे। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से यह माह शानदार रहेगा। उपाय: दही घी मिश्री कपूर दूध धर्मस्थल पर दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 5

nupur.com NRITYA

नुपुर नृत्य कला केंद्र
हल्द्वानी

में सभी के लिए
01 फरवरी 2021 से पुनः
कक्षाएं आरंभ
हो गई है।

जिसमें क्लॉसिकल डांस, तबला वादन, सेमी क्लासिकल, गिटार, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हुए तथा कक्षों (क्लास) को नियमित रूप से सेनेटाइज कर आधुनिक तरीके से देने की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है ।

एडमिशन के लिए संपर्क करें।

www.facebook.com/nupurnrityakalakendra
You Tube: Search: nupurnrityakalakendra
nupurnritya99@gmail.com
www.nupurnritya.com
NEAR KANDPAL ENT. Hospital, SHAKTI SADAN GALI, NAWABI ROAD, HALDWANI (NAINITAL), Uttarakahnd
05946 220841, 91 9760590897
91 9411161794